RNI No. DELHIN/2022/85477 | पेज - 32

पढ़ने
और
शेयर
के लिए करें
स्कैन

विज्ञापन और प्रसार
के लिए करें संपर्क
contactblitzindia@gmail.com
9205992246, 9205992248

नई दिल्ली, 7 सितंबर - 20 सितंबर, 2026

विकास की पत्रकारिता का अग्रदूत

ब्लिट्ज इंडिया

वर्ष : 4, अंक : 46 https://hindi.blitzindiamedia.com/ ₹30/-

भारत का बढ़ा रुतबा
प्रधान संपादक की कलम से
दीपक द्विवेदी 2

अब भारत बनाएगा
खुद का मोबाइल ब्रांड 14

इसरो ने भेजा धरती का
'पहरेदार' 31

पीएम मोदी का विदेश दौरा और एससीओ शिखर सम्मेलन का संदेश...

भारत विश्व-मित्र महाशक्ति

मध्य एशिया में भारत की कूटनीतिक विजय, वैश्विक राजनीति को नया मोड़

विनोद शील

नई दिल्ली। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय कूटनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई विशेष द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और शांति की बहाली पर विशेष जोर दिया गया।

वहीं, मंच पर पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी त्रिपक्षीय तस्वीरें और संवाद दुनिया भर के मीडिया में छाए रहे, जिससे यह संदेश गया कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र और संतुलित कूटनीति के साथ मजबूती से खड़ा है। इसके विपरीत, इस कूटनीतिक हलचल और भारत-रूस-चीन के बीच सहज संपर्कों के मध्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की असहज स्थिति और कूटनीतिक हाशिए पर जाने के दृश्य ने पड़ोसी देशों—विशेषकर चीन और पाकिस्तान की क्षेत्रीय रणनीतियों पर गहरा असर डाला है।

इस यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन से भारत ने साबित कर दिया है कि वह एक ऐसी 'विश्व-मित्र' महाशक्ति है, जो पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध (क्वाड के जरिए) रखते हुए भी यूरेशिया में रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को पूरी ताकत से निभा सकती है। इससे चीन-पाकिस्तान के उस कूटनीतिक घेरे को तोड़ा गया है जो वे भारत के खिलाफ मध्य एशिया में बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अत: यह कह सकते हैं कि बिश्केक में हुए 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन से वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय कूटनीति को एक नई दिशा मिलने का संदेश मिला है।

पीएम मोदी इन दोनों देशों की चार दिवसीय यात्रा से गत 1 सितंबर को लौट चुके हैं पर वह कई समझौतों के जरिये भारत को भविष्य की चुनौतियों के वास्ते तैयार करने के लिए बहुत कुछ अपने साथ लेकर आए हैं।

पीएम मोदी की इस पूरी यात्रा के दौरान भारत का दबदबा कैसे बढ़ा; और चीन तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर इसका क्या कूटनीतिक असर रहा, इसे नीचे दिए इन तथ्यों से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात

आधिकारिक तौर पर एससीओ की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित 26वें शिखर सम्मेलन से अलग अला-अरचा स्टेट रेजिडेंस में दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता रणनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रही।

अंतहीन युद्ध का अंत संदेश : यूक्रेन संकट पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने शांति का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि दुनिया को अंतहीन युद्ध (एंडलेस वॉर) से हटकर युद्ध के अंत (एंड ऑफ वॉर) की तरफ बढ़ना होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि युद्ध में बीता हर एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है।

व्यापार और रक्षा साझेदारी : दोनों नेताओं ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा ऊर्जा, निवेश, व्यापार और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर मजबूत सहमति बनी।

- शेष पेज 31 पर

उज्बेकिस्तान-भारत के बीच यूरेनियम समेत हुए 11 समझौते : पेज 16-17

ब्लिट्ज ब्यूरो

'झूठ की गूंज वाले निराशा फैलाने में लगे हैं'

जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आने के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ को एक असाधारण उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के लोगों की सामूहिक ताकत और मुश्किलों से उबरने की क्षमता को दर्शाती है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। 7.8% जीडीपी ग्रोथ से देश खुशियों से भर गया है। मैं देशवासियों को उनकी संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है।

नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला

पीएम मोदी ने कहा, दुनिया युद्ध में डूबी हुई है और चारों तरफ से युद्ध की खबरें आ रही हैं। विश्व संकटों से घिरा हुआ है और सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित है। 2020 के कोविड काल से लेकर अब तक इसी तरह की खबरें हैं। उसके बाद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग झूठी गूंज वाले; झूठ बोलकर चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। तमाम बाधाओं को पार कर हमने 7.8 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है।

स्वदेशी पर दिया जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें इस गति को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र याद रखें, 'वोकल फॉर लोकल' पर ध्यान देते हुए विदेशों की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। शादी विदेश में नहीं करनी चाहिए। 'मेड इन इंडिया' के मंत्र को जीना चाहिए। जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना ज्यादा आत्मनिर्भरता पर बल देंगे, मुझे पक्का यकीन है कि जब आजादी के 100 साल होंगे, हम अपनी युवा पीढ़ी को विकसित भारत से पुरस्कृत करेंगे।

पीएम ने कहा, हमारी नीति सही है, नीयत सही है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति देश को एकजुट होकर नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।

भारत का बढ़ा रुतबा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिवसीय यात्रा (29 अगस्त से 1 सितंबर, 2026) और बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने वैश्विक मंच पर भारत के रणनीतिक व कूटनीतिक रुतबे को एक नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा के पहले चरण में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया। इसके बाद बिश्केक (किर्गिस्तान) में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य एशिया उसके लिए केवल कूटनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि विस्तारित पड़ोस का एक अहम हिस्सा है और इसी वजह से मध्य एशिया में भारत का रणनीतिक प्रभाव उल्लेखनीय ढंग से बढ़ता दिख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह मध्य एशियाई कूटनीति; भारत की 'कनेक्टिविटी, एनर्जी और सिक्योरिटी' (सुरक्षा और ऊर्जा) की प्राथमिकताओं को पुख्ता करती है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाने पर सहमति बनी है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुए 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन ने भारत को मध्य एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत करने का एक बड़ा मंच प्रदान किया। भारत के लिए यह क्षेत्र आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि आतंकवाद के पोषकों को माफ नहीं किया जा सकता और आतंकवाद सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के पूरे तंत्र को मिलकर नेस्तनाबूद करने का आह्वान किया। उन्होंने दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह न होने की बात कहकर सीमा पार आतंकवाद फैलाने वाली ताकतों को कड़ा संदेश दिया।

दीपक द्विवेदी

प्रधान संपादक की कलम से

रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ एक ही मंच पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता से रखना भारत के बढ़ते कूटनीतिक वजन का भी द्योतक है।

यही नहीं, बिश्केक के मंच पर भारत, रूस, चीन और ईरान जैसी वैश्विक और क्षेत्रीय महाशक्तियां एक ही छत के नीचे मौजूद थीं। बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात और बातचीत ने वैश्विक राजनीति का ध्यान भी खींचा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संघर्ष पर भारत के शांतिपूर्ण रुख को दोहराते हुए कहा कि बातचीत और कूटनीति से ही समाधान संभव है और 'एंडलेस वॉर' के स्थान पर 'एंड ऑफ वॉर की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि इसी में मानवता की भलाई निहित है। शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मंच पर हुई संक्षिप्त बातचीत ने यह संकेत दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कायम है। बिश्केक घोषणापत्र के जरिए यूरेशियाई देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग का भी संदेश दिया।

शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि संकट के दौर में भारत संवाद और कूटनीति के पक्ष में है। इस बैठक से यह संदेश गया कि भारत, ईरान और पश्चिम एशिया के साथ अपने ऐतिहासिक एवं ऊर्जा आधारित संबंधों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारत को क्या मिला

इन यात्राओं और बैठकों से भारत को स्पष्ट रूप से अनेक कूटनीतिक लाभ मिले हैं। जहां भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल रहा है वहीं भारत ने पश्चिमी देशों और अन्य महाशक्तियों के बीच बिना झुके अपनी स्वतंत्र नीति का लोहा मनवाया है। एक तरफ जहां चीन के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर संतुलित संवाद बनाए रखा गया, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया गया। इसके अतिरिक्त एससीओ के मंच पर भारत की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक फैसले अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं हैं और भारत बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है। इससे यह साबित हुआ कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। साथ ही रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ एक ही मंच पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता से रखना भारत के बढ़ते कूटनीतिक वजन का भी द्योतक है।

तेजस एमके-2 फाइटर जेट पर पूर्व वाइस चीफ की दो टूक

'कब तक करेंगे इंतजार'

पूर्व वाइस एयर चीफ नागेश कपूर ने तेजस एमके-2 की समय सीमा और एचएएल की काम करने की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए भारत को नई रणनीति अपनाने की सलाह दी है।

भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी के बीच तेजस एमके-2 और स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम की समय सीमा को लेकर पूर्व वाइस एयर चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत को आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है और इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। कपूर ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की काम की रफ्तार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एचएएल जिस गति से काम कर रहा है, वह भारतीय वायुसेना की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। 2035 में चौथी पीढ़ी का विमान ठीक नहीं।

2035 में चौथी पीढ़ी के विमान का कोई लाभ नहीं, चीन छठी पीढ़ी की ओर बढ़ चुका है।

जब कपूर से पूछा गया कि अगर तेजस एमके-2, 2030 के दशक के मध्य में बड़ी संख्या में वायुसेना में शामिल होता है तो क्या उस समय चौथी पीढ़ी के विमान पर निर्भर रहना सही होगा जबकि चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दिशा में आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान पांचवीं पीढ़ी के विमान पर विचार कर रहा है? इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं होगा। भारत के पास फिलहाल पांचवीं या छठी पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। वहीं चीन पांचवीं पीढ़ी के जे-20 विमानों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है।

पूर्व वाइस एयर चीफ नागेश कपूर

विकसित भारत के लिए युवाओं का नशामुक्त होना जरूरी

137वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा- छोटा सा शौक बड़ी संभावनाओं के द्वार खोल सकता है

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में सबसे पहले भारतीय इतिहास को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने युवाओं को इतिहास के ज्ञान को आसानी से प्राप्त करने के लिए WWW.BHARATRAJYA.COM वेबसाइट पर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर कोई भी एक साल चुनें और आपको पता चल जाएगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसने शासन किया था।

इस वेबसाइट को मुंबई के कृष्णा शेषाद्रि ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृष्णा शेषाद्रि की यह कोशिश न सिर्फ इतिहास के छात्रों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि इससे हमें इतिहास को दिलचस्प तरीके से सीखने में भी मदद मिलेगी।

ड्रग फ्री इंडिया

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत', अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिलकुल साफ है- नशामुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत से लोग, खासकर युवा, इसका बड़ा हिस्सा बन गए हैं। यह भारत के युवाओं की सेहत, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा सामूहिक संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे हजारों युवा नशे के चंगुल में फंस रहे हैं जिसके चलते उनके परिवार को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमें युवाओं को संभालना होगा।

लाखों माताओं-बहनों को 'पीएम स्वनिधि योजना' से नई ताकत मिल रही है

'महिला सशक्तिकरण' के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। 'पीएम स्वनिधि योजना' के लाभार्थियों में करीब 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। यानी देशभर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।

मिशन शक्तिसैट की चर्चा

पीएम मोदी ने कहा कि मिशन शक्तिसैट के माध्यम से 108 देशों की 12 हजार छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली।

छोटा सा शौक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है

> 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई

पीएम मोदी ने कहा कि कभी-कभी हमारा एक छोटा सा शौक, जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नगालैंड की वेसालु पुरो जी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वेसालु जी किसान परिवार में पली-बढ़ीं। बचपन से उन्होंने अपने माता-पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था।

साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे-धीरे उनको इसमें संभावना दिखाई देने लगी और उन्होंने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।

स्वच्छता अभियान चरित्र को बदल देता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब स्वच्छता हर नागरिक की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बन जाती है, तो इसका असर केवल आस-पास की सफाई तक ही सीमित नहीं रहता, यह पूरी जगह की पहचान और चरित्र को बदल देता है।

पीएम ने कहा कि 'मन की बात' नए प्रयास सामने लाने का मंच

पीएम ने कहा कि इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और 'सूर्यपथ तिरंगा' के जरिए फिजी से लेकर दुनिया भर में तिरंगा शान से फहराया गया। फिजी के सुवा में सूर्य की पहली किरणों के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद, तिरंगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशनों और चौकियों पर लहराता रहा।

एवाकाडो की मांग तेजी से बढ़ रही है

उन्होंने आगे कहा कि कहा कि देश में एवाकाडो की मांग तेजी से बढ़ रही है और किसान इसकी खेती से शानदार कमाई कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कडपा में किसान वरदराज ने 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर स्थानीय बाजार में सप्लाई किया।

गंगा घाट की सफाई

पीएम मोदी ने यूपी के रामपुर स्थित पटवाई गांव के आकाश और रोहन का उदाहरण दिया, जिन्होंने 'क्लीन-अप पटवाई' टीम बनाकर युवाओं के साथ मिलकर चार गंगा घाटों की सफाई की, कई तालाब संवारे और एक टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटाया।

अभिनेता उत्तम कुमार को याद किया

पीएम मोदी ने कहा कि 3 सितंबर को महान अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म-शताब्दी दिन है। उन्होंने याद किया कि सत्यजीत रे ने फिल्म 'नायक' की स्क्रिप्ट उत्तम कुमार को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। पीएम ने कहा कि शुरुआती असफलताओं के बावजूद उत्तम कुमार ने कभी हार नहीं मानी।

वंदे मातरम

पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना देशभक्ति के रंगों से भरा रहता है। 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने से यह साल और खास हो गया है।

आईसीएमआर की तीन जांच तकनीकें उद्योग के लिए होंगी हस्तांतरित

ब्लिट्ज रिसर्च

नई दिल्ली। भारतीय विज्ञान का सबसे कठिन हिस्सा प्रयोगशाला नहीं है। सबसे कठिन हिस्सा वे बीस मीटर हैं जो एक काम करते नमूने और उसे बनाने को तैयार किसी कंपनी के बीच पड़ते हैं। इस हफ्ते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सूचना पट पर टंगे तीन नोटिस वही बीस मीटर हैं। तीनों तकनीक हस्तांतरण (ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी) के लिए रुचि पत्र मांगते हैं जिसकी आख़िरी तारीख 4 सितंबर 2026 थी। तीनों जांच तकनीकें उद्योग के लिए हस्तांतरित की जाएंगी।

क्या दिया जा रहा है

पहला है डेंगू की जांच का ड्यूल-ट्यूब वन-स्टेप आरटी मल्टीप्लेक्स पीसीआर एसे। डेंगू चार अलग-अलग प्रकारों (सीरोटाइप) से होता है, और मरीज को कौन सा है, यह जानना ज़रूरी होता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब है एक ही प्रतिक्रिया में एक से ज़्यादा चीज़ें खोजना। वन-स्टेप आरटी का मतलब है कि वायरस के आरएनए को डीएनए में बदलने और फिर उसे बढ़ाने का काम एक ही बंद ट्यूब में हो जाता है— ज़िला स्तर की प्रयोगशाला में यह आधी मेहनत और आधा जोखिम का काम है।

दूसरा है पेट के दो परजीवियों में फर्क बताने वाला मल्टीप्लेक्स क्यूपीसीआर किट — जिआर्डिया लैंब्लिया और एंटअमीबा। दोनों से दस्त होता है, दोनों की दवा अलग है, और अब तक दोनों की पहचान माइक्रोस्कोप से होती रही है। डीएनए से पहचान करने वाला किट अनुमान को नतीजे में बदल देता है।

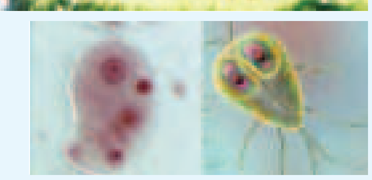

तीसरा है आपस में जुड़े ख़ानों वाली कोशिका संवर्धन प्लेट (सेल कल्चर प्लेट)। साधारण प्लेट में हर ख़ाना अलग रहता है। ख़ाने आपस में जुड़ जाएं तो एक कोशिका समूह दूसरे को प्रभावित कर सकता है — यहीं से किसी अंग का नमूना बनाना शुरू होता है।

यह प्रयोगशाला का वह उपकरण है जो भारत आमतौर पर आयात करता है।

प्रयोगशाला से कारख़ाने तक की स्थिति

यह भाग प्रायः छूट जाता है, इसलिए साफ़ लिखना जरूरी है। तकनीक हस्तांतरण का निमंत्रण तब निकलता है जब आविष्कार इतना पूरा हो कि कोई और उसे बना सके, और इतना पूरा न हो कि वह उत्पाद हो। बौद्धिक संपदा परिषद के पास रहती है; निर्माण, नियामक फाइल और वितरण नहीं। दोनों जांच किटों के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंज़ूरी अलग से लेनी होगी, और वह इस हस्तांतरण का हिस्सा नहीं है। परिषद इसके लिए पेटेंट मित्र नाम का अलग रास्ता चलाती है।

यानी सही स्थिति यह है कि तीन भारतीय आविष्कार बनने के लिए तैयार हैं, और वे बनेंगे या नहीं, यह इस पर टिका है कि शकोई भारतीय कंपनी जवाब देती है या नहीं।

उसी काम का दूसरा आधा हिस्सा

परिषद के दो और खुले प्रस्ताव इसी कहानी के हैं। मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशालाएं (वीआरडीएल) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, आख़िरी तारीख़ 30 सितंबर 2026; और पूर्वोत्तर राज्यों में तकनीकी संसाधन केंद्रों के लिए रुचि पत्र, आख़िरी तारीख़ 15 सितंबर। जांच किट उतनी ही काम की होती है जितनी उसे चलाने वाली प्रयोगशाला। किट बनवाना और प्रयोगशालाओं का जाल फैलाना — ये एक ही काम के दो आधे हिस्से हैं।

भारत और भारतवासी को क्या मिलता है। डेंगू और परजीवी की जो जांच आज आयातित किट पर होती है, वह विदेशी मुद्रा का भुगतान भी है और किसी और के हाथ की आपूर्ति श्रंखला भी। भारत में बनी, भारत में डिजाइन की गई आणविक जांच दोनों की जगह लेती है, और आगे चलकर उन्हीं देशों को जाती है जहां भारत पहले से दवा भेजता है। मरीज़ के लिए फायदा और सीधा है — राय के बजाय नाम, और पहली ही बार सही दवा।

सीएम योगी ने चला 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक

'यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026' में 3,195 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया

संजय द्विवेदी

लखनऊ। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को देश के विकास में एक 'बाधा' और 'बीमारू' राज्य के रूप में देखा जाता था, जहां कानून-व्यवस्था की बदहाली के कारण उद्यमी और निवेशक आने से कतराते थे लेकिन पिछले नौ वर्षों में इस बीमारू दंश को पूरी तरह मिटाकर, उत्तर प्रदेश आज देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत के विकास का असली 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण नई दिल्ली में आयोजित यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026' में देखने को मिला। यह आयोजन केवल एक साधारण बिजनेस मीट नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक और औद्योगिक विजन के मास्टरस्ट्रोक का सजीव प्रदर्शन था।

इस बिजनेस मीट में जहां एक ओर केंद्रीय मंत्रियों और जापानी प्रतिनिधियों ने यूपी की कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सक्रियता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लोहा माना। वहीं, दूसरी ओर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जमीन पर हजारों करोड़ रुपये का जापानी निवेश उतारा गया। यह ऐतिहासिक साझेदारी सिद्ध करती है कि कैसे योगी सरकार की प्रगतिशील नीतियां यूपी को 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब' बनाकर पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को समय से पहले सिद्ध

करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

इस ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी और जापान के बीच के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक जुड़ाव को बेहद गहरे और स्पष्ट अंदाज में परिभाषित किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, जहां जापान 'लैंड ऑफ द राइजिंग सन' है तो वहीं उत्तर प्रदेश 'लैंड ऑफ सूर्यवंश' होने के साथ-साथ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की पावन धरती है, जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जापान के पास जहां दशकों का बेहतरीन औद्योगिक अनुभव, सटीकता, गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता और मैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता की 'काइजेन' फिलॉसफी है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास विशाल युवा शक्ति, कौशल, बड़ा उपभोक्ता बाजार, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शी नीतिगत ढांचा उपलब्ध है।

सीएम योगी ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश को अपना 'सेकेंड इंडस्ट्रियल होम' बनाने का खुला न्योता दिया है। उन्होंने जापानी बिजनेस लीडर्स से आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश में केवल फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि यहां विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट संस्थान और ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें।

- जापानी कंपनियां यूपी को अपना 'सेकेंड इंडस्ट्रियल होम' बनाएं
- बसेगी जापानी सिटी, 500 एकड़ में होगा हाईटेक विकास
- इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप से होगी रोजगार की बरसात
- उत्तर प्रदेश बना भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

उल्लेखनीय है कि यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया गया। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपतियों सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं ने हिस्सा लिया। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 में जापानी कंपनियों के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रस्तुत किए गए।

यीडा में साल के अंत तक बसेगी जापानी सिटी, 500 एकड़ में होगा हाईटेक विकास; 60% भूमि अधिग्रहण पूरा।

यीडा में रोजगार सृजन

इस इन्वेस्टमेंट मीट का सबसे बड़ा व्यावहारिक 'मास्टरस्ट्रोक' ₹3,195 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश रहा, जिसके तहत यीडा क्षेत्र में दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। इन परियोजनाओं के स्थापित होने से उत्तर प्रदेश के कुशल युवाओं के लिए 10 हजार से अधिक रोजगार पैदा होंगे। ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण बनाने वाली वैश्विक जापानी दिग्गज कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड यीडा के सेक्टर-10 में ₹2,029 करोड़ का निवेश कर रही है। यहां प्रतिवर्ष 60 हजार ट्रैक्टर और 15 हजार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का उत्पादन किया जाएगा जिससे 3,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

योगी सरकार का तोहफा, 50 हजार छात्राओं को देगी स्कूटी

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एलान किया है। यूपी सरकार प्रदेश की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम ने ये एलान किया है।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार की हर एक योजना बेटियों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। 2017 के पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी। पहले कहा जाता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्रदेश में बेटियों का सम्मान, शिक्षा और भविष्य सुरक्षित नहीं था। प्रदेश में उत्सव के पहले दंगे हो जाते थे।

हर तरफ अव्यवस्था और अराजकता का माहौल था। हम उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पर जब मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो अराजकता को उत्सव बना दिया गया है। सरकार की हर योजना का केंद्र बेटी है। पहले तो हर योजना में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी होती थी। अब बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम में कोई एक जगह मिलेगी। पहले बेटियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी पर अब सिस्टम और तकनीक पर आधारित है।

60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए आजीवन निःशुल्क बस यात्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ रोजाना करीब 88438 महिला यात्रियों को मिलने का अनुमान है। योजना के तहत निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पात्र महिला यात्रियों की पहचान और निशुल्क यात्रा की व्यवस्था को सुगम बनाया जा सकेगा। सीएम ने कहा, माता अहिल्याबाई साहस और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। इसलिए इस योजना का नाम 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना नाम दिया है।

आधुनिक होगा दिल्ली चिड़ियाघर

टूरिस्टों के लिए कैफेटेरिया, नया एंट्री गेट और पार्किंग सुविधा जल्द

ब्लिट्ज ब्यूरो

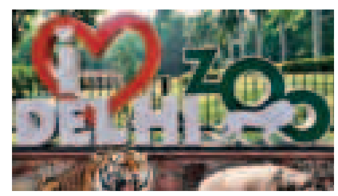

नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर के प्रवेश क्षेत्र को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रवेश क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए करीब 58 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। इसके तहत नया वाहन उतारने का क्षेत्र, सतही पार्किंग, प्रवेश द्वार, पैदल पारपथ, आगंतुक केंद्र और खुले परिसर में कैफेटेरिया बनाया जाएगा। प्रवेश क्षेत्र के बाहरी हिस्से में हरियाली और नए मार्ग भी विकसित किए जाएंगे।

यह परियोजना चिड़ियाघर के करीब 400 करोड़ रुपये के व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। पूरे चिड़ियाघर को चार वर्ष में अलग-अलग चरणों में विकसित करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाना और आगंतुकों के अनुभव को सुविधाजनक करना है।

हिमाचल में अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम

ब्लिट्ज ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में दाखिले से जुड़ी व्यवस्था में अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और हीन भावना से बचाना है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को समाप्त करने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूल के सामान्य दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाया जाएगा, लेकिन सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आवश्यकतानुसार अपनी जाति की जानकारी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी पात्र व्यक्ति को अनुसूचित

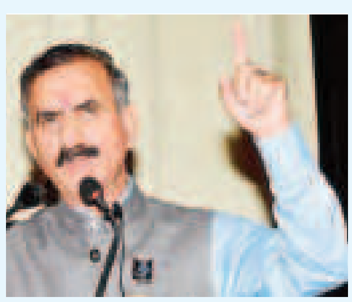

जाति के लिए उपलब्ध योजनाओं के लाभ से वंचित करना नहीं है। बच्चों के स्तर पर जातिगत पहचान के कारण पैदा होने वाली हीन भावना को कम करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।

अनुसूचित जाति के कल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के तहत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अति निर्धन परिवारों के लिए भी योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने तथा परिवार की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान प्रस्तावित है।

महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के काम ने पकड़ी रफ्तार

ठाणे में जमीन से 12 मीटर ऊपर होगा स्टेशन कॉन्कोर्स

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। ठाणे और पालघर के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस काम की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, ठाणे जिले के शिलफाटा से महाराष्ट्र-गुजरात सीमा के जरोली गांव तक 135.45 किमी लंबे एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण किया जा रहा है। इस सेक्शन में 124.027 किमी लंबा वायाडक्ट और पुल शामिल हैं। महाराष्ट्र में ठाणे, विरार और बोईसर तीन एलिवेटेड बुलेट ट्रेन स्टेशनों का निर्माण हो रहा है।

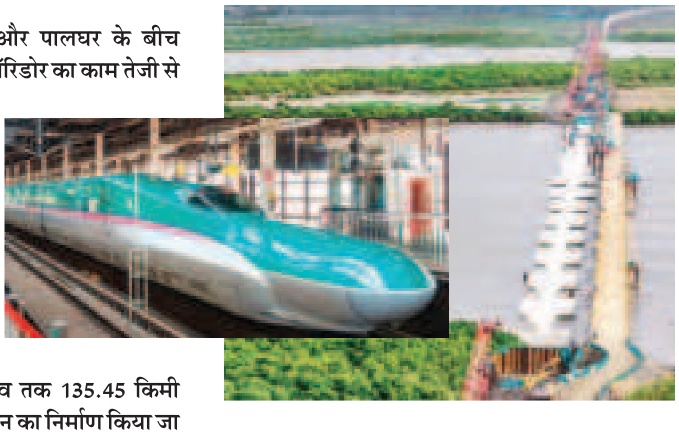

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील ठाणे स्टेशन को मैंग्रोव क्षेत्र को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका कॉन्कोर्स जमीन से करीब 12 मीटर ऊंचा होगा।

ठाणे में बुलेट ट्रेन के काम की स्थिति

74 किमी का हिस्सा गर्डर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका है। इस सेक्शन में 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पियर का निर्माण चल रहा है। करीब 74 किलोमीटर लंबाई में पियर वायाडक्ट गर्डर लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुके हैं। निर्माण कार्य को गति देने के लिए महाराष्ट्र में 9 कास्टिंग यार्ड, 7 फुल-स्पैन लॉन्चिंग गैन्ट्री और 8 एसबीएस लॉन्चिंग गैन्ट्री काम कर रही हैं।

वैतरण नदी पर तेजी से आगे बढ़ रहा काम

3 पहाड़ी टनल का ब्रेकथ्रू पूरा हो चुका। ताजा अपडेट में बताया गया है कि इस सेक्शन में 7 पहाड़ी टनल बनाई जा रही हैं। इनमें 3 में ब्रेकथ्रू हो चुका है। अब इनमें ड्रेनेज, वॉटरप्रूफिंग और लाइनिंग का काम चल रहा है। उल्हास नदी पर 460 मीटर, वैतरणा नदी पर 2.32 किमी और जगनी नदी पर 510 मीटर लंबे पुल बनाए जा रहे हैं। पूरे सेक्शन में 36 पुल और क्रॉसिंग होंगे, जिनमें 12 स्टील ब्रिज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम काफी उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले साल 15 अगस्त को बुलेट ट्रेन के संचालन की तारीख तय की है। हाल ही में जापान से बुलेट ट्रेन के ड्राइवर प्रशिक्षण पूरा करके लौटे हैं। इस साल के आखिर तक ट्रायल को लेकर गतिविधियां आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

गूगल गुजरात के युवाओं को कुशल बनाने में सहयोग देगा

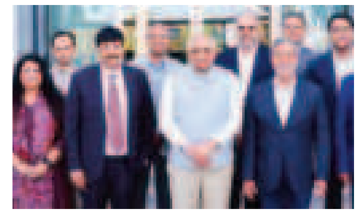

अहमदाबाद। अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गूगल और माइक्रोन के ऑफिस का विजिट किया। तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की 'द इंडस एंटरप्रेन्योर्स' (टीआईई) के सदस्यों के साथ बैठक हुई। उन्होंने परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास के साथ आमने-सामने बैठक की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि गूगल युवाओं को कौशल सिखाने, शिक्षकों और छात्रों के लिए एआई ट्रेनिंग, फसल पैटर्न, मिट्टी और जलवायु डेटा में एआई के इस्तेमाल और डेटा सुरक्षा के मामलों में गुजरात के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में टीआईई ने कहा कि विभिन्न एआई टूल्स के जरिए हेल्थकेयर वर्करों की ट्रेनिंग और युवाओं को कौशल सिखाने के लिए गुजरात के साथ मिलकर काम करेगा। गुजरात में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए डेवलपर और परप्लेक्सिटी एआई के बीच हाइब्रिड सेटअप पर सार्थक चर्चा हुई। टीआईई की स्थापना 1992 में सफल उद्यमियों, कॉर्पोरेट अधिकारियों और सिंध क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पेशेवरों के समूह द्वारा की गई थी। विभिन्न एआई टूल्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्रों में गुजरात के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई।

ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ी का शक, पूरी भर्ती प्रक्रिया रद

परीक्षा से पहले कुछ उम्मीदवारों को मिले थे प्रश्न

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत ड्रग इंस्पेक्टर, ग्रुप-बी पदों के लिए चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद कर दिया है। यह फैसला 22 मार्च 2026 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में संभावित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद लिया गया है। एमपीएससी के मुताबिक, ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा महाराष्ट्र के छह डिविजनल मुख्यालयों पर ऑफलाइन आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 12 जून को जारी किया गया था। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 506 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से 488 उम्मीदवारों ने 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच

आयोजित इंटरव्यू में हिस्सा लिया था।

कई शिकायतें मिलीं

आयोग को 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा आयोजित होने से पहले ही प्रश्न पत्र या प्रश्नों की जानकारी मिल गई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एमपीएससी ने 27 जुलाई को मुंबई पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया और मामले की जांच का अनुरोध किया। इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपों की प्रारंभिक जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि कम से कम एक उम्मीदवार को परीक्षा से पहले प्रश्नों का सेट मिल गया था और उसने इसका फायदा उठाया।

जांच का निष्कर्ष

प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती की पूरी प्रक्रिया रद करने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आयोग के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को रद करने का फैसला उम्मीदवारों के भरोसे को बनाए रखने और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। अब ड्रग इंस्पेक्टर पदों के लिए नए सिरे से स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी।

दोबारा आवेदन और फीस की जरूरत नहीं

उन उम्मीदवारों को राहत दी गई है, जिन्होंने पहले ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया था। उन्हें नई स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

अडाणी एनर्जी को मिला ₹4700 करोड़ का नया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने महाराष्ट्र में एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हासिल किया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 4,700 करोड़ रुपये का है। प्रोजेक्ट का मकसद रिन्यूएबल एनर्जी को आगे पहुंचाना और 4,500 मेगावाट तक के पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है।

इस प्रोजेक्ट को टैरिफ-बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए दिया गया था, जिसमें एईएसएल सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। यह प्रोजेक्ट कर्नाटक से महाराष्ट्र के मुख्य लोड सेंटर्स तक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने और सतारा, पुणे और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पंप-स्टोरेज इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा।

नया प्रोजेक्ट मिलने की खबर से अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में तेजी दिख रही है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल 'सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड' के तहत बनाया जा रहा है और इसके 36 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। एईएसए के पोर्टफोलियो में 562 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनें और 9,000 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जुड़ जाएगी।

खुले तेल की बिक्री पर लगी एफडीए की रोक हटी

मुंबई। महाराष्ट्र में खुले तेल का बिजनेस करने वाले दुकानदारों के लिए अब राहत की खबर है। कुछ दिन पहले एफडीए (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) के फैसले से छोटे बिजनेस करने वाले की परेशानी ज्यादा हो गई थी। अब सरकार ने इस मामले में नया रास्ता निकालने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी एसओपी बनाने को कहा है, जिससे तेल में मिलावट भी रोकी जा सके और छोटे बिजनेस करने वाले का काम भी चलता रहे।

महाराष्ट्र एफडीए ने 20 अगस्त को खुले खाद्य तेल और फैट की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

खेती में एमपी की महिलाओं की नई उड़ान

प्रदेश में ड्रोन से उर्वरक छिड़ककर कमा रहीं लाखों रुपये

ब्लिट्ज ब्यूरो

भोपाल। जो महिलाएं पहली बार ड्रोन देखकर डर गईं , वही अब ड्रोन से खेतों में उर्वरक छिड़ककर 12 लाख रुपये तक कमा रही हैं। मांग इतनी है कि कुछ जगह किसान 10 दिनों तक प्रतीक्षा में रहते हैं। एप से बुकिंग हो रही है। अभी प्रदेश में उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के सीएसआर फंड से दीदियों को 89 ड्रोन दिए गए थे। सभी चल रहे हैं।

मांग बढ़ने पर राज्य आजीविका मिशन ड्रोन दीदी बटालियन बनाने जा रहा है। इसमें 700 से अधिक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा।

15 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण और कीटनाशकों का छिड़काव

केंद्र की ओर से विभिन्न राज्यों को वर्ष 2023-24 में 1094 ड्रोन निशुल्क दिए गए थे, जिनमें मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 89 ड्रोन मिले थे। इन महिलाओं को ड्रोन पायलट का 15 दिन का

■ 700 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बनाई जाएगी ड्रोन दीदी बटालियन

निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को पांच दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। योजना से सर्वाधिक आय अर्जित करने वाली चार महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ड्रोन में कोई खराबी नहीं आई है, पर बैटरी पुरानी होने से उनका बैकअप कम हो गया है। उनका कहना है कि एक एकड़ में उर्वरकों का छिड़काव करने में पांच से 15 मिनट तक लगते हैं। इनसे नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। कुछ किसान कीटनाशकों का छिड़काव भी करा रहे हैं।

ड्रोन भी उपलब्ध करवाएंगे

हम 700 से अधिक दीदियों को प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी बटालियन तैयार कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत उन्हें ड्रोन भी उपलब्ध कराएंगे। पहले चरण में 89 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए थे जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

-विनय निगम, सीईओ, मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

नौ लाख की आय

ड्रोन देखकर पहले तो डर लगा था, लेकिन अब तक 4,500 एकड़ में फसल पर छिड़काव कर चुके हैं। प्रति एकड़ 400 रुपये लेते हैं। अभी तक नौ लाख रुपये की आय हो चुकी है। ड्रोन के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन भी मिला था, जिससे ड्रोन और अन्य सामान लाने-ले जाने में सुविधा हो गई है।

-कविता चौहान, ड्रोन दीदी, हरसूद।

त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड से होगी 'चिकन नेक' की सुरक्षा

अमित शाह ने सुरक्षा बलों संग बनाई नई रणनीति

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे 'चिकन नेक' भी कहा जाता है, की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में सीमा निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने पर चर्चा हुई।

अधिकारियों के मुताबिक, बैठक में केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस व प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

सिलीगुड़ी दौरे के तीसरे और आखिरी दिन शहर के बाहरी इलाके सुकना में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि सिलीगुड़ी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के करीब है। साथ ही यह संकरा कॉरिडोर पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख जमीनी संपर्क है।

अमित शाह ने क्या कहा

बैठक से पूर्व अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एसएसबी के एक कार्यक्रम में कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आठ राज्यों को जोड़ने वाले सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 'चिकन नेक' क्षेत्र के आसपास तीन नए सैन्य ठिकानों वाला एक त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। ये सैन्य ठिकाने असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में होंगे।

असम के सीएम ने केंद्रीय मंत्री से की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों पर चर्चा

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण ऊर्जा और शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में असम की दीर्घकालिक बिजली जरूरतों और केंद्रीय बिजली उत्पादन केंद्रों से राज्य को मिलने वाली बिजली के आवंटन को अधिक तर्कसंगत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। गुवाहाटी में भूमिगत केबल के जरिए बिजली वितरण व्यवस्था और प्राकृतिक गैस के बेहतर उपयोग तथा गैस आधारित बिजली उत्पादन के लिए इसकी कीमत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अर्बन चैलेंज फंड के तहत असम सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।

असम में बाढ़ से उजड़े परिवारों को मिलेंगे 3.8 लाख घर

केंद्र सरकार ने दी ₹5,000 करोड़ की मंजूरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी आवासीय मदद का एलान किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान, किसानों की समस्याओं और ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.8 लाख नए घरों के निर्माण के लिए करीब ₹5,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में असम के लोगों के साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए करीब ₹5,000 करोड़ के घरों को मंजूरी दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र परिवार योजना से बाहर न रह जाए, सर्वेक्षण की अवधि भी 15 दिन बढ़ा दी गई है।

चाय बागान श्रमिकों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

असम के चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की तैयारी है। सरकार के मुताबिक, चाय बागान श्रमिकों के पात्र परिवारों को जमीन का पट्टा मिलने के बाद डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए योजना का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने 3.8 लाख नए घरों के लिए मंजूरी का दस्तावेज उन्हें सौंपा, जिसमें करीब ₹5,000 करोड़ का निवेश शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि असम के चाय बागान क्षेत्रों में आवास के लिए केंद्र की ओर से अतिरिक्त सहायता का भरोसा दिया गया है।

किसानों के लिए भी करोड़ों रुपये की मंजूरी

बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मंजूर की है। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ₹832.70 करोड़ की कार्ययोजनाओं, कृषि मशीनीकरण के लिए ₹33.36 करोड़ और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत ₹96.87 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

बाढ़ के बाद घर और खेती, दोनों को सहारा

असम में हालिया बाढ़ ने बड़ी संख्या में परिवारों, किसानों और ग्रामीण इलाकों को प्रभावित किया है। ऐसे में केंद्र की ओर से आवास और कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सीएम सम्राट चौधरी ने बहनों को दिए 3 तोहफे

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की बहनों के लिए कई अहम एलान किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए तीन बड़ी योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्टार्टअप चैलेंज, बालिका पीएचडी फेलोशिप और स्कूल-कॉलेज के पास पुलिस दीदी की तैनाती का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने पुलिस दीदी (अभया ब्रिगेड) के लिए 4,700 दोपहिया वाहनों का लोकार्पण एवं फ्लैग ऑफ किया। अब स्कूल-कॉलेजों के पास पुलिस दीदी तैनात रहेंगी।

बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को अपने नवाचार एवं उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। 2100 महिलाओं को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत एक हजार छात्राओं को चार वर्षों तक 10000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

'मां हूं, जिम्मेदारियां हजार हैं, लेकिन देश सबसे पहले'

गोद में जुड़वां बच्चियां, कंधे पर सरकारी बैग, जनगणना ड्यूटी कर रही टीचर ने लूटी वाहवाही

ब्लिट्ज ब्यूरो

गुवाहाटी। असम की इस शिक्षिका के लिए, जनगणना 2027 की ड्यूटी का मतलब है सरकारी काम के साथ-साथ अपने बच्चों की देखभाल भी करना। रूमी डेका, जिन्हें जनगणना से जुड़ा काम सौंपा गया था, हाल ही में अपने दोनों बच्चों के साथ काम करती हुई देखी गई। रूमी डेका के शेयर किए गए एक वीडियो में उनके बच्चे अपनी मां के साथ दिख रहे हैं, जबकि वह अपनी फील्ड की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ये दोनों उनकी जुड़वां बेटियां हैं। दोनों महज 2 साल की हैं और वह उन्हें लेकर ड्यूटी कर रही हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और कई लोग बच्चों की देखभाल करते हुए भी अपना काम जारी रखने की उनकी कोशिश की तारीफ कर रहे हैं। जनगणना के काम में फील्ड विजिट और ऑफिस के बाहर जाकर काम करना शामिल हो सकता है। डेका के मामले में, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए वे अपने बच्चों को भी साथ ले जाती रही हैं।

ऐसा नहीं है कि रूमी डेका का जो वीडियो वायरल हुआ है, वह उसी दिन बच्चियों को लेकर फील्ड पर निकलीं थीं। वह इससे पहले भी बच्चियों को लेकर जनगणना के काम पर निकलीं। रूमी डेका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मां हूं, जिम्मेदारियां हजार हैं, लेकिन देश सबसे पहले। उन्होंने दिलवाला इमोजी बनाया और आगे लिखा कि दो नन्हें कदम साथ हैं, फिर भी कर्तव्य की राह नहीं रुकेगी। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक और वीडियो शेयर करते हुए रूमी ने लिखा कि ड्यूटी भी, मां की जिम्मेदारी भी और साथ में मेरी दो नन्ही जानें। जिंदगी की सबसे खूबसूरत ड्यूटी। हर जिम्मेदारी आसान हो जाती है, जब साथ में अपने बच्चे हों।

लोगों ने उठाए सवाल तो पति ने दिया जवाब

मां का कर्तव्य और प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने वाले रूमी डेका के इस वीडियो ने ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। लोगों के सवालों का जवाब रूमी के पति ने दिया। उन्होंने लिखा कि उनके पति के तौर पर, मैं उन कुछ लोगों के लिए यह साफ करना चाहता हूं जो पूछ रहे हैं, वह स्कूल कैसे संभालती हैं? उनका स्कूल घर के पास है, जबकि जनगणना की ड्यूटी के लिए अलग-अलग जगहों और घरों में जाना पड़ता है।

नालंदा विवि की वैश्विक उड़ान, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित विवि से करार

बिहारशरीफ। नालंदा विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय अकादमिक साझेदारी के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक, शोध और ज्ञान सहयोग को मजबूत करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (यूडब्ल्यूए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है। मुंबई में आयोजित 10वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के दौरान दोनों संस्थानों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त शोध परियोजनाओं, शिक्षण कार्यक्रमों और अकादमिक सम्मेलनों में सहयोग करेंगे। शिक्षक और छात्रों के आदान-प्रदान का रास्ता भी खुलेगा। दोनों संस्थान अकादमिक संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करेंगे। इससे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और शोध के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

सीएम विजय की बड़ी डील, जापानी कंपनी तमिलनाडु में करेगी ₹1000 का निवेश

मिलेंगे 1,000 से ज्यादा हाई-एंड टेक्नोलॉजी जॉब

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय राज्य में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और आकर्षित करने में सफल रहे हैं। इस बार निवेश के लिए राज्य सरकार से हाथ मिलाया है जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारतीय इकाइयों ने। जी हां, राज्य सरकार ने हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड और हिताची एनर्जी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

तमिलनाडु में औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी परिवेश को बढ़ावा देने के लिए हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त खुद मुख्यमंत्री थलपति विजय भी उपस्थित थे। बताया गया है कि दोनों कंपनियां राज्य में तीन से पांच वर्षों के दौरान 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे राज्य में 1,000 से भी ज्यादा हाई-एंड टेक्नोलॉजी जॉब भी मिलेंगे।

निवेश कहां होगा

एक बयान के अनुसार निवेश होने वाले 1,000 करोड़ रुपये का उपयोग दो प्रमुख विस्तार परियोजनाओं में किया जाएगा। इनमें चेन्नई के पोरूर इलाके में स्थित हिताची ग्रुप के ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर और चेंगलपट्टू स्थित हिताची एनर्जी इंडिया की विनिर्माण इकाई का विस्तार शामिल है। इनमें राज्य के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए बेहतर करियर अवसर उपलब्ध होंगे।

ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी

हिताची ग्रुप ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है। इसी की दोनों सब्सिडियरी कंपनियों के भारत में विस्तार के लिए आज यह समझौता हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अलावा उद्योग मंत्री एस. कीर्तना, मुख्य सचिव एम. साईकुमार सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। साथ ही हिताची इंडिया के एमडी और सीईओ तक कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

टॉप पर तमिल, फिर हिंदी-अंग्रेजी, चल गई सीएम की ट्रिक

तमिलनाडु में टीवीके की करिश्माई जीत के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की चर्चा उत्तर के राज्यों तक हो रही है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की मेजबानी तमिलनाडु के पास थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की तो वहीं विजय उपाध्यक्ष की हैसियत से मौजूद रहे। तमिलनाडु पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत करने वाले सीएम सी जोसेफ विजय ने क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तमिल भाषा को शीर्ष पर रखा। बैठक के मुख्य मंच पर सबसे ऊपर तमिल भाषा के बाद हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया।

विजय की पहल की हो रही तारीफ

बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। टीवीके और विजय के फैंस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के इस दांव की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व की दो बैठकों के बैनर भी साझा किए है। इसमें एक बैठक केरल में और दूसरी आंध्र प्रदेश में हुई थी।

विजय के तमिल यानी क्षेत्रीय भाषा को ऊपर रखने के मास्टरस्ट्रोक की तुलना अब पिनराई विजयन और जगनमोहन से हो रही है। उन दोनों बैठकों की भी अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी लेकिन उसमें क्षेत्रीय भाषा को मंच के मुख्य बैनर में जगह नहीं मिली थी।

ब्लिट्ज ब्यूरो

टेरर फंडिंग से चुकाई एमबीबीएस की फीस!

नहीं मिलेगी डिग्री, मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की स्टूडेंट की याचिका

नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट से एमबीबीएस की एक छात्रा को जोरदार झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अपनी सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मेडिकल की एक छात्रा को उसके शिक्षण संस्थान से कोर्स और एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट जारी किए जाने का आदेश देने की मांग वाली अर्जी ठुकरा दी गई थी।

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरूल मुरुगन की बेंच ने कहा कि चेत्तिनाद एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन को संबंधित छात्रा ने एमबीबीएस कोर्स के दौरान जो एमबीबीएस कोर्स की फीस चुकाई, उसे नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने इन आरोपों में सीज किया है कि वह माओवादी गतिविधियों के दौरान जबरन उगाही से जुटाई गई थी।

छात्रा को स्पेशल कोर्ट जाने को कहा

हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर छात्रा वास्तव में बेकसूर है तो वह जब्त की गई रकम को रिलीज करवाने के लिए एनआईए स्पेशल कोर्ट से संपर्क कर सकती है।

अदालत ने कहा कि संबंधित कॉलेज से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह फीस वापस पाने के लिए एनआईए के खिलाफ अदालत में जाए।

अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि वह पूरी तरह से बेकसूर है और दावा करती है कि वह फंड वैध था, तो उसे सक्षम स्पेशल कोर्ट से ही राहत मिल सकती है, एनआईए की ओर से जब्त फंड रिलीज करवाने में हम एक निजी शिक्षण संस्थान पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि याचिकाकर्ता के द्वारा जमा की गई फीस की रकम को एनआईए से निकलवाने के लिए कानूनी लड़ाई का बोझ ले।

'जबरन सर्टिफिकेट जारी करवाना अन्याय'

अदालत ने साफ किया कि एनआईए केस में छात्रा को भले ही आरोपी नहीं बनाया गया हो, लेकिन वह अपराध से जुटाई गई रकम पर दावा नहीं कर सकती।

हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे ही एनआईए ने कोर्स फीस जब्त कर ली, कानूनी तौर पर उसकी फीस बकाया हो गई।

हाई कोर्ट ने कहा कि जब कॉलेज को स्टूडेंट से फीस मिली ही नहीं, तो उससे जबरन सर्टिफिकेट जारी करवाना घोर अन्याय होगा।

शादी की रस्में बीच में रोक दुल्हन ने कैटरिंग के लिए आई महिलाओं का किया इलाज

तिरुवनंतपुरम। अपनी ही शादी के बीच अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आप क्या करेंगे? केरल की एक डॉक्टर के लिए इसका जवाब बहुत आसान था। यह दुल्हन के लिबास में डॉक्टर शिरीन सुबैर थीं। वह शादी की रस्मों को बीच में रोककर कैटरिंग के दो बीमार महिला कर्मचारियों की मदद करती हुई नजर आई।

महिलाओं की नाक से बहने लगा था खून

यह घटना केरल के कन्नूर में शिरीन सुबैर की शादी के दौरान हुई। जश्न के बीच, कैटरिंग टीम की दो महिलाओं की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक महिला की नाक से खून बहने लगा, जबकि दूसरी को चक्कर आने लगे। जब शादी में मौजूद लोगों को पता चला कि दुल्हन एक डॉक्टर है, तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए उसे बुलाया।

डॉ. शिरीन उस समय दुल्हन के लिबास में सजी हुई थीं। लोगों को हड़बड़ी में देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उन्हें जैसे ही पता चला, शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर तुरंत मरीजों की तरफ दौड़ पड़ीं। जमीन पर बैठकर वह दोनों महिलाओं को तुरंत मेडिकल फर्स्ट-एड देने लगीं। अस्पताल ले जाने से पहले डॉ. शिरीन ने दोनों महिलाओं की स्थिति को पूरी तरह स्थिर कर दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड को मिला 'मेगा बूस्टर', केरलम सरकार सौंपेगी 18.16 एकड़ जमीन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के लिए अच्छी खबर आई है। केरलम सरकार ने कंपनी के प्रस्तावित शिप ब्लॉक बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 18.16 एकड़ जमीन लीज पर देने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट में करीब ₹5,000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है।

कोचीन शिपयार्ड का शेयर विगत दिवस 2.2% की तेजी के साथ 1,491 रुपये के भाव पर बंद हुआ। शेयर का 52-वीक हाई 1,979 रुपये और 52-वीक लो 1,186 रुपये है।

2,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना कोच्चि में विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कोचीन शिपयार्ड बड़े पैमाने पर शिप ब्लॉक निर्माण की क्षमता विकसित करेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निवेश से करीब 2,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग सेवाओं और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

कोच्चि के पास स्थित द्वीप पर मिलेगी जमीन

सरकार जिस जमीन को लीज पर देने जा रही है, वह कोच्चि शहर के करीब स्थित एक द्वीप पर है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान माना जा रहा है क्योंकि यहां से समुद्री गतिविधियों और शिपबिल्डिंग ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा। सरकार और कोचीन शिपयार्ड के बीच कई दौर की चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह मामला काफी समय से लंबित था, जिसे अब कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

सरकार को मिलेगी रेगुलर कमाई

खबर के मुताबिक, इस जमीन के बदले कोचीन शिपयार्ड सरकार को हर साल ₹1.45 करोड़ का लीज रेंट देगा। जीएसटी समेत यह राशि करीब ₹1.70 करोड़ सालाना होगी। हालांकि इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा केवल लीज आय नहीं, बल्कि राज्य में आने वाला ₹5,000 करोड़ का निवेश और उससे पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां मानी जा रही हैं।

शिपबिल्डिंग सेक्टर को मिलेगा नया बूस्ट

भारत सरकार समुद्री क्षेत्र, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में कोचीन शिपयार्ड का यह विस्तार प्रोजेक्ट देश के शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकता है।

इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से कोच्चि एक महत्वपूर्ण शिपबिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग हब के रूप में और मजबूत होगा। साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित होने की संभावना भी बढ़ेगी।

चीनी कम

सरकार ने कहा- इथेनॉल को दोष न दें

ब्लिट्ज ब्यूरो

पिछले एक महीने में भारत में चीनी की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के समय बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार के ई20 (इथेनॉल) पर ज़ोर देने को ज़िम्मेदार ठहराए जाने के बाद मचे हंगामे के बीच, केंद्र सरकार ने हाल ही में इस पर चुप्पी तोड़ी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया कि कीमतों में बढ़ोतरी का संबंध इथेनॉल उत्पादन से है।

मंत्रालय ने कहा कि हालिया बढ़ोतरी के पीछे घरेलू और ग्लोबल, दोनों तरह के कारण हैं, साथ ही यह भी कहा कि अगले क्रशिंग सीज़न तक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

मंत्रालय के अनुसार, चीनी की खुदरा कीमतें 20 जुलाई को 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अब सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए उपाय किए हैं।

कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कई वजहें बताई, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू चीनी उत्पादन, त्योहारों के मौसम से पहले ज़्यादा मांग, मौसम की वजह से फसल को नुकसान, ग्लोबल सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों द्वारा सट्टेबाजी या जमाखोरी शामिल है।

मौजूदा सीजन के लिए भारत का चीनी उत्पादन 306 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) रहने का अनुमान है, जो शुरुआती अनुमान 343 एलएमटीसे कम है। मंत्रालय ने इस कमी के लिए फसल से जुड़ी समस्याओं को ज़िम्मेदार ठहराया, जिनमें रेड रॉट, टॉप बोरर बीमारी और भारी बारिश के कारण जलभराव शामिल हैं।

> **सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कई वजहें बताई, जिनमें उम्मीद से कम घरेलू चीनी उत्पादन, त्योहारों के मौसम से पहले ज्यादा मांग, मौसम की वजह से फसल को नुकसान, ग्लोबल सप्लाई में कमी और इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों द्वारा सट्टेबाजी या जमाखोरी शामिल है।**

क्या कीमत बढ़ने की वजह इथेनॉल है?

सरकार का कहना है कि नहीं। मंत्रालय ने कहा, चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है।

मंत्रालय ने बताया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा

असल में कम हुआ है - 2022-23 में यह लगभग 12 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9 प्रतिशत हो गया है। साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब लगभग तीन-चौथाई इथेनॉल का उत्पादन अनाज, खासकर मक्के से होता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इथेनॉल पॉलिसी से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, जिससे उन्हें किसानों का बकाया चुकाने में मदद मिली है। सरकार के अनुसार, 20 अगस्त तक मिलों ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का 97 प्रतिशत बकाया चुका दिया था।

वैश्विक कमी की वजह

भारत का घरेलू बाज़ार भी अंतरराष्ट्रीय रुझानों से प्रभावित हो रहा है। सरकार का अनुमान है कि 2026-27 में वैश्विक स्तर पर चीनी की 33 लाख मीट्रिक टन की कमी होगी, क्योंकि खराब मौसम के कारण प्रमुख बाज़ारों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतें 30 जून को $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई, जो दो महीने से भी कम समय में 16 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी है।

केंद्र सरकार ने कीमतों को और बढ़ने से रोकने और त्योहारों के मौसम में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट 30 नवंबर तक लागू रहेगी, जबकि थोक उपभोक्ताओं के लिए 1 सितंबर से 15 दिन की होल्डिंग लिमिट (स्टॉक रखने की सीमा) शुरू हो गई है। जमाखोरी और कृत्रिम कमी का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य की टीमें चीनी मिलों में स्टॉक की भौतिक जांच भी कर रही हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 10 एलएमटी कच्ची चीनी (रॉ शुगर) के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है। चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से ही पेराई (क्रशिंग) शुरू करने की सलाह भी दी गई है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे अक्टूबर में उत्पादन सामान्य 3-4 एलएमटी के मुकाबले 10 एलएमटी से ऊपर जा सकता है।

केंद्र ने कहा कि वह उपभोक्ताओं और गन्ना किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए चीनी के स्टॉक और बाज़ार की गतिविधियों पर नजर रखना जारी रखेगा।

मांग बनाम सप्लाई

भारत में चीनी की मांग आमतौर पर अगस्त से नवंबर के बीच बढ़ती है, जब गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार होते हैं और पारंपरिक मिठाइयों व कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है।

भारत में कुछ बंदरगाह आधारित चीनी रिफाइनरियां हैं जिन्हें कच्ची चीनी का ड्यूटी-फ्री आयात करने की अनुमति है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें उतनी ही मात्रा में रिफाइंड चीनी का निर्यात करना होगा। नई दिल्ली के एक डीलर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सरकार इन रिफाइनरियों से अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा घरेलू बाजार में भेजने के लिए कह सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर लगभग 3,00,000 टन चीनी उपलब्ध हो सकती है।

एक सीनियर ट्रेडर ने कहा कि सरकार को सीज़न के खत्म होने का इंतज़ार करने के बजाय जनवरी में ही कदम उठाना चाहिए था, जब चीनी का उत्पादन कम होने लगा था। ट्रेडर ने कहा कि जब तक आयातित चीनी असल में घरेलू बाजार में नहीं पहुंच जाती, तब तक तेज़ी का माहौल बना रह सकता है।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) का अनुमान है कि 2025-26 में घरेलू खपत 285 लाख टन और उत्पादन 279 लाख टन होगा (इसमें इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 30 लाख टन को शामिल नहीं किया गया है)। 30 सितंबर तक क्लोजिंग स्टॉक लगभग 36 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि 31 जुलाई को यह लगभग 80 लाख टन था।

एयर इंडिया की मालिकों से मदद की गुहार

कामकाज जारी रखने के लिए 1.5 अरब डॉलर की इक्विटी की मांग

हरविंदर आहूजा

एयर इंडिया अपने मालिकों - टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस - से लगभग 1.5 अरब डॉलर की नई इक्विटी की मांग कर रही है। यह मांग भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन द्वारा रिकॉर्ड सालाना नुकसान दर्ज करने के कुछ महीनों बाद की गई है।

2022 में टाटा द्वारा इस पूर्व सरकारी एयरलाइन का कंट्रोल संभालने के बाद से शेयरहोल्डर फंडिंग के लिए एयर इंडिया की ओर से सार्वजनिक रूप से की गई सबसे बड़ी मांगों में से एक है। यह एयरलाइन के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, क्योंकि यह कई अरब डॉलर के कायाकल्प से गुजर रही है, जिसमें इसके मौजूदा बेड़े का नवीनीकरण भी शामिल है।

एयरलाइन और उसकी बजट यूनिट एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मार्च में समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में कुल 2.33 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया, जो पिछले साल के नुकसान से दोगुना से भी अधिक है। इस नुकसान का असर सिंगापुर एयरलाइंस के मुनाफे पर भी पड़ा है।

एक सूत्र ने कहा, एयर इंडिया को तुरंत फंड चाहिए, हालांकि यह रकम किश्तों में मिलने की संभावना है। निवेश को पूरा करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस को प्रस्तावित निवेश में अपना हिस्सा देना होगा।

मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि यह फंडिंग नई इक्विटी के रूप में मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी। एयर इंडिया और टाटा संस ने मीडिया के कमेंट के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

सिंगापुर एयरलाइंस, जिसके पास एयर इंडिया की लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने कहा कि वह एयर इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में मदद के लिए टाटा संस के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन उसने एयरलाइन की फाइनेंशियल स्थिति पर कमेंट करने से इनकार कर दिया।

एयर इंडिया को पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस पर रोक, ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के युद्ध से इंटरनेशनल नेटवर्क में रुकावट और पिछले साल हुए एक भयानक क्रैश (जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी) के असर का भी सामना करना पड़ा है। यह फ़ंडिंग की मांग ऐसे समय में आई है जब टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ग्रुप के कंट्रोलिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ महीनों के मतभेदों के बाद हो रहा है, जिसमें एयर इंडिया के नुकसान का भी कुछ हद तक हाथ है।

चंद्रशेखरन ने कहा है कि एयर इंडिया को पटरी पर लाने में एक दशक तक का समय लग सकता है। उन्होंने सप्लाई-चेन में लगातार आ रही रुकावटों और एयरलाइन के पुराने सिस्टम, कल्चर और फ्लीट (विमानों के बेड़े) में बड़े बदलाव की ज़रूरत का हवाला दिया है।

मीडिया की इस साल की शुरुआत की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से ऑर्डर किए गए सैकड़ों जेट की डिलीवरी टालने की कोशिश की है, क्योंकि टाटा एयरलाइन पर लागत कम करने और भारी नुकसान को घटाने का दबाव बना रहा है।

एक सूत्र ने कहा, उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी एयर इंडिया को कैपिटल इन्फ्यूजन (पूंजी डालने) की जरूरत पड़ती रहेगी।

वेस्ट एशिया में युद्ध के कारण एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ने के अलावा, एयर इंडिया को पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस पर रोक, ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के युद्ध से इंटरनेशनल नेटवर्क में रुकावट और पिछले साल हुए एक भयानक क्रैश (जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी) के असर का भी सामना करना पड़ा है।

सिंगापुर के सांसद ने अपील का विरोध किया

मीडिया की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया का बढ़ता नुकसान सिंगापुर की संसद तक पहुंच सकता है। एक विपक्षी नेता ने सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा टाटा की एयरलाइन को सपोर्ट करने के कमर्शियल लॉजिक पर सवाल उठाए हैं। टाटा की इस एयरलाइन ने अपनी हालत सुधारने के लिए स्टेकहोल्डर्स से 1.5 अरब डॉलर के बेलआउट की मांग की है।

वर्कर्स पार्टी के सांसद केनेथ टियोंग बून कियाट ने सिंगापुर एयरलाइंस के ज़रिए एयर इंडिया को सपोर्ट करने के लिए टेमासेक फंड के किसी भी भविष्य के इस्तेमाल का विरोध किया। सिंगापुर एयरलाइंस की भारतीय एयरलाइन में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

टेमासेक होल्डिंग्स - सिंगापुर सरकार की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म - एसआईए की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। एयर इंडिया की बाकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा के पास है।

सिंगापुर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेफरी सियो को लिखे एक पत्र में, टियोंग ने पूछा कि क्या एयर इंडिया के नुकसान का आकलन एसआईए की जरूरी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की क्षमता के आधार पर किया गया है और क्या इससे 'सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर एक्ट' के तहत एसआईए के तय स्टेटस से जुड़ी नोटिफ़िकेशन की ज़िम्मेदारी लागू होती है।

उन्होंने 8 सितंबर के संसदीय सत्र में मौखिक जवाब मांगा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ प्राइवेट शेयरहोल्डर्स के लिए सवाल नहीं है। दोनों में से कोई भी चेक लिखे, इसका टेमासेक पर बड़ा असर पड़ेगा। किसी पर भी, खासकर सिंगापुर के लोगों पर, एयर इंडिया को चलाने की ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं सिंगापुर एयरलाइंस के ज़रिए एयर इंडिया को सहारा देने के लिए टेमासेक के फंड के किसी भी भविष्य के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करूंगा और न ही इसकी उम्मीद करूंगा। अगर सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया पर अपना दांव जारी रखना चाहती है, तो उसे अपने दम पर ऐसा करना चाहिए, न कि टेमासेक के दम पर। टेमासेक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एसआईए और एयर इंडिया ने सवालों का जवाब नहीं दिया।

टियोंग ने मिनिस्टर को लिखा अपना पत्र अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया। उनके मोबाइल पर टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं हो सका।

सिंगापुर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेफरी सियो को लिखे एक पत्र में, टियोंग ने पूछा कि क्या एयर इंडिया के नुकसान का आकलन एसआईए की जरूरी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की क्षमता के आधार पर किया गया है और क्या इससे 'सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर एक्ट' के तहत एसआईए के तय स्टेटस से जुड़ी नोटिफ़िकेशन की ज़िम्मेदारी लागू होती है।

एयर इंडिया पर एसआईए के दो साल के दांव के कारण एयरलाइन को लगभग $1.3 अरब ($780 मिलियन) का ऑपरेटिंग नुकसान हुआ है, जो एक साल पहले $2.02 अरब था। नवंबर 2024 में यह निवेश एयर इंडिया के अहमदाबाद विमान हादसे और पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानन कंपनियों को अपने हवाई क्षेत्र से बाहर रखने (साथ ही ईंधन की बढ़ती कीमतों) से कुछ ही महीने पहले किया गया था।

माल ढुलाई में नए दौर का सूत्रपात

गुजरात में पहली डबल-स्टैक लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेन ने ढोया 3922 टन वजन

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने मुंबई के पास स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से वडोदरा मंडल के वरणामा स्थित कॉनकोर के जीसीटी टर्मिनल तक पहली डबल-स्टैक लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेन का सफल संचालन किया। इस ट्रेन ने लगभग 422 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 360 टीईयू कंटेनर ढोए। ढोए गए माल का कुल वजन 3922 टन रहा।

यह ट्रेन पिछले सप्ताह जेएनपीटी से रवाना हुई और पश्चिमी समर्पित माल गलियारे (वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर चली। यह एक ही रेल यात्रा में कंटेनर माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस लॉन्ग-हॉल ट्रेन में दो डबल-स्टैक रैक को जोड़कर चलाया गया। आगे वाले रैक ने जेएनपीटी-वडोदरा मार्ग पर 45+1 लोड संरचना के साथ सफर किया। इसे लोकोमोटिव संख्या 60311 ने खींचा और इसका कुल वजन 1,817 टन था। पीछे वाले रैक में भी 45+1 लोड संरचना थी। इसे लोकोमोटिव संख्या 24690 ने खींचा और इसका वजन 2,105 टन था। दोनों रैक मिलाकर कुल 360 टीईयू कंटेनर ले जाए गए, जिनमें प्रत्येक रैक में 180 टीईयू कंटेनर थे। इस पहल का उद्देश्य जेएनपीटी और अन्य माल ढुलाई टर्मिनलों से कंटेनरों की निकासी को तेज और अधिक प्रभावी बनाना है। एक ही ट्रेन में अधिक माल भेजने से टर्मिनलों पर भीड़ कम होगी और कंटेनरों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अधिक वहन क्षमता होने के कारण समान मात्रा में माल ढोने के लिए कम रेल डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। इससे उपलब्ध रेल मार्ग क्षमता का बेहतर उपयोग होगा, कंटेनरों की आवाजाही तेज होगी और कुल परिवहन समय भी कम होगा।

इसका असर सड़क परिवहन पर भी पड़ेगा। चूंकि यह ट्रेन बिजली से संचालित हुई, इसलिए डीजल चालित सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। एक ट्रेन में बड़ी मात्रा में कंटेनर ले जाने से उतने ही माल के लिए ट्रकों की संख्या घटेगी। इससे डीजल की खपत, सड़कों पर भीड़ और वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

टर्मिनलों पर भीड़ कम होगी, कंटेनरों का लंबा इंतजार होगा खत्म

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश के समर्पित माल गलियारों पर माल ढुलाई को अधिक क्षमता और दक्षता के साथ संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। जेएनपीटी से वरणामा तक इस सफल संचालन ने दिखाया है कि डबल-स्टैक और लॉन्ग-हॉल ट्रेनें बंदरगाहों और देश के अंदरूनी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने तथा रेल आधारित कंटेनर लॉजिस्टिक्स की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

गोंडा से मुरादाबाद के बीच दौड़ी पहली 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन

भारतीय रेलवे का स्वरूप दिनों-दिन तेजी से बदल रहा है। एक ओर जहां बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना तेजी से अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रही है तो वहीं माल ढुलाई के क्षेत्र में भी रेलवे नए कीर्तिमान बना रहा है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित गोंडा जंक्शन से पूर्वोत्तर रेलवे की पहली 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन (मालगाड़ी) चलाई गई। मालगाड़ी गोंडा से सीतापुर के रास्ते मुरादाबाद के लिए रवाना हुई। मालगाड़ी में 129 वैगन लगाए गए थे, जिसे पावरफुल तीन इंजन खींच रहे थे।

लखनऊ मंडल की वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (समन्वय) डा. शिल्पी कन्नौजिया के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरों की उपस्थिति में पहली 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन गोंडा जंक्शन से रवाना की गई। इस फ्रेट ट्रेन में एक साथ एक ही ट्रिप में अधिक माल की ढुलाई संभव होगी। इससे रेलवे की राजस्व आय एवं परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे की पहली फ्रेट ट्रेन

तीन ट्रेनों को एक में मिलाकर चलाने से परिचालन समय, ईन्धन की खपत और ट्रैक क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि 'अवध महाशक्ति' नामक फ्रेट ट्रेन का गोंडा से मुरादाबाद मंडल को वाया सीतापुर होते हुए सफलतापूर्वक संचालन किया गया। रुटीन ओवरहालिंग डिपो (आरओएच) गोंडा द्वारा तैयार यह पूर्वोत्तर रेलवे की पहली फ्रेट ट्रेन है।

इस ट्रेन में कुल 129 वैगन एवं 03 इंजन लगाए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में माल परिवहन को अधिक सुदृढ़ एवं कुशल बनाने की दिशा में एक नई उपलब्धि हासिल की है।

मंडल रेल प्रबंधक के अनुसार 'अवध महाशक्ति' फ्रेट ट्रेन का सफल संचालन मंडल की बेहतर कार्यक्षमता, विभागों के बीच तालमेल और अच्छे प्रबंधन का उदाहरण है।

इसका उद्देश्य माल परिवहन क्षमता को बढ़ाकर ग्राहकों को तेज एवं किफायती सेवा उपलब्ध कराना है। यदि इन मालगाड़ियों को अलग-अलग चलाया जाता तो तीन अलग-अलग मार्ग और चालक दल की व्यवस्था करनी पड़ती। 'अवध महाशक्ति' के रूप में एक साथ चलने से समय की बचत होगी। साथ ही अधिक सवारी और मालगाड़ी के संचालन के लिए मार्ग भी उपलब्ध होगा।

सात सबसे व्यस्त रेलवे रूट्स को चार लेन में बदलने की योजना

नई दिल्ली। सरकार ने देश के सात सबसे व्यस्त रेलवे रूट्स पर भीड़भाड़ कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें चार लेन में बदलने की योजना बनाई है। इन रूट्स की कुल लंबाई 11,000 किमी है। रेलवे के पूरे नेटवर्क में इनकी हिस्सेदारी केवल 16 फीसदी है लेकिन ये रेलवे का करीब 41 फीसदी ट्रैफिक हैंडल करते हैं। इनमें दिल्ली-हावड़ा, हावड़ा-चेन्नई, चेन्नई-मुंबई, मुंबई-दिल्ली, दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-हावड़ा और दिल्ली-गुवाहाटी रूट्स शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद यात्रियों और माल की आवाजाही की बढ़ती मांग को पूरा करना और देश के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ रेल कॉरिडोर की क्षमता को मजबूत करना है। चार-लेन वाले प्रोग्राम के लिए चुने गए सात ज्यादा ट्रैफिक वाले रेलवे रूट भारत के कई बड़े शहरों और इलाकों को जोड़ते हैं।

ये रूट रेलवे नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं और यात्रियों तथा माल के ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। विस्तार योजना के तहत इन रूट्स को चार रेलवे लाइनों के लायक बनाया जाएगा।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 24 कोच वाले 50 ट्रेनसेट होंगे तैयार

चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होगा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर अच्छी खबर आई है। जैसा कि रेल मंत्री पहले भी बता चुके हैं कि आने वाले समय में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चेन्नई की रेलवे कोच फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच तैयार होने वाले हैं। करीब 50 ट्रेन सेट तैयार किए जाने हैं। 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सेट तैयार होने हैं। फिलहाल देश में एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच चलती है, जिसमें थर्ड एसी के 11 कोच, सेकेंड एसी के 4 और फर्स्ट एसी का एक कोच शामिल हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे देश के अन्य रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाए, इसके लिए ट्रेनसेट का तैयार होना बहुत जरूरी है और अब इसी दिशा में काम आगे बढ़ गया है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रोडक्शन का काम कहां तक पहुंचा?

चेन्नई के आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का प्रोडक्शन शुरू होगा। आईसीएफ के जीएम मनीष अग्रवाल ने चेन्नई के एम अरुण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी जानकारी दी है।

जीएम के मुताबिक, 24 कोच वाली स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सेट के लिए जरूरी प्रोडक्शन ड्रॉइंग तैयार हो चुकी है। इनमें कोच का स्ट्रक्चर, दो कोचों को एक-दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था से लेकर अंडरफ्रेम में लगाए जाने वाले उपकरणों से जुड़े डिजाइन शामिल हैं। यानी अब कोच के निर्माण का फ्रेमवर्क तैयार है और जल्द ही ट्रेन सेट का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर में ज्यादा यात्रियों को फायदा

फिलहाल 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन आने वाले समय में 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर में ज्यादा यात्रियों को फायदा मिलेगा। 24 कोच वाली ट्रेन में डेढ़ गुना ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि 24 कोच वाली ट्रेन में थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और स्लीपर के कितने-कितने कोच शामिल होंगे, इसको लेकर अपडेट सामने नहीं आया है। मौजूदा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तुलना में नए ट्रेनसेट को ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा। स्लीपर कोच होने के चलते लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कम समय में गंतव्य तक पहुंचना आसान भी होगा और आरामदायक भी। रेलवे का लक्ष्य वंदे भारत स्लीपर को लेकर ये है कि रेल यात्रा को आधुनिक, तेज और आरामदायक ट्रेनों के जरिए बेहतर बनाया जाए।

अमृत भारत एक्सप्रेस के वैरिएंट 3.0 पर आया अपडेट

आईसीएफ के जनरल मैनेजर मनीष अग्रवाल ने अमृत भारत ट्रेन के वैरिएंट 3.0 को लेकर बताया है कि नेक्स्ट जेनरेशन की अमृत भारत ट्रेनों में एसी, सामान्य और स्लीपर कैटगरी के कोच होंगे, जिससे रेलयात्रियों को किफायती और आरामदायक सफर का एक नया विकल्प मिलेगा। मौजूदा समय में अमृत भारत ट्रेनों में केवल सामान्य और स्लीपर कोच ही होते हैं।

बता दें कि आईसीएफ चेन्नई, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है, जहां ट्रेनों के कोच कम समय में और किफायती लागत में तैयार किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने वंदे भारत तकनीक पर ही आधारित गुड्स ट्रेन के लिए भी काम किया है और फ्रेट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी फ्रेट ईएमयू ट्रेनसेट विकसित किए हैं।

लातूर में बनेंगी 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री से इसका पहला प्रोटोटाइप अब 31 मार्च 2027 तक बाहर आने की उम्मीद है। रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस की ट्रांसमाश होल्डिंग के संयुक्त उपक्रम को 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट बनाने की जिम्मेदारी मिली है हर ट्रेनसेट में 16 कोच होंगे। पहले इसे जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य था।

मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप मौजूदा वित्त वर्ष में बाहर आने की उम्मीद है। पहले इसे जून 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई। यह जानकारी रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम अहमद ने कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक में दी। कंपनी के मुताबिक, मराठवाड़ा फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर के निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के तहत कुल 1,920 कोच तैयार किए जाने हैं।

वंदे भारत स्लीपर प्रोजेक्ट के साथ कंपनी के कारोबार का आकार भी बदल रहा है। कंपनी अब पारंपरिक रेलवे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ-साथ रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। कंपनी के ऑर्डर बुक में बदलाव, रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश, बड़े कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कॉम्पिटेटिव बिडिंग के जरिए हासिल की गई परियोजनाओं में विस्तार इसका हिस्सा हैं।

रेलवे के पहले हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का काम अंतिम चरण में

220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का होगा परीक्षण

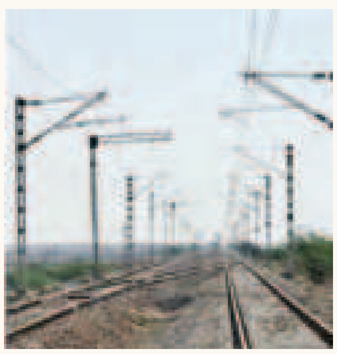

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का देश का पहला समर्पित हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस ट्रैक पर ट्रेनों का परीक्षण 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से किया जा सकेगा। करीब 967.07 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा विकसित की जा रही है।

यह हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक राजस्थान में जोधपुर मंडल के गुढ़ा-ठठाना मीठड़ी के बीच बनाया जा रहा है। यह क्षेत्र जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर है और उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि देश का पहला समर्पित हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक अब अंतिम चरण में है। राजस्थान में तैयार की जा रही इस सुविधा पर देश-विदेश में निर्मित ट्रेनों और रेलवे उपकरणों का परीक्षण किया जा सकेगा। इससे भारतीय रेलवे को नई तकनीक को तेजी से अपनाने तथा ट्रेनों और रेलवे बुनियादी ढांचे के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान में गुढ़ा-ठठाना मीठड़ी के बीच 59 किलोमीटर लंबा नया ब्रॉड गेज समर्पित टेस्ट ट्रैक विकसित किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। इसके जरिए भारत यूइईसी-518/ईएन-14363 मानकों के अनुरूप व्यापक परीक्षण सुविधाओं वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रेलवे अधिकारी के अनुसार, 2027-28 से विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक, जिनमें सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनसेट भी शामिल हैं, का परीक्षण और ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है।

चार प्रमुख परीक्षण सेक्शन

परियोजना के तहत 23 किलोमीटर लंबी मुख्य लाइन, गुढ़ा में 13 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड लूप, नावा में 3 किलोमीटर लंबा एक्सेलरेटेड टेस्टिंग लूप और मीठड़ी में 20 किलोमीटर लंबा कर्व टेस्टिंग लूप बनाया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि रोलिंग स्टॉक के स्थैतिक परीक्षण के लिए 4.5 किलोमीटर लंबा ट्विस्टेड ट्रैक पहले ही पूरा कर चालू किया जा चुका है। वहीं, 31.5 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड स्ट्रेच और 3 किलोमीटर लंबे एक्सेलरेटेड टेस्टिंग लूप का काम लगभग पूरा हो चुका है और सितंबर 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। मीठड़ी में 20 किलोमीटर लंबे कर्व टेस्टिंग लूप का काम भी उन्नत चरण में है और इसके 2026 के अंत तक परिचालन में आने की संभावना है।

गुढ़ा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव

परियोजना को मौजूदा रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने गुढ़ा स्टेशन पर आवश्यक बदलावों का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें जोधपुर मंडल की क्योसान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में संशोधन, गुढ़ा एंड स्टेशन की ओर स्लॉट कंट्रोल की व्यवस्था तथा सभी 18 प्वाइंट के प्वाइंट इंडिकेशन सर्किट में बदलाव शामिल हैं।

नए अवतार में दिखाई देंगे रेल के पुराने जंग लगे डिब्बे

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अक्सर आपने रेलवे स्टेशनों के आसपास पुराने कोच यानी यात्री डिब्बे देखे होंगे, जिन पर जंग लगा हुआ होता है, और वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब उन पुराने डिब्बों को भी रेलवे ने बेहतरीन इस्तेमाल में लाने का प्लान बना लिया है।

इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर 'रेल कोच रेस्टोरेंट' का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बहुत जल्द यह अनूठा रेस्टोरेंट यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। गांधीधाम स्टेशन का यह रेल कोच रेस्टोरेंट आने वाले दिनों में शहर के मुख्य आकर्षण और 'फूड स्पॉट' के रूप में अपनी खास पहचान बनाने के लिए तैयार है।

बनने वाला है अनूठा रेस्टोरेंट

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ गांधीधाम स्टेशन का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन रेल कोच रेस्टोरेंट के बुनियादी ढांचे, इंटीरियर डिजाइन, सुरक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता मानकों की विस्तृत समीक्षा की। डीआरएम ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर काम को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द इसका भव्य उद्घाटन किया जा सके।

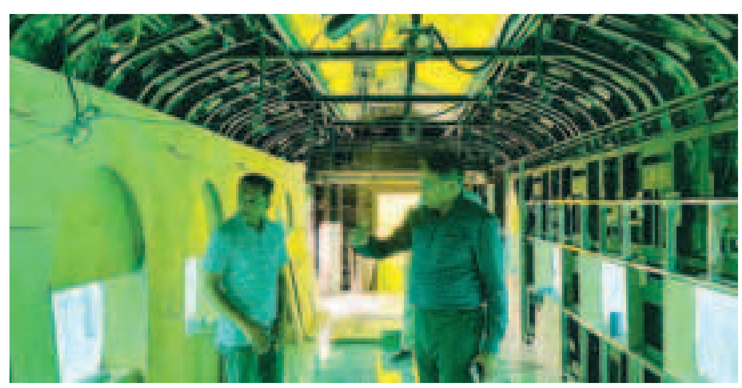

दहेज केस में 60-90 दिन में चार्जशीट की हो कोशिश

आरोप तय होने के बाद गवाही भी जल्द शुरू होः सुप्रीम कोर्ट

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दहेज प्रताड़ना और दहेज मौत से जुड़े मामलों की सुनवाई अब ज्यादा तेजी से कराने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी की जल्द पेशी सुनिश्चित की जाए और आमतौर पर 60 से 90 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रयास किया जाए। आरोप तय होने के बाद गवाही भी जल्द शुरू हो और संभव हो तो लगातार, दिन-प्रतिदिन दर्ज की जाए।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 15 दिसंबर 2025 के अपने फैसले के अनुपालन पर सुनवाई के दौरान राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज मौत) और 498-ए(दहेज प्रताड़ना) और बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत आने वाले मामलों को, जहां तक संभव हो, प्राथमिकता देकर तेजी से निपटाया जाए।

जिला अदालतें तीन साल से ज्यादा समय से लंबित मामलों की पहचान करें। खासकर उन मामलों पर ध्यान दिया जाए, जो आरोप तय होने या गवाही दर्ज होने के चरण में अटके हैं। इनकी हर महीने या तीन महीने में समीक्षा की जाए। कोर्ट ने कहा जागरूकता अभियान चले,और यह स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी हो।

व्यवस्था सुधारने को सुप्रीम कोर्ट के 10 निर्देश

1. सहायता व्यवस्था मजबूत होः दहेज निषेध अधिकारी सक्रिय हों। वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था मजबूत की जाए।
2. जागरूकता बढ़ाएंः दहेज,लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलें।
3. पुराने मामलों को प्राथमिकताः तीन साल से पुराने मामलों की हर माह या तिमाही समीक्षा हो।
4. ट्रायल जल्द शुरू होः चार्जशीट के बाद आरोपी की जल्द पेशी हो। कोशिश हो कि 60-90 दिनों में आरोप तय हों और इसके बाद गवाही जल्द शुरू हो।
5. बेवजह तारीखें न मिलें : अनावश्यक स्थगन से बचें।
6. तकनीक से निगरानीः डिजिटल डैशबोर्ड और ऑटोमैटिक अलर्ट हो।
7. हाई कोर्ट में पुराने केस देखेंः पुरानी अपील, रिविजन, धारा 482 सीआरपीसी /528 बीएनएसएस की याचिकाओं और जमानत मामलों की नियमित समीक्षा हो।
8. जिम्मेदारों की ट्रेनिंगः जज, पुलिस, अभियोजक, प्रोटेक्शन ऑफिसर और काउंसलर की ट्रेनिंग हो।
9. उचित मामलों में मध्यस्थताः सिर्फ वैवाहिक विवाद वाले मामलों में ही कोर्ट मध्यस्थता का विकल्प देखे।
10. हर साल रिपोर्टः हाई कोर्ट और राज्य/यूटी हर साल 15 जनवरी, मई और सितंबर को रिपोर्ट दें जिसमें लंबित मामलों, उनकी स्थिति की जानकारी हो।

फर्जी बीमा दावों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। शीर्ष कोर्ट ने फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए सभी राज्यों को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी बीमा दावे दाखिल किए जा रहे हैं और उन्हें मंजूर भी किया जा रहा है। एक ही वाहन को कई दुर्घटनाओं में दिखाया जाता है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जो प्रारंभ में दुर्घटना में शामिल एक गाड़ी की पहचान से जुड़ा था।

पीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संकेत मिले हैं और उसने देश भर में धोखाधड़ी वाले दावों की जांच करने के लिए मामले का दायरा बढ़ा दिया।

पीठ ने आदेश दिया

अदालत का मानना है कि यह बताना जरूरी है कि बीमा कंपनियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे धोखाधड़ी वाले सभी दावे एसआईटी को भेजें। अगर यह पाया जाता है कि संबंधित राज्य की एसआईटी को मामले भेजने में भेदभाव किया गया है तो अदालत संबंधित बीमा कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी।

धोखाधड़ी वाले ऐसे दावों से न सिर्फ बीमा कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है बल्कि ग्राहकों को भी अधिक किस्त देनी पड़ सकती है।

मिलीभगत पर विभागीय कार्रवाई करें

पीठ ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे एसआईटी को पर्याप्त कर्मचारी दें और ऐसे मामलों की जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि अगर एसआईटी की सिफारिश या एफआईआर से उनके अधिकारियों की धोखाधड़ी वाले दावों में मदद करने की बात का पता चलता है तो वे बिना देरी किए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें। आदेश में बीमा कंपनियों से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया जिसमें एसआईटी को भेजे गए मामलों और कंपनी के हितों के खिलाफ काम करने या धोखाधड़ी में मदद करने के संदेह वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई आंतरिक कार्रवाई का विवरण हो।

उत्तर प्रदेश में गठित हो चुकी है एसआईटी

पीठ ने गौर किया कि उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के बाद ही एसआईटी का गठन कर लिया था। राज्य ने पीठ को बताया कि एसआईटी को 2,188 शिकायतें मिली थीं जिनमें 1,029 से ज्यादा की जांच हो चुकी है। 533 आरोपियों के खिलाफ 231 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाई

ब्लिट्ज ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्कूल में स्कार्फ अथवा हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती । स्कूल यूनिफॉर्म अनुशासन बच्चों के बीच समानता, संस्थागत पहचान और पंथनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने इस टिप्पणी के साथ एक नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। प्रयागराज में टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने स्कूल के तय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि वह कक्षा छह से ही स्कार्फ पहनकर आती रही है और इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। कक्षा 11 में दाखिले के समय स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ पहनकर आना ड्रेस कोड का उल्लंघन है, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। छात्रा ने इसके खिलाफ जिलाधिकारी को दो शिकायती पत्र दिए। रिपोर्ट मांगे जाने पर सहायक डीआईओएस ने दोनों पक्षों को सुना।

प्रधानाचार्या ने स्पष्ट किया कि स्कूल सह शिक्षा संस्था है, जहां सभी समुदायों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए समान ड्रेस कोड लागू है। किसी एक छात्रा को विशेष छूट देने से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह उसकी गरिमा व शारीरिक स्वायत्तता से भी जुड़ा है। इससे रोकना अनुच्छेद 14 व 19(1)(ए) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। राज्य सरकार तथा सीबीएसई की ओर से पेश वकील ने कहा कि स्कूल निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्था है, जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन नहीं आता।

ब्रिक्स सदस्यों में 11 कानूनी परंपराओं को जोड़ने के लिए 'न्याय सेतु' का प्रस्ताव रखा सीजेआई ने

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यहां आयोजित 11वीं ब्रिक्स प्लस लीगल फोरम में 'न्याय सेतु' (न्याय का सेतु) और न्याय के अर्थशास्त्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 'बहुध्रुवीय दुनिया में कानून का शासन' विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 'न्यानॉमिक्स' शब्द गढ़कर वैश्विक न्यायिक सहयोग के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो कानून के शासन और आर्थिक समृद्धि का प्रत्यक्ष संश्लेषण है। उन्होंने ब्रिक्स प्लस सदस्य देशों में 11 कानूनी परंपराओं को जोड़ने के लिए 'न्याय सेतु' का भी प्रस्ताव रखा।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि सतत आर्थिक विकास भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होने के बजाय संस्थागत स्थिरता, विश्वास और पूर्वानुमान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स प्लस देशों में मानवता का 40% से अधिक और

राजधानी में 11वीं ब्रिक्स प्लस लीगल फोरम का आयोजन

वैश्विक पीपीपी उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा शामिल है, और कहा कि मजबूत न्यायिक प्रणाली तीव्र आर्थिक प्रगति की रीढ़ है।

उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसा शब्द गढ़ने का प्रयास किया है जो कानून के शासन और अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों में इसके व्याप्त होने के बीच के संबंध को पूरी तरह से वर्णित करेगा - न्यानॉमिक्स , या सरल शब्दों में कहें तो न्याय का अर्थशास्त्र। जिस पैमाने पर हमारा देश प्रगति कर रहा है, और यह बात ब्रिक्स प्लस देशों में से प्रत्येक के लिए सच है, वह हमारी संस्थाओं की प्रकृति के कारण है, जिनमें न्यायपालिका प्रमुख है।

साझेदार देशों के बीच मजबूत कानूनी सहयोग की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स प्लस कानूनी मंच द्वारा विचार के लिए दो पहलों का प्रस्ताव रखा - एक ब्रिक्स प्लस न्यायिक फैलोशिप और एक साझा न्यायशास्त्र भंडार।

प्रस्तावित न्यायिक फेलोशिप के तहत, सदस्य देशों के पेशेवर न्यायाधीशों को एक-दूसरे की अदालतों में संक्षिप्त रूप से बैठने और विभिन्न कानूनी प्रणालियों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने न्यायशास्त्र के एक साझा भंडार का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें केस कानून के डिजिटलीकरण में भारत के अनुभव का उपयोग किया गया, ताकि ब्रिक्स प्लस क्षेत्राधिकार में दिया गया एक निर्णय समान कानूनी प्रश्नों से निपटने वाले अन्य न्यायालयों को सूचित कर सके।

सूर्यकांत ने कहा, यदि आज सुबह आप अपने शब्दकोश में एक वाक्यांश आत्मसात करना चाहते हैं, तो वह 'न्याय सेतु' होना चाहिए, जो न्याय का एक सेतु है जो 11 कानूनी परंपराओं को जोड़ता है, जिन्होंने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि विश्वास को निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बजाय जानबूझकर विकसित किया जाना चाहिए। मैं इस मंच के विचारार्थ दो प्रस्ताव रखना चाहता हूं। पहला, एक ब्रिक्स+ न्यायिक फैलोशिप, जिससे प्रत्येक पेशेवर न्यायविद को एक-दूसरे की अदालतों में संक्षिप्त रूप से कार्य करने का अवसर मिले। दूसरा, एक साझा न्यायशास्त्र भंडार, जो भारत द्वारा डिजिटल केस कानून में किए गए महत्वपूर्ण निवेश पर आधारित हो, ताकि नई दिल्ली, ब्रासीलिया या प्रिटोरिया में लिखे गए किसी फैसले को उसी तरह के प्रश्न का सामना कर रही अन्य अदालतों को सूचित करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा समझौता, पाकिस्तान को बड़ा झटका

देखते रह गए अमेरिका और चीन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में इसके लिए द्विपक्षीय बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आगे के सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इस समझौते को चीन व पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

दिल्ली में मिले राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी

इस समझौते के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग मजबूत होगा, जिसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना शामिल है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रमुख आधार हैं। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने जुलाई 2026 में दोनों देशों के नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान को याद किया।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बड़ी डील

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने फ्री और खुले हिंद-प्रशांत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा सहयोग और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर एक-दूसरे के आकलन साझा करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता और सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। दोनों ने बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का भी विरोध किया। इसके अलावा खोज और बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा।

डिफेंस मिनिस्टर्स की द्विपक्षीय मीटिंग

दोनों पक्ष समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाजों और सैन्य इकाइयों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ाएंगे। संयुक्त अभ्यास, सैन्यकर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान भी होगा। बंदरगाहों, रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौसैनिक जहाज निर्माण में सहयोग की संभावना को भी बढ़ाया जाएगा। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की बात कही।

दोनों पक्षों ने नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और डिजाइन की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति जताई है। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत व जापान ने रक्षा जहाज निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में एक-दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठाने पर जोर दिया। 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत की उत्पादन क्षमता के इस्तेमाल पर भी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। दोनों पक्ष निकट भविष्य में जहाज मरम्मत सुविधाओं के पारस्परिक इस्तेमाल के लिए व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए हैं।

'धर्म गार्जियन' और 'जेमेक्स' जैसे युद्धाभ्यास का विस्तार

दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान के बीच लगातार बढ़ रहे सैन्य अभ्यासों का स्वागत किया। इसके तहत 'धर्म गार्जियन' और 'जेमेक्स' जैसे युद्धाभ्यासों का विस्तार किया जाएगा।

भारतीय थियेटर कमांड में हेल्प करेगा जापान

जापान ने सहमति जताई है कि भारत के एकीकृत थिएटर कमांड्स बनने के बाद उनसे सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्पेशल फोर्सेज के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारत अपनी सैन्य संरचना को थिएटर कमांड्स के रूप में रीऑर्गनाइज कर रहा है ताकि विभिन्न सेवाओं का बेहतर समन्वय हो। जापान के साथ यह सहयोग दोनों देशों की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा। इससे संयुक्त अभियानों में आसानी होगी। बदलते सुरक्षा माहौल में यह कदम समयानुकूल है क्योंकि दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं।

संयुक्त नौसैनिक जहाज निर्माण

नएसमन्वय तंत्र और 2+2 संवाद को लेकर एक नया डायरेक्टर जनरल/जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। यह परिचालन, खुफिया, प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग सहयोग का समन्वय करेगा। दोनों पक्ष टोक्यो में चौथे भारत-जापान 2+2 संवाद को भी तेज करेंगे। यह तंत्र नियमित बातचीत सुनिश्चित करेगा। रक्षा सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, निर्भरता कम होगी।

भारत जल्द टेस्ट करेगा 500 किलो का बंकर बस्टर बम, कांप उठेगा पाकिस्तान

नई दिल्ली। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) इसी साल सितंबर-अक्टूबर में स्वदेशी पीजीबी-500 प्रिसिजन गाइडेड बम का एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान पर उड़ान परीक्षण करने जा रहे हैं। यह 500 किलोग्राम का वॉरहेड वाला बम कठोर बंकरों, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है।

कई जांच एक साथ

परीक्षण में विमान पर ले जाना, एयरोडायनेमिक बैलेंस और सुरक्षित रिलीज आदि की जांच की जाएगी। गाइडेंस सिस्टम में जीपीएस/आईएनएस के साथ प्रिसिजन टर्मिनल टारगेटिंग शामिल होने की उम्मीद है। पीजीबी-500 स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड बम परिवार का हिस्सा है। यह भारी वर्ग का आयुध है जो उच्च सटीकता के साथ मजबूत लक्ष्यों को भेद सकता है।

जमीन के अंदर के ठिकाने करेंगे नष्ट

पड़ोसी मुल्कों - जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार में छिपे आतंकियों के बंकर या जमीन के अंदर के ठिकाने अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे।

आयात पर निर्भरता कम होगी

एसयू-30एमकेआई पहले से ब्रह्मोस, अस्त्र और रुद्रम जैसे हथियार ले जाता रहा है। इस बम के जुड़ने से विमान की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ेगी।

भारतीय वायु सेना के जगुआर जेट में लगेगी इजराइली किट

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के जगुआर विमान ने इजराइली रेस्ट ग्लाइड किट का सफल परीक्षण किया है। यह किट साधारण बमों को 120 किमी तक की रेंज और 10 मीटर सटीकता वाले प्रिसिजन स्टैंड-ऑफ हथियार में बदल देती है। एल्बिट सिस्टम्स द्वारा जारी वीडियो फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई है कि यह किट जगुआर विमान के साथ जुड़ चुकी है।

यह डेवलपमेंट भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जगुआर लंबे समय से आईएएफ का मुख्य ग्राउंड अटैक प्लेटफॉर्म रहा है। अब रेस्ट किट के जरिए यह विमान दुश्मन की एयर डिफेंस जोन में ज्यादा अंदर घुसे बिना दूर से ही सटीक हमला कर सकेगा।

रेस्ट किट क्या है, कैसे काम करता है?

रेस्ट का मतलब है रेंज एक्सटेंशन एंड स्मार्ट टेल। यह एक मॉड्यूलर गाइडेंस और रेंज-एक्सटेंशन पैकेज है जो साधारण अनगाइडेड

(डम्ब) बमों को स्मार्ट, प्रिसिजन और स्टैंड-ऑफ हथियार में बदल देता है। किट में स्मार्ट टेल सेक्शन होता है जिसमें आईएनएस (इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम) और जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) गाइडेंस लगा होता है।

साथ ही एंटी-जैमिंग क्षमता भी है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में भी सटीकता बनाए रखती है। बम पर लगने वाले डिप्लॉयबल अपर विंग्स रिलीज होने के बाद खुल जाते हैं। बम को ग्लाइड करने में मदद करते हैं। रिलीज की ऊंचाई और स्पीड के हिसाब से यह किट 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल (सीईपी) 10 मीटर तक बताया गया है।

मिसाइल, टैंक, रडार समेत भारत अब खुद बनाएगा 405 जरूरी रक्षा सामान

3070 करोड़ का हो सकता है कारोबार, बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने 405 जरूरी रक्षा सामानों की नई सूची जारी की है। इसे छठी पॉसिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट कहा गया है। इन सामानों को अब भारत में ही बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे करीब 3070 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है।

इस सूची में भारतीय तटरक्षक बल के 16 और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के 389 सामान शामिल हैं। इनमें टैंक, लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल, रडार, सोनार और दूसरे रक्षा उपकरणों से जुड़े पार्ट्स शामिल हैं। इन सामानों का भारत में सफल विकास होने के बाद इन्हें भारतीय कंपनियों से खरीदा जाएगा।

टी-90 और एसयू-30एमकेआई के सामान भी शामिल

नई सूची में एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर, एसयू-30एमकेआई और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमानों से जुड़े सामान शामिल हैं. एएल-31एफपी इंजन के जरूरी सामान भी इसमें रखे गए हैं। टी-72, टी-90 और बीएमपी-II जैसे टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से जुड़े सामान भी सूची में

हैं। इसके अलावा युद्धपोतों और कोन्कर्स-एम, इनवार और एमआरएसएएम जैसी मिसाइलों से जुड़े सामान भी शामिल किए गए हैं। रक्षा में इस्तेमाल होने वाले रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के सामान भी इस सूची का हिस्सा हैं। हाई एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक एम्युनिशन और दूसरे जरूरी रक्षा सामान भी इसमें शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों को मिलेगा काम

इन 405 सामानों को भारत में बनाने के लिए हर सामान की एक तय समय सीमा होगी। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियां और भारतीय तटरक्षक बल इन सामानों को अलग-अलग तरीकों से देश में तैयार करेंगे। इसमें 'मेक' प्रक्रिया और खुद तकनीक विकसित करने जैसे तरीके शामिल हैं। इस काम में निजी कंपनियों के साथ एमएसएमई और स्टार्टअप भी हिस्सा ले सकेंगे।

अब भारत बनाएगा खुद का मोबाइल ब्रांड : अश्विनी वैष्णव

दो-तीन सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों को मंजूरी बहुत जल्द

आस्था भट्टाचार्य

नई दिल्ली। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश में मोबाइल विनिर्माण की व्यापक सफलता से सीख लेकर एक भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड विकसित करने पर काम कर रही है। वैष्णव ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फोनपे की तरफ से इंडस एप स्टोर को पेश करते हुए कहा कि सरकार बहुत जल्द दो-तीन सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों को मंजूरी दे सकती है।

इस मौके पर वैष्णव ने कहा, '' हम देश में संपूर्ण हैंडसेट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर काम करेंगे।'' वैष्णव ने कहा, ''बड़े पैमाने पर मोबाइल विनिर्माण की हमारी शुरुआती सफलता ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। इसने उद्योग को बहुत आत्मविश्वास दिया है। इसने पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों को भारत आने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अगले पांच वर्षों में यह सफर तय किया जाएगा।'

प्रधानमंत्री ने दिया खाका

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक बहुत स्पष्ट खाका दिया है। उन्होंने कहा, ''हमने अपना भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया और हमें पहले ही बहुत अच्छी सफलता मिल चुकी है। माइक्रोन संयंत्र पहले से ही निर्माणाधीन है।''

उच्च मात्रा वाले फैब्रिकेशन संयंत्र

अश्विनी वैष्णव ने कहा, ''बहुत कम समय सीमा में हमें दो या तीन और स्वीकृतियां भी देखने को मिलेंगी।''

उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में तीन-चार अच्छे, उच्च मात्रा वाले फैब्रिकेशन संयंत्र स्थापित करने, एक खास मुकाम बनाने और कम-से-कम एक उत्पाद श्रेणी में अग्रणी भूमिका हासिल करने पर विचार कर रही है।

सेना प्रमुख धीरज सेठ नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित

ब्लिट्ज ब्यूरो

काठमांडू। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परम्परा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं।

जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिगदेल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए।

रणनीतिक हथियारों के विकास व उत्पादन की दिशा में लंबी छलांग की तैयारी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की स्वदेशी रक्षा मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का दायरा बढ़ाने के मकसद से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (डीआरडीओ) ने घरेलू प्राइवेट कंपनियों को 'एमएसएस' (मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम) क्लस्टर के मिसाइल और बम हथियार सिस्टम प्रोजेक्ट्स के विकास और उत्पादन में पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया है।

इस खास रिसर्च एजेंसी ने इस संबंध में 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (ईओआई) जारी किया है। एजेंसी ने कहा, इस ईओआई का मकसद मिसाइल और रणनीतिक सिस्टम क्लस्टर के मिसाइल/बम हथियार सिस्टम प्रोजेक्ट्स के विकास और उत्पादन के लिए संभावित विकास-सह-उत्पादन पार्टनर्स (डीसीपीपी) की पहचान करना और उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। यह ईओआई इसलिए अहम है क्योंकि सरकार देश के भीतर बड़े पैमाने पर रणनीतिक हथियारों के निर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है।

डीआरडीओ पहले ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के जरिए अग्नि, पृथ्वी और आकाश मिसाइलों और पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (एमबीआरएल) सिस्टम जैसे सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में पहुंचा चुका है।

पार्टनरशिप मॉडल के तहत, चुनी गई कंपनियों को उत्पादन से जुड़ी ज़िम्मेदारियों के लिए विचार किए जाने से पहले डीआरडीओ की तकनीकी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करना होगा।

सुसाइड ड्रोन 'दिव्यास्त्र एमके3' की पहली टेस्ट फ्लाइट सफल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थित कावा यूएवी प्राइवेट लिमिटेड (होवरइट) ने 'दिव्यास्त्र एमके 3' नामक अगली पीढ़ी के जेट-संचालित लॉइटिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन की पहली सफल टेस्टिंग की। कंपनी के अनुसार यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण वाला लॉइटिंग म्यूनिशन तैयार किया गया है। इसमें भारतीय जेट इंजन लगा है। टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक निर्धारित एयर स्ट्रिप पर हुई।

यह एक ऐसा सिस्टम है जो लक्ष्य की तलाश में लंबे समय तक हवा में घूम सकता है। सही समय पर सटीक हमला कर सकता है। अब तक भारत में इस तरह के सिस्टम या तो विदेशी तकनीक पर निर्भर थे या फिर पारंपरिक प्रोपेलर इंजन वाले थे। दिव्यास्त्र एमके 3 ने इस कमी को पूरा करते हुए जेट इंजन की ताकत को स्वदेशी रूप में जोड़ा है।

स्वदेश की सफलता

इस म्यूनिशन को डीजी प्रोपल्शन कंपनी के जेट इंजन से ताकत मिली है। उड़ान के दौरान इंजन का प्रदर्शन सभी मानकों पर खरा उतरा। कंपनी का कहना है कि यह इंजन अब मिशन के लिए पूरी तरह सक्षम साबित हो चुका है और दिव्यास्त्र एमके 3 पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह उपलब्धि सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि भारतीय एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी मान्यता है। अब तक जेट इंजन जैसी जटिल तकनीक मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों के पास मानी जाती थी। डीजी प्रोपल्शन और होवरइट ने दिखाया कि भारतीय इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सकती है।

'दिव्यास्त्र एमके 3' कार्यक्रम की शुरुआत 2026 के शुरूआत में हुई थी। महज एक कैलेंडर वर्ष के अंदर ही यह जेट-संचालित लॉइटिंग म्यूनिशन आसमान में उड़ने में सफल हो गया। यह गति और फोकस भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के सह-संस्थापकों ने कहा कि यह सिर्फ टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि एक इरादे का एलान है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह अपने ही सीमाओं के अंदर जेट-संचालित सटीक स्ट्राइक सिस्टम की कल्पना, इंजीनियरिंग और उड़ान पूरी तरह कर सकता है।

एफिल टावर से ऊंचे ब्रिज पर फुल स्पीड से दौड़ रही वंदे भारत

रेलवे ने इसे बताया भारत का गौरव

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे ट्रैक चिनाब रेल ब्रिज है, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) का हिस्सा है। एफिल टावर से भी ऊंचे इस रेलवे ट्रैक पर सरपट वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। नॉर्दर्न रेलवे ने अपने ट्विटर (अब X) हैंडर पर इस ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो जारी किया है और इसे भारत का गौरव करार दिया है।

चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई की बात करें, तो ये चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर (1,178 फीट) ऊपर बना हुआ है और इस तरह से ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज में टॉप पर आता है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। बता दें कि फ्रांस के एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर है।

बीते साल जनवरी 2025 में इस रेल ट्रैक पर आखिरी सफल परीक्षण किया गया था और फिर इस पर श्रीनगर-कटरा वंदे भारत सेवा शुरू हुई। इस साल अप्रैल 2026 में इसे जम्मू तवी तक बढ़ाया गया। ये 180 डिग्री की चढ़ाई वाली चुनौतियों से भरा रेल ट्रैक है।

उत्तर रेलवे ने एक्स पर चिनाब ब्रिज से गुजरती हुई तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन का वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा गया है, 'भारत का गौरव, विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल चिनाब ब्रिज पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस।

ब्रिज का भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता

चिनार ब्रिज को बनाने में रेलवे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संकरी सड़कें, लगातार बदलता और खराब मौसम, ऊंची पहाड़ियां और अस्थिर चट्टानी भूभाग ने प्रोजेक्ट को और भी जटिल बनाया, क्योंकि ट्रैक तैयार करने के लिए भारी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन सामग्री को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाना चुनौती रही। तमाम दिक्कतों के बाद इस पूरा करने में सफलता मिली। बता दें कि ये चिनाब पुल इस तरह डिजाइन किया गया है कि तेज भूकंप, तेज हवाओं और विस्फोट जैसी परिस्थितियों का भी सामना कर सके। इसे अत्यधिक सुरक्षा मानकों के हिसाब बनाया गया है और इसमें करीब 25000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ।

तिपहिया, ट्रेन और खेत: तिमाही का असली हिसाब

ब्लिट्ज विशेष

राष्ट्रीय सांख्यिकी ने अप्रैल-जून की तिमाही के जारी किए आंकड़े

नई दिल्ली। जीडीपी का आंकड़ा टीवी पर एक मिनट चलता है और उतर जाता है। 31 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल-जून की तिमाही के जो आंकड़े जारी किए, उनमें असली ख़बर उस मुख्य आंकड़े में नहीं है। वह उस परिशिष्ट में है जिसे कोई नहीं पढ़ता- उन बत्तीस संकेतकों की सूची में, जिनसे यह पूरा हिसाब बनता है।

वहां अर्थव्यवस्था वैसी नहीं दिखती जैसी वह प्रतिशत में दिखती है। वहां वह ट्रैक्टर, तिपहिया, रेल का डिब्बा और खेत की मेड़ बनकर दिखती है।

पहले खेत

खेती और उससे जुड़े कामों का उत्पादन इस तिमाही में 3.6 फ़ीसदी बढ़ा। यह कोई चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है और यही इसकी खूबी है, खेती में स्थिरता ही सबसे बड़ी खबर होती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 4.8 फ़ीसदी और चावल 6.2 फीसदी ऊपर है। गेहूं में बढ़त सिर्फ़ 0.5 फ़ीसदी रही, जो कम है, पर घटी नहीं है।

इसके साथ एक और आंकड़ा पढ़िए। यूरिया और पोषक तत्व आधारित खाद की सब्सिडी 57.6 फ़ीसदी बढ़ी है। यानी खेत तक खाद पहुंचाने पर सरकार का ख़र्च डेढ़ गुना से ज्यादा हो गया। किसान के लिए इसका मतलब सीधा है, बोरी का दाम वही रहा, और अंतर सरकार ने उठाया। खेती में स्थिरता ही सबसे बड़ी खबर होती है। इस तिमाही में खेती ने वही किया जो उससे उम्मीद थी।

फिर सड़क

तिपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री 29.7 फीसदी बढ़ी है। यह आंकड़ा जितना छोटा दिखता है, उतना है नहीं। तिपहिया वाहन शौक से नहीं खरीदा जाता, वह कमाई का साधन होता है। जब तीस फीसदी ज्यादा ऑटो और लोडर बिकते हैं, तो तीस फीसदी ज्यादा परिवार यह मानकर कर्ज उठाते हैं कि अगले साल सवारी और सामान दोनों मिलेंगे। व्यावसायिक वाहनों की बिक्री 18.3 फीसदी और माल ढोने वाले वाहनों का पंजीकरण 20.1 फीसदी बढ़ा है। एक साल पहले इन्हीं आंकड़ों में हलचल नहीं थी। घरेलू वाहनों का पंजीकरण 15.9 फीसदी ऊपर है।

और फिर पटरी

रेलवे में यात्री प्रति किलोमीटर 8.3 फीसदी बढ़े हैं। पिछले साल इसी तिमाही में यह बढ़त 3.0 फीसदी थी। यह लगभग तिगुनी रफ़्तार है, और इसका मतलब है कि लोग ज्यादा दूर तक जा रहे हैं, काम के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। दूसरी तरफ माल की ढुलाई में नेट टन किलोमीटर 0.7 फीसदी घटे हैं। एक ही विभाग के दो आंकड़े, दो अलग दिशाएं। बिजली उत्पादन का सूचकांक 9.3 बढ़ा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 1.5 फीसदी घटा था। सीमेंट का सूचकांक 8.9 फीसदी और तैयार इस्पात की खपत 8.3 फीसदी ऊपर है। निर्माण क्षेत्र 7.7 फीसदी बढ़ा। बिजली, सीमेंट और लोहा, तीनों एक साथ बढ़ें तो कहीं कुछ बन रहा होता है।

तिमाही, घर की भाषा में

- खेती और सहायक काम – 3.6% बढ़े
- खाद्यान्न 4.8%, चावल 6.2% ऊपर
- खाद सब्सिडी 57.6% बढ़ी
- तिपहिया बिक्री 29.7% ऊपर
- व्यावसायिक वाहन 18.3% ऊपर
- रेल यात्री किलोमीटर 8.3% बढ़े
- बिजली उत्पादन सूचकांक 9.3% ऊपर
- निर्माण क्षेत्र 7.7% बढ़ा

एक आंकड़ा जो ठहरकर पढ़ने लायक है

पूरी तिमाही में सबसे बड़ी बात यह है कि निवेश ने खपत की बराबरी कर ली। ब्लिट्ज ने प्रेस नोट के दूसरे विवरण से खुद जोड़कर देखा है, कुल 7.8 फीसदी की बढ़त में परिवारों के खर्च का हिस्सा 3.95 प्रतिशत अंक है और स्थायी पूंजी निर्माण, यानी कारख़ाना-मशीन-सड़क-गोदाम बनाने का हिस्सा भी 3.95 प्रतिशत अंक। दोनों बराबर। यह आंकड़ा प्रेस नोट में कहीं छपा नहीं है; यह इसी डेस्क की गणना है। खपत से बढ़ी अर्थव्यवस्था चीजे खर्च करके बढ़ती हैं। निवेश से बढ़ी अर्थव्यवस्था आगे ज्यादा बनाने की ताकत बनाकर बढ़ती है। इस तिमाही में भारत ने दोनों बराबर किए हैं और दूसरा वाला ही आने वाले सालों में नौकरी बनकर लौटता है।

जिस तिमाही में मशीन का आयात 51.5 फीसदी और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 15.2 फीसदी बढ़ता है, उस तिमाही में कारखाने की नींव पड़ रही होती है। नींव तीन साल बाद निर्यात का ऑर्डर बनती है और ऑर्डर नौकरी बनता है।

जीडीपी आंकड़ों पर केंद्र ने दी अहम जानकारी

जीडीपी के आंकड़ों को लेकर छिड़ी बहस के बीच केन्द्र सरकार ने जीडीपी आंकड़ों में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने बताया कि फरवरी 2026 में नए बेस ईयर के अनुसार की नई सीरीज जारी की गई थी। पुराने सिस्टम में मिली कमियों को दूर करते हुए नई मेथडोलॉजी अपनाई गई।

पिछले साल के जीडीपी स्तर को 369 लाख करोड़ से संशोधित कर 361 लाख करोड़ किया गया था। पहली तिमाही जीडीपी को भी 86 लाख करोड़ से संशोधित कर 80.3 लाख करोड़ किया गया था। ये संशोधन फरवरी 2026 में ही किए गए थे, अभी नहीं। दो अलग-अलग वर्षों की तुलना कॉन्स्टेंट प्राइस पर की जाती है, ताकि महंगाई के प्रभाव को हटाकर वास्तविक आर्थिक वृद्धि को देखा जा सके। नई सीरीज के साथ 2022-23 तक की बैक सीरीज भी पूरी पारदर्शिता के साथ जारी की गई है।

तीन लाख भारतीयों को जापान में मिलेगी नौकरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

जापानी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंश्योरेंस में निवेश करें : पीयूष

नई दिल्ली। जापान अब भारत से सिर्फ बाजार नहीं, कामगार भी मांग रहा है। जापानी पक्ष ने तीन लाख भारतीय तकनीशियनों, प्रबंधकों, देखभालकर्मियों और परिचरिकाओं को प्रशिक्षित कर जापान में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा है। प्रशिक्षण जापान या भारत में कहीं भी हो सकता है लेकिन उन्हें काम जापानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ही करना होगा।

यह प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के चार दिनी जापान दौरे में सामने आया। इसका मतलब है कि भारत-जापान आर्थिक रिश्ते का ढांचा अब निवेश व व्यापार से आगे बढ़कर लोगों पर केंद्रित होगा। असल में जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और अस्पताल, वृद्धाश्रमों, कारखानों और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले हाथ घट रहे हैं।

भारत के लिए यह अवसर है, लेकिन शर्तों के साथ। तीन लाख लोगों को भेजने का मतलब है भाषा प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन और दोनों देशों के बीच योग्यता की आपसी मान्यता का एक पूरा तंत्र खड़ा करना। यह तंत्र बना तो जापान भारत के लिए सिर्फ निवेश नहीं, रोजगार का भी बाजार बनेगा। अगर नहीं बना तो उन कई घोषणाओं जैसा रह जाएगा, जो बैठकों के बाद सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं।

व्यापार घाटे पर दो टूक, भारत अपनी गुणवत्ता बदले

इस दौरे ने व्यापार घाटे के सवाल पर एक भ्रम भी तोड़ा है। भारतीय पक्ष को उम्मीद थी कि जापान अपने आयात नियम कुछ ढीले करेगा, प्रमाणन प्रक्रिया आसान करेगा और भारतीय माल के लिए दरवाजा थोड़ा चौड़ा करेगा लेकिन जापान का संदेश साफ है, भारत के लिए अपने मानक नहीं बदलेगा, क्योंकि वे भारत के लिए बने ही नहीं हैं। वही मानक हर देश के माल पर लागू होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भारत के मानक हर आयातक पर लागू होते हैं। सीधा अर्थ है, घाटा घटाने का बोझ पूरी तरह भारत के पाले में है। भारत को जापानी बाजार में जगह रियायत से नहीं, अपने उत्पाद को जापानी कसौटी पर खरा उतारकर लेनी होगी।

संक्षेप में

भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती साबित की : निर्मला

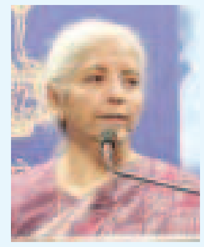

वाशिंगटन। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती साबित करते हुए देश के आम नागरिकों के हितों की रक्षा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिकागो में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखने के साथ-साथ अपनी घरेलू आवश्यकताओं को केंद्र में रखा। इसी का परिणाम है कि दुनिया भर के संकटों के बावजूद भारतीय किसान, घरेलू परिवार और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कई देशों के आर्थिक अनुमान लड़खड़ा गए, वहीं भारत ने अपनी सीमाओं के बावजूद चुनौतीपूर्ण माहौल में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा। वित्त मंत्री के अनुसार, भारत की सफलता का आधार वैश्विक बदलावों को लगातार ट्रैक करने के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को समझना रहा है। इसी नीतिगत सूझबूझ ने देश को बड़े आर्थिक झटकों से बचाए रखा है।

हर माह 30 लाख की इंटर्नशिप

भारत में हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी') कंपनियां इंटर्न्स को रिकॉर्ड तोड़ पैसा ऑफर कर रही हैं। शेयर बाजार में सुस्ती और डेरिवेटिव्स के कड़े नियमों के बीच, ये कंपनियां गणित और डेटा के माहिर युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भारी-भरकम सैलरी दे रही हैं।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुड़गांव की कंपनी क्वाडेये इंटर्न्स को दो महीने के करीब 30 लाख रुपये ऑफर कर रही है। यानी दो महीने की इंटर्नशिप के लिए छात्र को 60 लाख रुपये मिलेंगे। यह रकम पिछले साल के मुकाबले करीब चार गुना ज्यादा है। वहीं, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल दो महीने की इंटर्नशिप के लिए करीब 50 लाख रुपये दे रही है, जबकि पहले यह रकम 16 लाख रुपये के आसपास थी। विदेशी ट्रेडिंग कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। एम्सटर्डम की आईएमसी ट्रेडिंग ने दो महीने की इंटर्नशिप का पैकेज दोगुना कर 50 लाख रुपये कर दिया है। ऑप्टिवर नाम की कंपनी तो दो महीने के लिए करीब 60 लाख रुपये ऑफर कर रही है।

जियो के आईपीओ को मंजूरी

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल और टेलीकॉम ब्रांच, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल पोर्टल पर भी जियो के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का स्टेटस 'अप्रूव्ड' दिखाने लगा है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि आईपीओ मार्केट में कब आएगा। लेकिन, जानकारों का अनुमान है कि दीपावली के आसपास इसे लॉन्च किया जा सकता है।

भारतीय कंपनियों की भरमार

दुबई और भारत के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दुबई चैंबर्स के अध्यक्ष मोहम्मद अली राशिद लूता ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 के अंत तक दुबई चैंबर के सक्रिय सदस्यों के रूप में पंजीकृत भारतीय कंपनियों की संख्या बढ़कर 85,841 हो गई है। वर्ष 2026 की पहली छमाही के दौरान ही 7,579 नई भारतीय कंपनियां दुबई चैंबर से जुड़ीं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दुबई आधारित प्रकाशन अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों में लगातार विस्तार देखा जा रहा है। वर्ष 2025 में भारत और दुबई के बीच गैर-तेल व्यापार 60.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है।

उज्बेकिस्तान-भारत के बीच यू

दोनों देशों में आयुर्वेद से खनिज तक बढ़ेगा स

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है। यूपीआई की उज्बेकिस्तान में भी एंट्री हो गई है।

इस दौरान संस्कृति, आयुर्वेद, खनिज संसाधन, पर्यटन, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त और वैज्ञानिक शोध समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों और अन्य पहलों की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी यात्रा के परिणामों के मुताबिक, दोनों देशों ने 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर समझौता किया है। दोनों देशों में आयुर्वेद से खनिज तक बढ़ेगा सहयोग।

बौद्ध स्थलों के संरक्षण में सहयोग

भारत उज्बेकिस्तान के प्राचीन बौद्ध स्थलों फयाज टीपा और करा टीपा के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहयोग करेगा। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल उज्बेकिस्तान के तेरमेज क्षेत्र में स्थित हैं। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एजेंसी के बीच 'लैटर ऑफ इंटेंट' हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच भी सहयोग का समझौता हुआ है। वहीं, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी एमओयू किया गया।

भारत के खान मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के खनन उद्योग एवं भूविज्ञान मंत्रालय के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। पर्यटन के क्षेत्र में 2026-28 के लिए साझेदारी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और उज्बेकिस्तान की डिप्लोमैटिक अकादमी के बीच सहयोग का समझौता हुआ है। दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों के बीच आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने के लिए भी एमओयू किया गया है।

प्रमुख फैसले

- भारत-उज्बेकिस्तान संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदले।
- अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए भारत देगा 10 लाख डॉलर।
- बौद्ध स्थलों, फयाज टीपा और करा टीपा के संरक्षण में भारत सहयोग करेगा।
- हिंदी भाषा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्तियां।
- भूविज्ञान, खनिज, आयुर्वेद, पर्यटन, पर्यावरण, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध में सहयोग बढ़ेगा।
- ताशकंद में संस्कृत चेयर स्थापित होगी।

यूजेडक्यूआर कोड

भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र यूपीआई को भी उज्बेकिस्तान में विस्तार मिलने जा रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और उज्बेकिस्तान के नेशनल इंटरबैंक प्रोसेसिंग सेंटर (एनआईपीसी) के बीच वाणिज्यिक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत के यूपीआई एप से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय क्यूआर कोड यूजेडक्यूआर को स्कैन कर व्यापारिक भुगतान किया जा सकेगा।

पीएम मोदी ने ताशकंद में योग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग सत्र में भी हिस्सा लिया।

भारत और किर्गिस्तान बढ़ाएंगे आर्थिक सहयोग

एससीओ सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने किर्गिज राष्ट्रपति से कई मुद्दों पर की चर्चा

ब्लिट्ज ब्यूरो

बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के साथ आम बैठक की। दोनों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री ने 26 वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए भी राष्ट्रपति जापारोव को बधाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत तथा किर्गिज गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ सम्मेलन दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की विशेषता वाले आपसी सम्मान, विश्वास और समर्थन को दर्शाता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जापारोव का उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ-साथ एससीओ शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आभार जताया।

आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के साथ भी अलग से द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने कहा, भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने वाला है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में व्यापार और निवेश के संबंध और मजबूत होंगे।

उधर, अमेरिका ने किर्गिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बिश्केक में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जापारोव से मुलाकात की।

किर्गिज नागरिक बोले, भारत हमारा बड़ा भाई

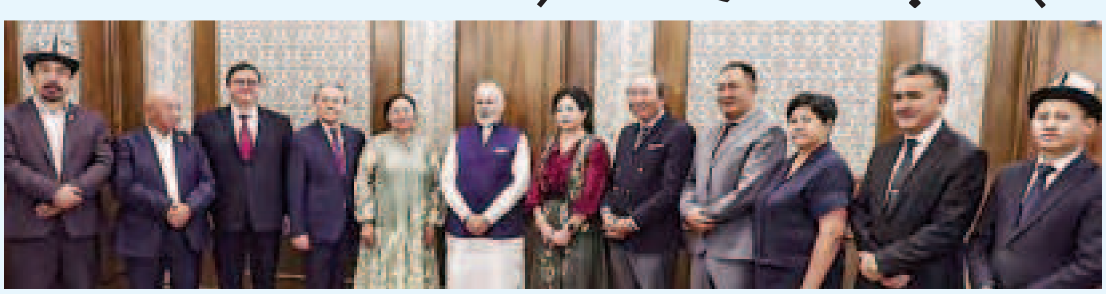

मोदी ने विगत दिवस बिश्केक में भारत के मित्रों' के एक समूह से मुलाकात की। इसमें भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्य, पर्यावरण प्रेमी, योग साधक, शिक्षाविद, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के पूर्व प्रतिभागी तथा शोधकर्ता शामिल थे। उनसे मिलने वाले लोगों में किसी के लिए यह जिंदगी भर याद रहने वाला मौका था, तो किसी के लिए वह क्षण खास था जब प्रधानमंत्री को पहली बार सामने से देखने का मौका मिला। कई किर्गिज बोले, भारत हमारा बड़ा भाई है।

रेनियम समेत हुए 11 समझौते

सहयोग, यूपीआई की एक और देश में दस्तक

मोदी ने पुतिन से कहा, इस युद्ध का अंत हो

बोले, लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा भारत-रूस सहयोग

ब्लिट्ज ब्यूरो

बिश्केक। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच विगत दिवस द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि वह शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में बिताया गया एक-एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम नई आशा से भर देता है।

एससीओ समिट से इतर हुई इस मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा हमें 'एंडलेस वॉर' से 'एंड ऑफ वॉर' की दिशा में जाना ही होगा। यह मानवता की भलाई के लिए जरूरी है। सभी मुद्दों का जल्द शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होना चाहिए। यही मानवता की पुकार और भारत का संदेश है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।

शी जिनपिंग और पुतिन ने वीजा मुक्त यात्रा पर की चर्चा

चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिश्केक में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने चीन-रूस के बीच वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था समेत आपसी चिंता के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों नेताओं की यह बैठक बिश्केक में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2026 से इतर हुई। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार पुतिन ने जिनपिंग से कहा कि यदि चीनी पक्ष इसे संभव और उपयोगी मानता है तो हम वीजा मुक्त व्यवस्था पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

एससीओ सम्मेलन से इतर हुई दोनों नेताओं के बीच बैठक को स्थायी बनाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था के कारण इस वर्ष की पहली छमाही में दोनों देशी के बीच पर्यटकों की आवाजाही में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक दिसंबर, 2025 को पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर चीनी नागरिकों को पारस्परिकता के आधार पर 14 सितंबर 2026 तक 30 दिनों तक बिना वीजा रूस में प्रवेश की अनुमति दी थी।

बातचीत से सुलझाएं विवाद : पीएम मोदी

पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से अहम मुलाकात

ब्लिट्ज ब्यूरो

बिश्केक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातों और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान की अपील की। वहीं, पेजेश्कियन ने आग्रह किया कि मोदी अलग-अलग पक्षों के साथ भारत के व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध और खून-खराबे के रास्ते से हटाकर बातचीत और समझौते के रास्ते पर लौटने में मदद करें।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक एससीओ के शिखर सम्मेलन से इतर पेजेश्कियन के साथ बैठक की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ व्यापार का दायरा बढ़ाना और उसमें विविधता लाना चाहता है। हमने क्षेत्र के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की। भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही सभी कोशिशों का समर्थन करना जारी रखेगा।

भारत के समर्थन को सराहा

उधर, मोदी और पेजेश्कियन की मुलाकात के बारे में ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने हालिया युद्ध के दौरान ईरान को भारत से मिले समर्थन और सहयोग के लिए सराहना की। शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।

समुद्री आवाजाही पर विस्तार से चर्चा

विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने समुद्री आवाजाही और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हालत में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे, जिसमें वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री कर्मी शामिल है- को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने बिवर और एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों में ईरान के साथ मिलकर काम करने के भारत के इरादे को दोहराते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति पेजेश्कियन का भारत में स्वागत करने का इंतजार है। पेजेश्कियन ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से विभिन्न पक्षों के साथ नई दिल्ली के संपर्कों का इस्तेमाल करने की अपील की।

अब एक साल वकालत कर बन सकेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा बदलाव, पहले तीन साल की थी अनिवार्यता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल सर्विस में सिविल जज के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की लीगल प्रैक्टिस की शर्त को बदल दिया है। अब 1 साल की प्रैक्टिस पूरी करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद 1 साल ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी करनी होगी।

इसके बाद उन्हें 1 साल की क्लर्कशिप भी करनी होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मई 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने

उस फैसले में संशोधन किया है, जिसमें एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए 3 साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य किया गया था।

अब कितने साल की वकालत जरूरी है?

सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डिवीजन ज्यूडिशियल सर्विस में भर्ती के नियमों में अहम बदलाव किया है। भविष्य में सिविल जज भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम एक साल की सत्यापित एक्टिव लॉ प्रैक्टिस जरूरी होगी। यानी पहले जहां 3 साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य था। हालांकि, सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से नियुक्ति नहीं मिलेगी।

31 मार्च 2027 तक बिना प्रैक्टिस भी कर सकेंगे आवेदन

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत बड़ा फैसला दिया है। इसके अनुसार 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली सभी ज्यूडिशियल सर्विस भर्ती में लॉ की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार बिना किसी पूर्व वकालत के भी आवेदन कर सकेंगे।

इस अवधि में कैंडिडेट्स से 1 साल की प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र नहीं मांगा जाएगा और उन्हें आवेदन के लिए यह शर्त पूरी मानी जाएगी। हालांकि, चयन होने के बाद उम्मीदवारों को सीधे नियमित नियुक्ति नहीं मिलेगी।

पहले उन्हें एक साल तक स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एक साल की क्लर्कशिप करनी होगी।

इसमें पहले छह महीने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या हायर ज्यूडिशियल सर्विस के अधिकारी की देखरेख में और अगले छह महीने हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

हाई कोर्ट में 10वीं पास को मिलेगी ₹52000 तक मंथली सैलरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

तिरुवनंतपुरम। 10वीं पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। केरल हाई कोर्ट ने माली की रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाल ही में इससे जुड़ा वैकेंसी नोटिफिकेशन कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hckrecruitment.keralacourts.in पर जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कोर्ट ने अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल पर शुरू भी कर दी है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं।

यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विज्ञापन संख्या 15/2026 के माध्यम से निकाली गई है। अभ्यर्थियों को इसी वैकेंसी में अपना आवेदन जमा करना होगा। सेलेक्शन प्रोसेस आवेदन पत्र आने की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। यह बिना परीक्षा डायरेक्ट इंटरव्यू या फिर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के होगा।

हाई कोर्ट माली के लिए योग्यता

- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता हासिल की हो।
- गार्डनिंग में डिप्लोमा या नर्सिंग मैनेजमेंट और ओर्नामेंटल गार्डनिंग में या - एग्रीकल्चर (प्लांट प्रोटेक्शन) या वीएचएससी एग्रीकल्चर किया हो।
- जिन अभ्यर्थियों को हॉर्टिकल्चर या फार्म से जुड़े काम का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी।
- जिन उम्मीदवारों का जन्म 02 जनवरी 1986 से 01 जनवरी 2008 (दोनों तिथियों को भी गिना जाएगा) तक हुआ वे आवेदन के योग्य हैं।
- एससी/एसटी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2 जनवरी 1981 से 1 जनवरी 2008 तक हुआ हो।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स की

जन्मतिथि 2 जनवरी 1983 से 1 जनवरी 2008 तक होनी चाहिए।

- पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन को भी नियमानुसार छूट मिलेगी।

हाई कोर्ट गार्डनर भर्ती की जरूरी डिटेल्स

- पद गार्डनर (माली) ■ रिक्तियां 05
- विज्ञापन संख्या 15/2026
- ऑफिशियल वेबसाइट hckrecruitment.keralacourts.in
- अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर
- सैलरी ₹23700–₹52600
- चयन प्रक्रिया इंटरव्यू या लिखित परीक्षा और इंटरव्यू

सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा?

माली की पोस्ट पर सेलेक्शन के लिए हाई कोर्ट केवल इंटरव्यू या लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों ले सकता है। यह पूरी तरह फॉर्म आने की संख्या पर निर्भर करेगा।

अगर इंटरव्यू के बेस पर सेलेक्शन होगा, तो यह 50 नंबर का होगा। इसमें अभ्यर्थियों की गार्डनिंग फील्ड में थियोरेटिकल और प्रैक्टिल नॉलेज देखी जाएगी लेकिन अगर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होते हैं, तो रिटन एग्जाम 100 और साक्षात्कार 10 नंबर का होगा। परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे जो गार्डनिंग डिप्लोमा के सिलेबस पर बेस्ड होंगे। हर सवाल 01 अंक होगा। परीक्षा की अवधि 75 मिनट की होगी। अगर लिखित परीक्षा ली जाती है, तो इसका सेंटर एर्नाकुलम होगा।

एप्लिकेशन फीस कितनी लगेगी?

फॉर्म भरने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के लिंक पर जाना होगा। यहां अपनी सभी डिटेल्स सर्टिफिकेट के मुताबिक भरें। जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, एड्रेस, 10वीं के मार्क्स, रोल नंबर ये सभी जानकारी ध्यान से भरनी होंगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनका सर्टिफिकेट के मिलान किया जाएगा। वहीं आवेदन के समय अभ्यर्थियों को ₹600 एप्लिकेशन फीस ऑनलाइन भरनी होगी। आवेदन शुल्क से एससी/एसटी/बेरोजगार दिव्यांग अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी। इस भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं।

3 लाख छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाएगा आईआईटी

हिंदी में पढ़ाए जाएंगे साइबर क्राइम,ऑनलाइन फ्रॉड, डार्क वेब जैसे विषय

ब्लिट्ज ब्यूरो

कानपुर। डिजिटल दौर में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी की जानकारी भी जरूरी होती जा रही है। इसे देखते हुए आईआईटी कानपुर ने बड़ा कदम उठाया है। संस्थान ने हिंदी भाषा में ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स शुरू किया है। इसका उद्देश्य लगभग 3 लाख छात्रों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी देना है।

यह पहल मुख्य रूप से डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से संबंधित 570 से ज्यादा कॉलेजों के छात्रों के लिए की गई है। इस कोर्स में साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा सुरक्षा, डार्क वेब और डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका फायदा उठा सकें।

570 से ज्यादा कॉलेजों के 3 लाख छात्रों के लिए हिंदी में साइबर सिक्योरिटी कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट iitk.ac.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, के साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब, सी3आईहब ने साइबर सिक्योरिटी में वोकेशनल प्रोग्राम शुरू करने के लिए आगरा की डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (डीबीआरएयू) और विवेकानंद इनक्यूबेशन फाउंडेशन (वीआईएफ) के साथ साझेदारी की है।

तीन पक्षों के बीच हुए समझौते (एमओयू) के तहत यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम पूरी तरह से ऑनलाइन और हिंदी में चलाया जाएगा।

इस कोर्स को ऐसे छात्रों के लिए साइबर सिक्योरिटी की शिक्षा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सेमी-अर्बन और रूरल एरिया में रहते हैं और उन्हें इंग्लिश में पढ़ाए

जाने वाले टेक्निकल कोर्स को समझने में भाषा की दिक्कत होती है।

पढ़ाए जाएंगे ये टॉपिक

इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में ऑनलाइन सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और डॉर्क वेब शामिल होंगे। इस सहयोग के तहत सी3आईहब साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और ट्रेनिंग में आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञता से इसका करिकुलम तैयार करेगा और उसे चलाएगा।

इस कोर्स में साइबर क्राइम और साइबर हाईजीन, सोशल मीडिया से जुड़े खतरे, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), पर्सनल डेटा लीक, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डार्क वेब, साइबर टेररिज्म और गैर-कानूनी ऑनलाइन गतिविधियों जैसे टॉपिक कवर किए जाएंगे।

साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ इंजीनियर्स के लिए ही कोई खास विषय नहीं रह गया है, यह जिंदगी की एक जरूरी स्किल बन गई है। छात्रों को बड़े पैमाने पर और उनकी अपनी भाषा में यह स्किल सिखाने का मौका मिलेगा। प्रो. आशु रानी, वाइस चांसलर, डीबीआरएयू छात्रों के लिए बनाया जाएगा सिक्योरिटी काउंसलिंग सेल डीबीआरएयू एक साइबर सिक्योरिटी काउंसलिंग सेल (सीसीसी) भी बनाएगा। यह सेल साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करेगा और ऑनलाइन खतरों का सामना कर रहे छात्रों को मदद और गाइडेंस देगा। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रो. मनिंद्र अग्रवाल और दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में सी3आईहचयूबी, डीबीआरएयू और वीआईएफ के प्रतिनिधियों ने एमओयू पर साइन किए। इस पहल का उद्देश्य साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई को ज्यादा आसान बनाना और छात्रों को रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में आने वाले खतरों को समझने में मदद करना है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी अब बन सकेंगे प्रधानाचार्य

800 से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने अतिथि शिक्षकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली के स्कूलों में प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली भर्ती में हिस्सा लेने की अंतरिम राहत दे दी है। कैट के न्यायिक सदस्य मनीष गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य डॉ. आनंद एस. खाटी ने आदेश जारी किया। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिल्ली में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था।

आयु सीमा में छूट पर विचार

मामले में कैट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से आवेदकों को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। उनकी पात्रता अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उनके परिणाम भी सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया गया। कैट ने अतिथि शिक्षकों की आयु में छूट की मांग पर विचार करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी। कुछ शर्तों के चलते इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसे लेकर अतिथि शिक्षक कैट पहुंच गए थे।

भर्ती 800 से ज्यादा पदों पर होनी है। यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 124 प्रधानाचार्य और 704 उप प्रधानाचार्य पदों के लिए भर्ती निकाली है।

कब तक आवेदन ?

प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

क्या है शैक्षणिक योग्यता ?

प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना जरूरी है।

प्रिंसिपल पद के लिए अनुभव

प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव वाइस-प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पद पर होना चाहिए।

वाइस प्रिंसिपल पद के लिए अनुभव

वाइस प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार के पास पीजीटी के रूप में कम से कम 2 वर्ष या टीजीटी के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

कितनी होनी चाहिए उम्र ?

प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 वर्ष, जबकि वाइस प्रिंसिपल पद के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। हालांकि, किसी भी स्थिति में उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसरो में साइंटिस्ट बन राज्य का नाम रोशन किया लवकुश ने

पाई 15 वीं रैंकिंग, मौसम विभाग में सहायक वैज्ञानिक रहते हुए की तैयारी

नई दिल्ली। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए बड़े शहरों या महंगे स्कूलों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी है। इस बात को बिहार के भोजपुर जिले में बड़हरा प्रखंड के शाहजहांपुर गांव के रहने वाले लवकुश प्रसाद ने साबित कर दिखाया है।

लवकुश ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में साइंटिस्ट के पद पर चयनित होकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लवकुश ने इस कठिन राष्ट्रीय स्तर की भर्ती परीक्षा में पूरे भारत में 15वीं रैंक हासिल की है। जैसे ही उनके चयन की खबर परिजनों और गांव वालों को मिली, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया।

साधारण परिवार से असाधारण सफर

लवकुश की यह सफलता इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि उनका पालन-पोषण किसी बड़े शहर में नहीं, बल्कि एक साधारण ग्रामीण माहौल में हुआ है। उनके पिता नंदलाल प्रसाद एक शिक्षक हैं और मां शिवरानी देवी गृहिणी हैं। लवकुश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय नूरपुर से प्राप्त की। उन्होंने 2015 में हाई स्कूल बलुआं से 10वीं और 2017 में एसबी कॉलेज, आरा से गणित विषय के साथ 12वीं (साइंस) की परीक्षा पास की। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद में दाखिला लिया और 2022 में बीटेक की डिग्री हासिल की।

बीटेक पूरी करने के बाद भी लवकुश अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहे। 6 सितंबर 2023 को उनका चयन मौसम विभाग, गुवाहाटी में असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर हुआ।

नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। उनकी इसी निरंतर लगन और विषयों पर मजबूत पकड़ का नतीजा रहा कि उन्होंने इसरो की परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल कर अपने गांव और राज्य का नाम रोशन कर दिया।

कड़ी मेहनत व निरंतरता सफलता की कुंजी

लवकुश प्रसाद का मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सही मार्गदर्शन और निरंतरता होती है। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सेल्फ-स्टडी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कमजोर पहलुओं पर लगातार काम किया।

इसी अनुशासन का परिणाम है कि उन्होंने देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते हुए टॉपर्स की सूची में स्थान हासिल किया।

यूपीएससी के लिए छोड़ी 48 लाख की नौकरी

नई दिल्ली। कहते हैं कि अगर मन में अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो बड़ी से बड़ी सुख-सुविधाएं और लाखों का पैकेज भी छोटा लगने लगता है। इस बात को 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा ने सच साबित किया है। मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून की रहने वालीं अंजलि ने एक समय में न्यूजीलैंड में 48 लाख रुपये सालाना के मोटे पैकेज वाली नौकरी को अलविदा कहकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की राह चुनी थी।

असफलता से नहीं हारी हिम्मत, दूसरे प्रयास में बनीं आईपीएस

यूपीएससी की तैयारी का सफर धैर्य और निरंतरता की मांग करता है। अंजलि ने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और एक सटीक रणनीति के साथ रोजाना पढ़ाई की। उनकी दिन-रात की मेहनत रंग लाई और उन्होंने दूसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा 2020 पास कर भारतीय पुलिस सेवा का पद हासिल किया। उन्हें यूपीएससी में 158 रैंक हासिल की थी।

'लेडी सिंघम' के नाम से बनाई पहचान

एक पुलिस अधिकारी के रूप में अंजलि ने चार साल के करियर में कई जटिल साइबर अपराधों और बाल अपराधों से जुड़े मामलों को सुलझाया है। अंजलि को उनके बेहतर काम के लिए लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

पीएचडी करने के लिए सालाना ₹1 करोड़ स्टाइपेंड

पढ़ाई के साथ भारतीय स्टूडेंट्स को मालामाल कर रहे 5 देश

नई दिल्ली। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी करने के बाद यदि आपकी दिलचस्पी रिसर्च में है, तो फिर पीएचडी करना आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी को पूरा होने में 4 से 12 साल तक का समय लग सकता है लेकिन पीएचडी करते वक्त सबसे ज्यादा टेंशन इस दौरान होने वाले खर्चों को लेकर होती है।

पीएचडी स्टूडेंट के रूप में रिसर्च करते वक्त कहीं सैलरी मिलती है, तो कहीं स्टाइपेंड। स्टूडेंट को क्लास लेने, लैब का काम संभालने या मरीजों की देखभाल करने जैसे कामों के लिए स्कूलों और यूनिवर्सिटीज द्वारा काम पर रखा जाता है। ऐसे में आइए आज उन टॉप-5 देशों के बारे में जानते हैं, जहां पीएचडी करने पर सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है।

स्वीडन: स्टडी इंटरनेशनल के मुताबिक, इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर स्वीडन का नाम आता है। यहां पर औसत पीएचडी स्टाइपेंड 42,618 डॉलर (लगभग ₹40.80 लाख) है, जबकि स्वीडन में रहने का खर्च 2,264 डॉलर (लगभग ₹2.16 लाख प्रति माह) है। स्वीडन को इसके इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ब्लीकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डलारना यूनिवर्सिटी, हाल्मस्टैड यूनिवर्सिटी और जॉनकोपिंग यूनिवर्सिटी यहां पढ़ने के लिए बेस्ट हैं।

डेनमार्क : यूरोपीय देश डेनमार्क भी पीएचडी के लिए अच्छा माना जाता है। यहां पर औसत पीएचडी स्टाइपेंड 53,436 डॉलर (लगभग ₹51.14 लाख) है। देश का सोशल वेलफेयर सिस्टम ऐसा है, जिससे स्टाइपेंड के जरिए आराम से सभी खर्चे कवर हो जाते हैं। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, आरहूस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क और आलबर्ग यूनिवर्सिटी में पीएचडी की जा सकती है।

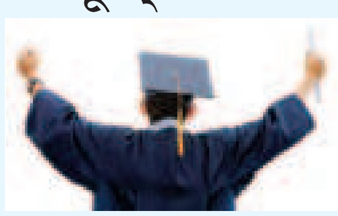

फिनलैंड: फिनलैंड अपने हाई-क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है, जो शुरुआती वर्षों से लेकर डॉक्टोरल लेवल तक फैली हुई है। यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी है। यहां मिलने वाली औसत पीएचडी स्टाइपेंड की बात करें तो वह 46,537 डॉलर (लगभग ₹44.54 लाख) है। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, आल्टो यूनिवर्सिटी, ओउलू यूनिवर्सिटी, टेम्पेरे यूनिवर्सिटी और टुर्कू यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए बेस्ट है।

नीदरलैंड : अगर आप नीदरलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको 74,163 डॉलर (लगभग ₹70.99 लाख) तक की स्टाइपेंड मिल सकता है। यहां पर रहने का खर्च भी कम है, जिससे स्टाइपेंड से ही पैसे भी बचाए जा सकते हैं। नीदरलैंड को रिसर्च पब्लिशिंग वाले देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रखा गया है। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी, लीडेन यूनिवर्सिटी, ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इरास्मस यूनिवर्सिटी रॉटरडैम अच्छे संस्थान हैं।

ऑस्ट्रिया : ऑस्ट्रिया में पीएचडी के लिए सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है। यहां मिलने वाली स्टाइपेंड की बात करें तो वह 1,04,328 डॉलर (लगभग ₹1 करोड़) है, जबकि यहां रहने का औसत खर्च 1,955.43 डॉलर (लगभग ₹1.87 लाख प्रति माह) तक है। वियना यूनिवर्सिटी, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इंसब्रुक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज व साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

खिलाड़ियों के लिए आयकर विभाग में भर्ती, ₹81000 तक सैलरी

17 खेलों के मेधावी खिलाड़ियों से मांगे गए आवेदन

पुणे। खेल के मैदान में आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अब अच्छी नौकरी ढूंढ़ रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। पुणे आयकर विभाग में वैकेंसी निकली हैं। खिलाड़ियों के लिए यहां स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस कैडर में रिक्तियां आई हैं। इसके लिए कार्यालय, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त की तरफ से आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन www.incometaxindia.gov.in पर जारी किया गया है। आवेदन भी चल रहे हैं।

यह भर्ती एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्विमिंग, वॉलीबॉल, पैरा-स्पोर्ट्स, टेनिस, योगासान को मिलाकर 17 खेलों के मेधावी खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इंटर यूनिवर्सिटी या खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो। सबसे ज्यादा रिक्तियां एथलेटिक्स में हैं, 20। इसके बाद 12 पोस्ट वॉलीबॉल में हैं। इस भर्ती में कैंडिडेट्स लास्ट डेट 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं।

रिक्तियां और सैलरी

पद- कुल रिक्तियां-सैलरी

- स्टेनोग्राफर (ग्रेड-II) (स्टेनो)- 06 लेवल-04- 25,500-81,100
- टैक्स असिस्टेंट -40 लेवल-04- 25,500-81,100
- मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) -39 लेवल-01- 18,800-56,900
- कुल -85

योग्यता क्या चाहिए ?

- स्टेनोग्राफर ग्रेड II (स्टेनो): मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो। अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए।
- टैक्स असिस्टेंट (टीए): मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी की हो या समकक्ष योग्यता हासिल की हो। एज लिमिट 18-27 साल तक हो।
- मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस): 10वीं पास या समकक्ष योग्यता हासिल की हो। उम्र सीमा 18-25 वर्ष तक तय की गई है।

शैक्षिक योग्यता और एज लिमिट के अलावा अभ्यर्थियों के पास खेल से जुड़े सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। इसके लिए फॉर्म 1 से 5 प्रारूप रखे गए हैं। फॉर्म -1 अंतर्राष्ट्रीय संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव द्वार, फॉर्म-2 राष्ट्रीय संघ या राज्य संघ के सचिव द्वारा, इंटर यूनिवर्सिटी फॉर्म-3 में विश्वविद्यालय के खेल डीन/प्रभारी द्वारा, फॉर्म-4 में राज्य के लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशालय के खेल निदेशक/उप निदेशक और फॉर्म -5 में भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

सेलेक्शन कैसे होगा ?

आयकर विभाग की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन खेल उपलब्धियों और पोस्ट पर आधारित स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। सबसे पहले प्रेफरेंस देखी जाएगी। पहली प्राथमिकता में वे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद दूसरे प्रेफरेंस में राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर चैंपियनशिप/नेशनल गेम्स में टॉप 3 में स्थान प्राप्त किया हो।

तीसरे प्रेफरेंस में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टॉप 3 में आए हों। इसी तरह अन्य प्राथमिकता रखी गई हैं। इसके बाद खेल सर्टिफिकेट देखें जाएंगे। अगले चरण में स्किल टेस्ट और आखिरी चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होगा।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा ?

आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को ₹200 एप्लिकेशन फीस भरनी होगी। यह ऑनलाइन भरी जाएगी। एक बार फीस का भुगतान होने के बाद यह रिफंड नहीं होगी। ध्यान रखें कि जो अभ्यर्थी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आखिरी तारीख से पहले ही आवेदन संबंधित प्रक्रिया पूरी कर लें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड की सौगात, अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी करेंगे जेईई-नीट की निःशुल्क तैयारी

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। जिन परिवारों के पास निजी कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस भरने के पैसे नहीं, अब उनके बच्चे भी इंजीनियरिंग व मेडिकल जैसी परीक्षाओं की तैयारी उतने ही अच्छे माहौल में कर सकेंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम को राज्य के 155 चुनिंदा सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल प्लस-टू स्कूलों तक पहुंचाया है। इसका सीधा फायदा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले उन निर्धन विद्यार्थियों को मिलेगा, जो जेईई और नीट जैसी देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। इस पूरी पहल को अनुभवी शिक्षकों की मदद से चलाया जा रहा है, ताकि निजी कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े।

ब्लिट्ज ब्यूरो

देशभर से चार स्टूडेंट्स जाएंगे नासा हरियाणा से आयशा का चयन

एक लाख से अधिक बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको दिलचस्पी ऐसी प्रतियोगिताओं में जो आपको अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भेज दे, तो यह खबर आपके लिए है। मिटश्योर ओलंपियाड मास्टर्स भी इसी प्रतियोगिता में से एक है। इसका रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें हरियाणा की बेटी आयशा समेत चार विद्यार्थियों ने पूरे देश में नाम रोशन कर दिया है। अब इनका चयन नासा विजिट के लिए हुआ है।

मिटश्योर ओलंपियाड मास्टर्स के परिणामों की घोषणा जयपुर स्थित होटल मैरिएट में की गई। इस समारोह में देशभर के विभिन्न स्कूलों से आए स्टूडेंट्स, शिक्षकों, प्रिंसिपल्स और स्कूल प्रतिनिधि शामिल हुए।

शानदार प्रदर्शन का ईनाम

हरियाणा की आयशा ने विज्ञान विषय में शानदार प्रदर्शन किया। इसी वजह से उनका चयन नासा विजिट के लिए हुआ। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के कई चरण शामिल थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद पूरे देश से केवल चार विद्यार्थियों को नासा जाने का मौका मिला है। आयशा के अलावा राजस्थान से गौरांगी शर्मा और मध्य प्रदेश के श्योपुर से शुभ जैन और एमपी के ही रीवा से जयप्रकाश पांडे का भी चयन हुआ है।

विजेताओं को मिला ये इनाम

बता दें कि कार्यक्रम में 60 विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को 50 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के अतिथि डॉ. पी अग्रवाल, प्रो. अनिल धवन एवं विनोद पंवार ने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार पाने वाले छात्रों में न केवल मेट्रो शहरों बल्कि छोटे कस्बों और गांवों के बच्चे भी शामिल थे, जो इस ओलंपियाड की सबसे बड़ी खासियत रही। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस प्रतियोगिता के लिए देशभर से 1 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ओलंपियाड मास्टर्स का उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं, बल्कि इसे केवल बड़े शहरों तक सीमित न रखते हुए देश के सभी छोटे शहरों की प्रतिभाओं तक पहुंचाना है। नासा विजिट के दौरान आयशा और अन्य चयनित विद्यार्थी रकिट साइंस, स्पेस रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी लैब्स और प्रोजेक्ट्स को करीब से देखेंगे।

क्या है मिटश्योर ओलंपियाड

यह एक राष्ट्रीय स्तर की स्कूली ओलंपियाड परीक्षा है जिसे मिटश्योर आयोजित करता है। इसका उद्देश्य बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटीटिव एग्जाम स्किल्स को डेवलप करना है। यह कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, जिला, स्टेट/जोनल और नेशनल लेवल पर रैंक और पुरस्कार होते हैं।

'इतने काबिल लोग हैं, मेरा नंबर कैसे आएगा?'

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जगा दी है। यह वीडियो किसी फिल्मी सीन या मोटिवेशनल स्पीच का नहीं, बल्कि सड़क पर हुई एक छोटी-सी, बेहद सहज बातचीत का है, जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया। यह वीडियो है आईएएस अफसर परी बिश्नोई का जो फिलहाल सिक्किम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी संभाल रही हैं। हुआ यूं कि मशहूर स्ट्रीट फोटोग्राफर अंकित कुमार सड़क पर घूमते हुए लोगों से उनका प्रोफेशन पूछ रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर दो वर्किंग विमेन पर पड़ी, जो इत्मिनान से टहल रही थीं। जैसे ही अंकित ने माइक आगे बढ़ाया इनमें से एक ने खुद को आईएएस परी बिश्नोई बताया। यह सुनते ही अंकित का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने तुरंत सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कुछ टिप्स मांग डाले। परी ने जो जवाब दिया वह इतना सीधा और दिल को छू लेने वाला था कि देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई।

दरअसल, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवार अक्सर किताबों के बोझ से कहीं ज्यादा कम्पिटिशन के खौफ से टूट जाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर प्रयागराज की गलियों तक, हर एस्पिरेंट के जेहन में एक ही सवाल घूमता रहता है, इतने काबिल लोग तैयारी कर रहे हैं, आखिर मेरा नंबर कैसे लगेगा ? यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल कर चुकीं परी बिश्नोई ने इसी डर को नए सिरे से समझाने की कोशिश की।

शुरुआत मुझे भी डर लगा था

परी बिश्नोई खुलकर बताती हैं कि जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, तो उनके मन में भी घबराहट थी। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से आए तेज-तर्रार अभ्यर्थियों को देखकर किसी का भी हौसला डगमगा सकता है, यह बात वह बखूबी समझती हैं। उनका कहना है कि वह किसी बड़े नाम वाले स्कूल-कॉलेज से नहीं, बल्कि एकदम आम पृष्ठभूमि से आई हैं। तैयारी शुरू करते वक्त उनके मन में भी सबसे पहला खयाल यही आया था कि इतनी भीड़ में उनकी जगह कहां बनेगी लेकिन इस शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद उन्होंने न तो आत्मविश्वास खोया और न ही सही रणनीति के साथ पढ़ाई करना छोड़ा।

भ्रम भी तोड़ा

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए परी बिश्नोई ने एक दिलचस्प भ्रम भी तोड़ा। उनके मुताबिक, परीक्षा का दबाव स्टूडेंट्स के दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वे कॉम्पिटिशन के दायरे को असल से कहीं ज्यादा बड़ा मान बैठते हैं।

ईपीएफओ में एपीएफसी पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू

भरे जाएंगे 80 पद, 11 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। यूपीएससी ने ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (एपीएफसी) के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी। इच्छुक उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बताते चलें कि इस भर्ती योजना के तहत कुल 80 पदों पर भर्तियां होनी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 22 अगस्त से ही शुरू हो चुकी।

कब है आवेदन की अंतिम तारीख

उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख 11 सितंबर शाम 6 बजे तक निर्धारित है। वहीं, यूपीएससी की जानकारी के अनुसार एपीएफसी पदों के लिए भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

किस कैटेगरी के लिए कितने पद

नोटिफिकेशन में अलग-अलग वर्ग के लिए पदों की संख्या भी जारी की है। इनमें 29 पद जनरल कैटेगरी के, 8 पद ईडब्ल्यूएस, 18 पद ओबीसी, 15 पद एससी और 10 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए है। कुल पदों में से तीन पद पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। इस पद पर चयनित उम्मीदवार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्य करेंगे। एपीएफसी पद सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल 10 के अंदर आता है।

- ऑनलाइन आवेदन शुरूः 22 अगस्त
- आवेदन की अंतिम तारीखः 11 सितंबर
- रिक्रूटमेंट टेस्टः 20 दिसंबर
- चयन प्रक्रियाः रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा।

योग्यता

- उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की हो या समकक्ष योग्यता रखते हों।
- इसके अलावा कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा वांछनीय क्वालिफिकेशन में रखा गया है।

आयु सीमा

जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। वहीं ओबीसी के लिए अधिकतम आयु 38 वर्ष और एससी, एसटी के लिए 40 वर्ष है। आयु की गणना आवेदन की आखिरी तारीख के आधार पर की जाएगी।

एप्लिकेशन फीस

अगर फीस की बात करें तो जिन उम्मीदवारों पर फीस लागू होगी, उन्हें 250 रुपये फीस देनी होगी। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन में छूट दी है।

चयन प्रक्रिया

रिक्रूटमेंट टेस्टः परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (एमसीक्यू) होंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए 300 अंक और इंटरव्यू के लिए 100 अंक निर्धारित हैं।

इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशनः रिक्रूटमेंट टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

सिलेबस में बदलाव

इस बार एपीएफसी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। नए सिलेबस में लेबर लॉ की जगह लेबर कोड्स को शामिल किया गया है। परीक्षा में अभ्यर्थियों से कई अलग-अलग विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस में जनरल इंग्लिश, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन, विकास से जुड़े मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा रुझान, शासन और भारतीय संविधान से संबंधित विषय शामिल हैं।

इसके अलावा जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इंडसट्रियल रिलेशन, लेबर कोड्स और भारत में सोशल सिक्योरिटी की भी तैयारी करनी होगी।

वहीं, सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस को भी जगह दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे।

ऐसे करें आवेदन

1. उम्मीदवार सबसे पहले यूपीएससी के एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in पर जाएं।
2. फिर नया अकाउंट बनाकर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और अपनी पर्सनल व शैक्षणिक जानकारी भरें।
4. फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लागू होने पर आवेदन शुल्क जमा करें।
5. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह जांच लें।
6. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

हर स्कूल में अलग-अलग फॉर्म भरने का झंझट खत्म

'संविदा साथी' पोर्टल से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी समेत कई पदों के लिए करें आवेदन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर और स्टाफ बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने अब तक चली आ रही पुरानी और बिखरी हुई भर्ती व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए एक नया केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है संविदा साथी पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए अब उम्मीदवारों को हर स्कूल में अलग-अलग आवेदन करने की झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

क्या है केवीएस संविदा साथी पोर्टल

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह पोर्टल samvida-sathi.kvs.gov.in पर लॉन्च किया है, जिसका मकसद कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों की भर्ती को आसान बनाना है ताकि केंद्रीय विद्यालय में अस्थायी शिक्षक और स्टाफ के रूप में काम करना चाहने वाले उम्मीदवार एक ही ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर आवेदन कर सकें। पहले जो व्यवस्था थी उसमें हर स्कूल अपने स्तर पर अलग प्रक्रिया अपनाता था, जिसकी वजह से अक्सर कन्फ्यूजन और दोहराव की स्थिति बन जाती थी, इसीलिए केवीएस ने इस असमानता को खत्म करने के मकसद से केंद्रीकृत सिस्टम की ओर कदम बढ़ाया। सबसे अहम बात यह है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से किसी भी तरह की ऑफलाइन या स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मान्य नहीं होगी, यानी अब सभी उम्मीदवारों के लिए इस पोर्टल से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है।

किन पदों के लिए होगी भर्ती

इस पोर्टल के जरिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, स्पोर्ट्स कोच जैसे कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल पदों के लिए उम्मीदवारों को रजिस्टर किया जाएगा, प्रोफाइल बनाई जाएगी और वे वेकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे साथ ही अपने आवेदन का स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा योग शिक्षक, नर्स जैसे पदों पर भी इसी पोर्टल के जरिए भर्तियां होंगी। पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग रखी गई है। 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी जैसी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की आवेदन फीस नहीं रखी गई है, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए यह पूरी तरह निःशुल्क है।

उम्र सीमा को लेकर जरूरी बात

गौर करने वाली बात यह है कि केवीएस ने हर कॉन्ट्रैक्चुअल पद के लिए एक समान उम्र सीमा तय नहीं की है, बल्कि अलग-अलग केंद्रीय विद्यालय अपनी भर्ती सूचना में खुद उम्र से जुड़ी शर्तें तय कर सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले संबंधित स्कूल की ओर से जारी विज्ञापन को अवश्य पढ़ें।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है। उम्मीदवार नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी बुनियादी जानकारी देकर अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके प्रोफाइल पूरी कर सकते हैं। इसके बाद फोटो, सिग्नेचर सहित जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड या प्रिंट जरूर कर लें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले स्कूल पोर्टल पर मौजूद प्रोफाइल की छंटनी करेंगे, फिर शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को वॉक-इन इंटरव्यू और टीचिंग डेमो के लिए बुलाया जाएगा, और अंत में मेरिट लिस्ट यानी पैनल तैयार कर वेकेंसी के हिसाब से उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।

तकनीकी दिक्कत हो तो यहां करें संपर्क

अगर किसी उम्मीदवार को पोर्टल के सामान्य उपयोग को लेकर कोई सवाल है तो उसे संबंधित केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करना चाहिए लेकिन अगर लॉगिन में दिक्कत आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा या डॉक्यूमेंट अपलोड में एरर आ रहा है, तो samagamhelpdesk@kvs.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है। यह सुविधा सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहती है।

चाय वाले के बेटे का कमाल, सीएपीएफ में 81वीं रैंक लाकर बना असिस्टेंट कमांडेंट

10 से ज्यादा परीक्षाओं में मिली नाकामी, पर नहीं मानी हार

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। लक्ष्य के लिए सच्ची लगन हो तो कोई भी रुकावट या आर्थिक तंगी आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस मिसाल को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले घनश्याम जायसवाल ने साबित कर दिखाया है।

घनश्याम के पिता शत्रुघ्न शाह बैरिया बस स्टैंड पर ठेले पर चाय और स्नैक्स की छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर के घनश्याम ने सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यूपीएससी सीएपीएफ (एसी) परीक्षा में ऑल इंडिया 81वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का गौरव प्राप्त किया है।

आईआईटी का सपना टूटा, फिर सिविल सेवा की ओर बढ़ाया कदम

घनश्याम की शिक्षा और शुरुआती जीवन का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के नथुनी भगत विद्यालय से पूरी की। इसके बाद रामेश्वर सिंह कॉलेज से 12वीं (साइंस) और फिर पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया।

बचपन में उनका सपना आईआईटी में दाखिला लेकर इंजीनियर बनने का था। हालांकि जेईई परीक्षा में सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने अपना रुख सिविल सेवा की ओर मोड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान परिवार को आर्थिक सहारा देने और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया।

आसान नहीं था रास्ता

घनश्याम के लिए सफलता का यह रास्ता आसान नहीं था। वे 10 से अधिक अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुए और 6 बार यूपीएससी की परीक्षाओं में भी उन्हें निराशा हाथ लगी।

इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 5 वर्षों के निरंतर संघर्ष, धैर्य और कड़ी मेहनत के बल पर परीक्षा में झंडे गाड़ दिए।

कड़ी मेहनत और जिद से पाई सफलता

घनश्याम ने अपनी सीमित सुविधाओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। महंगी कोचिंग में जाने के बजाय उन्होंने खुद से पढ़ाई करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे, उन्हीं का सही इस्तेमाल किया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा हुआ, बल्कि पूरे गांव और समाज में खुशी की लहर दौड़ गई।

तीन हफ्ते में लाएं नए नियम, वरना रोक दें विमान संचालन: सुप्रीम कोर्ट

हवाई किराये में अनियमित बढ़ोतरी पर कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

केंद्र ने मसौदा नियम सीलबंद लिफाफे में जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष रखा। पीठ ने कहा, मसौदे में एक तंत्र प्रस्तावित है, लेकिन नियामक को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराये में अनियमित बढ़ोतरी से जुड़ी याचिका पर केंद्र से नए विमानन नियमों को जल्द अंतिम रूप देकर तीन हफ्ते में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, अगर विमानन कंपनियां अनुपालन नहीं करती हैं तो उनका संचालन रोक दें। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने बताया, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियमों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रक्रिया तीन सप्ताह में पूरी हो जाएगी। केंद्र ने मसौदा नियम सीलबंद लिफाफे में जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष रखा। पीठ ने कहा, मसौदे में एक तंत्र प्रस्तावित है, लेकिन नियामक को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। याचिका सामाजिककार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन ने दाखिल की है। इसमें विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता व यात्री हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं प्रभावी नियामक की मांग की गई है।

एअर इंडिया के दो और पायलट डोप टेस्ट में फेल, ड्यूटी से हटे

टर्बुलेंस का शिकार हुई फुकेट-दिल्ली विमान के मुख्य पायलट के बाद एअर इंडिया के दो और पायलट शुरुआती डोप टेस्ट में फेल पाए गए हैं। उनके सैंपल कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया और इनके अंतिम टेस्ट नतीजों का इंतजार है। सूत्रों ने बताया, अब तक करीब 400 पायलटों के साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जिनमें से दो पॉजिटिव पाए गए हैं। डोप टेस्ट के अंतिम नतीजे आने में आमतौर पर 24-48 घंटे लगते हैं।

5,000 से अधिक पायलटों का रोज होता है डोप टेस्ट

फुकेट से 4 अगस्त को दिल्ली आई विमान में दुर्घटना के बाद एअर इंडिया समूह ने 13 अगस्त से अपने सभी 5,000 से अधिक पायलटों का अनिवार्य डोप टेस्ट शुरू करने का फैसला किया था। यह नए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का हिस्सा है।

याचिका में बैगेज शुल्क समेत इन मुद्दों पर जोर

याचिका में कहा गया है कि बिना किसी कारण के मुफ्त चेक-इन सामान की सीमा 25 से घटाकर 15 किलोग्राम कर दी गई। पहले यह सुविधा टिकट का हिस्सा थी, अब इसे कमाई का नया जरिया बना दिया गया है। अब सिर्फ एक ही बैग चेक-इन करने की अनुमति है। चेक-इन बैग का उपयोग नहीं करने पर भी यात्री को टिकट कीमत में छूट नहीं मिलती।

अभी किसी भी अथॉरिटी के पास हवाई किराया या अतिरिक्त पैसे वसूलने की समीक्षा, उसकी अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार नहीं है। इससे कंपनियां को हिडन चार्ज और अनिश्चित कीमतें वसूलती हैं।

उड़ान योजना को गति देने के लिए विकसित होंगे 100 नए एयरपोर्ट

200 हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी भी तेज

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के नए चरण को लेकर केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया है। राज्यों के सहयोग 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी तेज हो गई है।

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नए हवाई अड्डों और हेलीपैड के चयन के लिए राज्य प्रस्ताव भेज सकते हैं। जमीन की उपलब्धता, तकनीकी जांच, यात्रियों की संभावना के आधार पर स्थानों का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, राज्यों से भी प्रस्ताव मांग जा रहा है। राज्य जमीन उपलब्ध कराते हैं तो तकनीकी जांच के बाद देखा जाएगा कि संबंधित जगह से कितने यात्री मिल सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी हवाई पट्टियों को भी एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो बड़े शहरों में हैं और किसी वीवीआईपी के आवागमन के लिए इनका इस्तेमाल होता है, जबकि इन शहरों से हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी है। पर्वतीय प्रदेशों, पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य आकांक्षी क्षेत्रों में दो सौ हेलीपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। हाल ही में लोकसभा में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू एक सवाल के जवाब में बताया कि योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू की गई है।12 हजार 159 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है नए एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र ने दस वर्ष के लिए उड़ान योजना का लक्ष्य तय किया।

वैश्विक संकट व पूंजी की कमी से शुरू नहीं हो पा रहीं नई एयरलाइंस

भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार में एकाधिकार और द्वयाधिकार तोड़ने की केंद्र सरकार की योजना फिलहाल आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रयास भी किया। ताजा स्थिति यह है कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 63.6 फीसद से बढ़ कर 67.4 फीसदी हो गई है, जिन कंपनियों की शुरूआत की गई, वो प्रतिस्पर्धी बाजार में ठीक से संचालन भी शुरु नहीं कर पाई हैं।

अभी तक शुरू नहीं हुई

दिसंबर 2025 में शंख एयर उत्तर प्रदेश से, अल हिंद केरल से और फ्लाईएक्सप्रेस तेलंगाना/हैदराबाद से क्षेत्रीय सेवाएं शुरू करने वाली थीं। जुलाई 2026 तक इनमें से कोई भी कंपनी व्यावसायिक उड़ानें शुरू नहीं कर पाई है। एक कारण पश्चिम एशिया संकट को बताया जा रहा है जिसकी वजह से इन नई कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लीज पर विमान नहीं मिल पा रहा।

शंख एयर कई बार सेवाएं शुरू करने की योजना आगे बढ़ा चुकी है। अब वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही का लक्ष्य रख रही है। जानकार बता रहें हैं कि नई एयरलाइनों को एटीआर-72 जैसे छोटे जहाज भी लीज पर नहीं मिल पा रहे।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की प्रथा समाप्त

अब स्मार्टफोन पर ई-बोर्डिंग पास दिखाना होगा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की प्रथा एक सितंबर से समाप्त कर दी गई है।

अधिकारियों ने कहा, इसके बजाय विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को आव्रजन मंजूरी के लिए अपने स्मार्टफोन पर ई-बोर्डिंग पास दिखाना होगा।

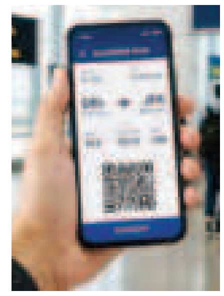

अधिकारियों ने कहा, भारतीय हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को अब भौतिक बोर्डिंग पास ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आव्रजन अधिकारियों ने 1 सितंबर से इस दस्तावेज़ पर मुहर लगाने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) ने हाल ही में हवाई अड्डे के अधिकारियों को आधिकारिक निर्देश जारी किया है, क्योंकि एजेंसी ने पाया कि आव्रजन उद्देश्यों के लिए बोर्डिंग पास पर भौतिक रूप से मुहर लगाने से यात्रियों को असुविधा हो रही थी।

अधिकारियों ने कहा, बोर्डिंग पास पर अनुचित या गलत मुहर लगने के कारण उन्हें पढ़ने में त्रुटियों के मामले भी सामने आ रहे थे, इसलिए इस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

अधिकारियों ने निर्देश का हवाला देते हुए कहा, बीओआई द्वारा इस मामले की जांच की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भौतिक बोर्डिंग पास की अनिवार्य आवश्यकता और आव्रजन काउंटरों पर बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए।

हालांकि, उन्होंने कहा कि फिजिकल बोर्डिंग पास स्वीकार किए जाते रहेंगे, लेकिन अब आव्रजन अधिकारियों द्वारा उन पर मुहर नहीं लगाई जाएगी।

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बोर्डिंग पास पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा व्यक्तिगत तलाशी के दौरान मुहर नहीं लगाई जा रही थी और उन्हें केवल आव्रजन अधिकारियों द्वारा मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों यात्रियों के लिए सीआईएसएफ द्वारा बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने की प्रथा कई साल पहले बंद कर दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए आव्रजन प्रवेश और निकास पर मुहर लगाने की प्रथा को समाप्त करने की एक प्रायोगिक परियोजना को भी इस संदर्भ में एक प्रायोगिक अभ्यास पूरा होने के बाद समाप्त करने की योजना है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट से हब एंड स्पोक सिस्टम शुरू

यह सुविधा देने वाला देश का तीसरा हवाई अड्डा बना

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से हब एंड स्पोक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा संचालन का शुभारंभ किया। अमृतसर और वाराणसी के बाद यह देश का तीसरा हवाई अड्डा है , जिसे अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन के लिए भारत के अग्रणी हब एंड स्पोक ढांचे में एकीकृत किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हब हवाई अड्डों के माध्यम से घरेलू यात्रियों को निर्बाध अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की सुविधा देता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हब एंड स्पोक सिस्टम के तहत देश भर में कुल 44 एयरपोर्ट्स को विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

ऐसे काम करता है हब एंड स्पोक सिस्टम

यह एयरलाइंस की एक ऐसी संचालन प्रणाली है, जिसमें छोटे शहरों (स्पोक) के यात्रियों को एक बड़े केंद्रीय हवाई अड्डे (हब) पर लाया जाता है और वहां से उन्हें कनेक्टिंग अंतरराष्ट्रीय या लंबी दूरी की उड़ानों में भेजा जाता है।

नए सिस्टम के तहत छोटे एयरपोर्ट पर ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए होगी सारी जांच, इससे एयरलाइंस की परिचालन लागत में आएगी कमी और यात्रियों के समय की होगी बचत।

क्यों पड़ी जरूरत

यात्रियों का समय और परेशानी बचाना व कनेक्टिंग। अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने के लिए बड़े एयरपोर्ट्स पर लगने वाली लंबी कतारों, दोबारा चेक-इन और इमिग्रेशन की झंझट से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी।

सुगम और निर्बाध यात्रा विदेश जाने वाले लोगों को बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से जुड़ने की सुविधा मिलती है।

हवाई अड्डों पर भीड़ प्रबंधन

मेन टर्मिनल पर यात्रियों और सामान की दोबारा जांच का दबाव कम होता है, जिससे परिचालन अधिक तेज बनता है।

वैश्विक विमानन मानकों को अपनाना अंतरराष्ट्रीय एविएशन हब इसी मॉडल पर काम करते हैं। वैश्विक विमानन केंद्र बनाने को व्यवस्था जरूरी है।

ये सुविधाएं मिलेंगी

- सामान की जांच यात्रियों के सामान, कस्टम और इमिग्रेशन की सारी जांच उनके शुरुआती (छोटे) हवाई अड्डे पर ही पूरी हो जाती है।
- दोबारा सुरक्षा जांच नहीं: हब एयरपोर्ट पर उतरने केबाद यात्रियों को दोबारा सुरक्षा जांच या चेक-इन नहीं कराना पड़ता। वे सीधे अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र की ओर जा सकते हैं।
- एयरलाइंस कंपनियों को हर छोटे शहर से सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनका परिचालन लागत कम पड़ती है।
- स्वचालित सामान ट्रांसफर हब एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान का ट्रांसफर एयरसाइड से दूसरी फ्लाइट में एयरलाइन द्वारा खुद किया जाता है। यात्रियों को सामान दोबारा लेने और चेक-इन कराने की जरूरत नहीं पड़ती।

पीएम सोलर पैनल योजना ने हर घर में उजाले, हर घर में समृद्धि की जगाई अलख

केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी ला रही अच्छे दिन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। बिजली के बढ़ते बिलों के कारण आज कई परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली का खर्च कम करना चाहते हैं। इसी दिशा में भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

इंटरनेट पर इस योजना को कई लोग प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना या प्रधानमंत्री सोलर योजना के नाम से भी खोजते हैं। इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त स्टेट, सब्सिडी भी उपलब्ध है।

क्या है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना नाम से आमतौर पर जिस योजना को जाना जाता है, उसका आधिकारिक नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इस योजना का उद्देश्य घरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और परिवारों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में मदद करना है। रूफटॉप सोलर पैनल से दिन के समय घर में बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्यादा बिजली बनने पर लागू नेट मीटरिंग नियमों के तहत इसे ग्रिड में भेजा जा सकता है।

इस योजना से घरों को मुख्य रूप से ये फायदे मिल सकते हैं:

- बिजली के बिल में कमी
- रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी
- स्वच्छ और रिनिवेबल एनर्जी का उपयोग
- ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता कम करना
- सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में एक्सपोर्ट करने का अवसर देना।

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर सब्सिडी मिलती है।

सोलर सिस्टम -सेंट्रल सब्सिडी

- 1 केवी सोलर पैनल - ₹30,000
- 2 केवी सोलर पैनल- ₹60,000
- 3 केवी सोलर पैनल- ₹78,000
- 3 केवी से अधिक- अधिकतम ₹78,000

इसका मतलब है कि 3 केवी या उससे बड़े सोलर पैनल पर सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 तक हो सकती है। ध्यान रखें कि सब्सिडी पाने के लिए सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

क्या राज्य सरकार भी सोलर सब्सिडी देती है?

हां, लेकिन हर राज्य में अतिरिक्त सब्सिडी नहीं है। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी तरफ से अतिरिक्त आर्थिक मदद देते हैं। यह सहायता राज्य के नियम, उपभोक्ता की कैटीगरी, सिस्टम की क्षमता और अन्य स्थितियों पर निर्भर करती है।

2026 में राज्यवार सोलर सब्सिडी

वर्तमान में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलती है।

3 केवी पर संभावित कुल लाभ

- राजस्थान ₹17,000 ₹95,000 तक
- गुजरात ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹20,000 ₹98,000 तक
- दिल्ली-जनरेशन बेस्ड प्रोत्साहन राशि
- उत्तर प्रदेश ₹15,000/केवी, अधिकतम ₹30,000 ₹1.08 लाख तक
- तेलंगाना ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹30,000 + लागू एसजीएसटी बेनिफिट ₹1.08 लाख+
- हरियाणा ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹20,000* पात्रता के अनुसार
- बिहार ₹15,000/केवी तक ₹1.23 लाख तक
- छत्तीसगढ़ ₹15,000 (1 केवी), ₹30,000 (2 केवी+) ₹1.08 लाख तक
- झारखंड पात्र परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता ₹1.23 लाख तक
- असम ₹15,000/₹30,000/₹45,000 ₹1.23 लाख तक
- गोवा लागू लागत/बेंचमार्क कोस्ट का प्रतिशत अलग-अलग
- जम्मू-कश्मीर ₹3,000/1केवी, अधिकतम 3 केवी ₹87,000 तक
- लद्दाख पहले 2 केवी के लिए ₹20,000/प्रति केवी + तीसरे केवी के लिए ₹10,000, कुल ₹1.28 लाख तक
- पुडुचेरी ₹9,000/1केवी ₹1.05 लाख तक

इन राज्यों में केवल सेंट्रल सब्सिडी

- महाराष्ट्र ■ कर्नाटक ■ तमिलनाडु
- केरल ■ ओडिशा ■ पंजाब ■ पश्चिम बंगाल ■ मध्य प्रदेश ■ उत्तराखंड
- हिमाचल प्रदेश ■ आंध्र प्रदेश ■ चंडीगढ़
- मेघालय ■ मिजोरम ■ नगालैंड
- मणिपुर ■ त्रिपुरा ■ सिक्किम
- अरुणाचल प्रदेश ■ अंडमान और निकोबार ■ लक्षद्वीप ■ दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

प्रधानमंत्री सोलर योजना के लिए कौन पात्र है?

यह मुख्य रूप से रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के लिए है।

आम तौर पर आवेदक के पास-

- रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए
- वैलिड कंज्यूमर नंबर होना चाहिए
- सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए
- स्कीम की पात्रता पूरी करनी चाहिए
- अपेक्षित डिस्कॉम प्रोसेस पूरा करना चाहिए
- पंजीकृत वेंडर से ही पैनल इंस्टॉल करवाएं

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले सामान्य तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें:

- आधार कार्ड ■ बिजली बिल
- बिजली उपभोक्ता नंबर
- पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर
- बैंक खाता विवरण ■ कैंसिल्ड चेक
- बैंक पासबुक ■ रिहायश प्रमाण पत्र
- यदि आवश्यक हो तो इनकम सर्टिफिकेट
- डिस्कॉम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन है।

- **चरण 1: पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकरण करें**
- राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर अपने बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी के साथ पंजीकरण करें।
- **चरण 2: बिजली कनेक्शन की जानकारी भरें**
- अपना: राज्य
- बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम)
- उपभोक्ता संख्या
- मोबाइल नंबर
- जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- **चरण 3: घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए आवेदन करें**

आप अपने घर की छत पर जितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं, उसकी जानकारी देकर आवेदन जमा करें।

- चरण 4: बिजली वितरण कंपनी की मंजूरी

आपके आवेदन को संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा जांच और प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा।

- **चरण 5: अधिकृत विक्रेता का चयन करें**

पोर्टल पर उपलब्ध पात्र या सूचीबद्ध विक्रेताओं में से अपनी पसंद का विक्रेता चुनें।

- **चरण 6: सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं**

चयनित विक्रेता घर की छत पर सौर पैनल, विद्युत परिवर्तक, पैनल लगाने का ढांचा तथा आवश्यक विद्युत उपकरण स्थापित करेगा।

- **चरण 7: निरीक्षण और संचालन प्रक्रिया**

सौर संयंत्र लगने के बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा आवश्यक निरीक्षण किया जाएगा और संयंत्र को विद्युत ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

- **चरण 8: सब्सिडी की प्रक्रिया**

संयंत्र की स्थापना और सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र उपभोक्ता को केंद्र सरकार की योजना के नियमों के अनुसार सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

किसानों की बल्ले-बल्ले करेगा 'मूनराइडर 27'

डीजल का झंझट होगा खत्म, आ रहा धूप से चलने वाला ट्रैक्टर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। खेत के मैदान में अब ट्रैक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। अभी तक खेत में ट्रैक्टर दिखते ही डीजल की गंध, इंजन की गड़गड़ाहट और फ्यूल का बड़ा का खर्च याद आता है लेकिन अमेरिका की कंपनी गोसन ने यह पूरी कहानी बदलने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपने नए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में बिजली और सूरज की रोशनी जोड़ दी है। गोसन ने अपना पहला ऑल-इलेक्ट्रिक सोलर ट्रैक्टर पेश किया है, जो बैटरी से चलेगा। खास बात यह है कि इसमें सोलर चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे खेत में काम करते समय सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। गोसन ने अपने सोलर से चलने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को मूनराइडर 27 नाम दिया है। इसकी कीमत 19,995 डॉलर (तकरीबन 19.13 लाख रुपये) रखी गई है। कंपनी का कहना है कि इस ट्रैक्टर को मॉडर्न फार्मिंग, छोटे खेतों, होमस्टेडिंग जैसे कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें कंपनी का इंटीग्रेटेड सोलर चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जो कि ऑप्शनल है।

इसमें रिमूवेबल सोलर पैनल दिया गया है। इसके साथ हाई-एफिशिएंसी फोल्ड-आउट सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, जो ट्रैक्टर के खेत में काम करने या बाहर खड़े रहने के दौरान सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करते हैं। इससे ट्रैक्टर का रनिंग टाइम बढ़ता है और ग्रिड से चार्जिंग पर निर्भरता कम होती है।

तुरंत पावर देगी इलेक्ट्रिक मोटर

मूनराइडर में हाई-टॉर्क इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर की खासियत यह है कि इससे पावर तुरंत मिलती है, जिससे ट्रैक्टर को भारी सामान खींचने, जुताई करने, घास काटने और मुश्किल रास्तों पर चलने में मदद मिलती है।

कंपनी के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के फ्यूल खर्च को काफी कम कर सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर में ट्रेडिशनल इंजन की तुलना में कम मूवेबल पार्ट्स होते हैं, इसलिए रेगुलर सर्विस और मेंटनेंस का खर्च भी कम होता है। गोसन के सीईओ पैट्रिक शेरविन का कहना है कि, ये सोलर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर महंगे डीजल ट्रैक्टरों का किफायती विकल्प बन सकता है। डीजल ट्रैक्टरों के मुकाबले इसकी रनिंग कॉस्ट और मेंटनेंस कॉस्ट काफी कम है।

बैटरी पैक और चार्जिंग

इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में कंपनी ने 24kWh की क्षमता का दमदार लिथियम ऑयन फॉस्फेट बैटरी पैक दिया है। 220V के एसी चार्जर की मदद से इसकी बैटरी 2.5 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। 1,100 वॉट का ऑप्शनल सोलर पैनल चार्जर भी दिया जा रहा है, जिससे एक्स्ट्रा रन टाइम मिलता है।

6 फिल्मों ने इस साल हासिल किया 'ब्लॉकबस्टर' का तमगा

मेकर्स ने 797 करोड़ खर्च कर कमाए 3000 करोड़

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। 2026 के पहले 8 महीने बॉलीवुड के लिए बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ने वाला समय साबित हुए। इस दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कंटेंट, भव्यता और थ्रिलर एलिमेंट्स पर बड़ा दांव लगाया, जिसमें प्रोड्यूसर्स ने लगभग 797 करोड़ का भारी बजट इन्वेस्ट किया। दर्शकों के जबरदस्त सपोर्ट और लगातार भरे हुए थिएटर्स की वजह से इन 6 फिल्मों ने दुनिया भर में 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।

बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

धुरंधर- द रिवेंज: 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली एक्शन-थ्रिलर

'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज होते ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेकर्स ने इस जबरदस्त मास एंटरटेनर को बनाने के लिए दोनों पार्ट में 250 करोड़ का भारी-भरकम बजट खर्च किया। अपनी बेहतरीन कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस की वजह से फिल्म ने दुनिया भर में ऐतिहासिक 1778.5 करोड़ कमाए। फिल्म ने न सिर्फ अपना बजट वसूल किया, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बनी।

बॉर्डर 2: इंडियन आर्मी के जबरदस्त साहस और देशभक्ति की भावना को दिखाने वाली वॉर-ड्रामा 'बॉर्डर 2' ने दर्शकों को रुला दिया

और थिएटर भरे रहे। 250 करोड़ के बड़े बजट पर बनी इस सीक्वल को देश और विदेश दोनों जगह जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अपने दमदार स्क्रीनप्ले और देशभक्ति वाले गानों की वजह से इस फिल्म ने दुनिया भर में 450.4 करोड़ कमाए। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने इसकी शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे 'सुपरहिट' बताया।

भूत बांग्ला: हॉरर-कॉमेडी 'भूत बांग्ला' ने हंसी और डर का एक अनोखा मेल पेश किया, जिसमें अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मशहूर जोड़ी ने वापसी की। 120 करोड़ के बजट में बनी इस एंटरटेनिंग फिल्म ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और दिलचस्प कहानी की वजह से बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाई। फिल्म ने दुनिया भर के थिएटर्स से 270.5 करोड़ कमाए। यह अपने बजट के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट कमाकर बॉक्स ऑफिस पर साफ तौर पर हिट साबित हुई।

धमाल 4: 'धमाल' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 'धमाल 4' ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैमिली कॉमेडी फिल्मों की डिमांड कभी कम नहीं होती। 130 करोड़ की लागत से बनी इस मल्टी-स्टारर कॉमेडी ने अपनी रिलीज के पहले दिन से ही दर्शकों को अपनी ओर खींचा। इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 231.6 करोड़ की सक्सेसफुल कमाई की। बिना किसी फालतू ड्रामे के सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हुए इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म दी।

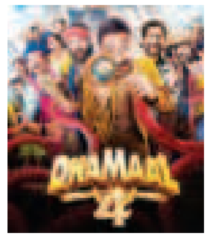

आवारापन 2: 2007 की कल्ट क्लासिक 'आवारापन 2' के इस बहुत इंतजार किए जा रहे सीक्वल ने अपने सीरियस टोन, मधुर म्यूजिक और जबरदस्त ड्रामे से दर्शकों का दिल जीत लिया। सिर्फ 45 करोड़ के लिमिटेड बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से चार गुना से ज्यादा कमाई की। इस फिल्म ने दुनिया भर में 212.3 करोड़ की कमाई करके सबको चौंका दिया। यह कम बजट की रोमांटिक-थ्रिलर 2026 की एक बड़ी 'सुपरहिट' बन गई।

हनुमान अंश: 2026 के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा चमत्कार 'हनुमान अंश' नाम की एक छोटी कल्चरल फिल्म थी। सिर्फ 2 करोड़ के मामूली बजट में बनी इस भक्ति-थ्रिलर को लोगों की जुबान पर मिली पब्लिसिटी ने पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन बना दिया।

अर्थशास्त्र की छात्रा ने संत की कहानी को सिनेमा बना दिया

चारों ओर अनुप्रिया नागर के 'हनुमान अंश' की गूंज

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। बॉलीवुड में जहां बड़े सितारों और करोड़ों-अरबों के बजट वाली फिल्मों का दबदबा दिखाई देता है, वहीं 2026 में एक बेहद छोटी फिल्म ने अपनी असाधारण सफलता से सबका ध्यान खींचा। फिल्म का नाम है 'हनुमान अंश'।

नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित इस फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर महज 21 वर्ष की हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका रास्ता पारंपरिक फिल्मी दुनिया से होकर नहीं आया। वे ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही थीं। इसी दौरान एक अकादमिक अध्ययन के सिलसिले में उनकी रुचि नीम करोली बाबा के जीवन

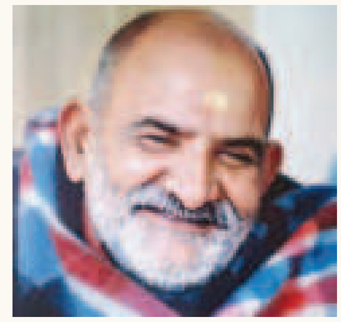

और आध्यात्मिक प्रभाव में पैदा हुई।

फिर एक विचार ने आकार लिया— क्या एक भारतीय संत की कहानी को युवाओं और वैश्विक दर्शकों तक सिनेमा के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? इसी भाव को लेकर मिशन शुरू हुआ। उसके बाद तो एक से एक तार जुड़ते गए और अनुप्रिया ने 'हनुमान अंश' बनाने की घोषणा कर दी। थोड़ा रिस्क था लेकिन विश्वास दृढ़ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सोनू सूद बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए नेपाल पहुंच चुके हैं। उनकी टीम वहां राहत बचाव के कामों में जुट गई है। सोनू ने कहा, 'हम यहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने आए हैं और भारत से काफी सामान लाए हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है और कोशिश है कि उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके।'

सोनू आगे कहते हैं, 'मुझे लगता है कि अपनी तरफ से मदद करना हर किसी का फर्ज है। हम वहां के लोगों से पूछ रहे हैं

कि उन्हें और क्या चाहिए, ताकि हम भारत से मंगवा सकें।' उन्होंने आने वाले महीनों में भी लगातार मदद करने की बात कही है।

हुमा करेंगी एमी में शिरकत

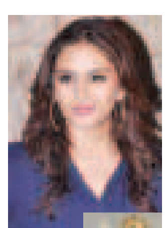

मुंबई। मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी 78वें एमी अवॉर्ड्स में शामिल होंगी। वह इस पुरस्कार समारोह में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय अभिनेत्री हैं। हुमा 10 सितंबर से एमी से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वह गोल्ड हाउस के तीसरे सालाना 'वन हाउस टोस्ट टू द एमीज' कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। यह टीवी की दुनिया में कलाकारों को सेलिब्रेट करने वाला प्रमुख आयोजन है। वह मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन फंड के 20वें सालाना 'ईवनिंग बिफोर' प्री-एमी कार्यक्रम में भी दिखाई देंगी।

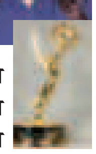

बर्बादी के कगार पर हॉलीवुड ट्रंप बोले, टैक्स घटाया जाना जरूरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए फेडरल टैक्स इंसेंटिव यानी केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में छूट देने वाली योजना की पैरवी करेंगे। उनका मकसद विदेशों में जा रही फिल्म इंडस्ट्री की नौकरियों को वापस अमेरिका लाना है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हॉलीवुड के 'एंबेसडर' और दिग्गज एक्टर जॉन वोइट के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। दोनों ही अमेरिका में फिल्म

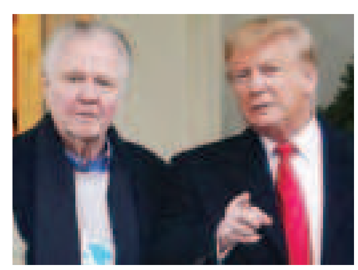

और टीवी इंडस्ट्री की हालत को लेकर बेहद चिंतित हैं। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन लगभग पूरी तरह बिखर गया है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि वहांज्यादा आकर्षक इंसेंटिव मिलते हैं। पारंपरिक फिल्म प्रोडक्शन सेंटरों से काम के बाहर जाने की वजह से हॉलीवुड की हालत पूरी तरह बर्बाद जैसी हो गई है।

टिम कुक की पारी खत्म, जॉन टर्नस ने संभाली एपल की कमान

कुक के 15 साल के कार्यकाल में 2,500 प्रतिशत उछला शेयर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एपल के नए सीईओ जॉन टर्नस ने एक सितंबर को कमान संभाल ली। इसके साथ ही टिम कुक का 15 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। कुक के दौर में आईफोन की जबरदस्त कामयाबी की बदौलत कंपनी की वैल्यू आसमान छूते हुए 4.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। विगत दिवस कंपनी के शेयरों में 2.61% उछाल आई और इसके साथ ही इसका मार्केट कैप $4.745 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। एपल मार्केट कैप के हिसाब से एनवीडिया के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है।

एपल के सीईओ के तौर पर टिम कुक ने अपने आखिरी दिन एक बेहद भावुक संदेश लिखा। उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी टीम को दिया और कहा कि कंपनी की असली ताकत उसका कल्चर है। कुक ने साफ किया कि वे कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं और उन्हें नए सीईओ जॉन टर्नस की काबिलियत पर पूरा भरोसा है।

कुक का कार्यकाल

कुक 2011 में एपल के सीईओ बने थे जब कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उस समय कंपनी का मार्केट कैप $350 अरब था। साल 2015 आते-आते यह $500 अरब पार कर चुका था और अगले साल यह $600 अरब से ऊपर चला गया। 2018 में कंपनी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पहुंचा और महज दो साल में यह दोगुना होकर $2 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। साल 2023 में एपल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया जबकि अगला साल यह $4 ट्रिलियन पहुंचा। कुक ने 15 साल पहले जब कार्यभार संभाला था तो एपल के शेयर का भाव 13 डॉलर था जबकि पिछले सप्ताह इसका बंद भाव 325.13 डॉलर था। इस तरह कंपनी के शेयरों में पिछले 15 साल में करीब 2,500 फीसदी तेजी आई।

टर्नस का करियर

एपल में कुक के उत्तराधिकारी बने 50 साल के जॉन टर्नस 2001 में कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन टीम से जुड़े थे। 2013 में उन्हें हार्डवेयर इंजीनियरिंग का वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया और फिर 2021 में उन्हें प्रमोट करके सीनियर वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। टर्नस ने आईपैड और एयरपॉड्स जैसे प्रोडक्ट्स के विकास में अहम भूमिका निभाई।

कितनी मिलेगी सैलरी?

टर्नस को $3 मिलियन की सैलरी और $55 मिलियन के सालाना इक्विटी अवॉर्ड मिलेंगे। उन्हें वन टाइम $2.5 मिलियन की आरएसयू ग्रांट भी मिलेगी। वहीं कुक को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर अपनी नई भूमिका में भी भारी-भरकम पैकेज मिलेगा। कुक को $2 मिलियन की सैलरी और $45 मिलियन का इक्विटी अवॉर्ड मिलेगा।

एयर मार्शल संदीप थरेजा को मिली नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। एयर मार्शल संदीप थरेजा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक (डीजीएएफएमएस) का कार्यभार संभाल लिया। वह इस पद पर पहुंचने वाले 47वें अधिकारी हैं। उनकी नई जिम्मेदारी में जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की निगरानी करना शामिल है। इससे पहले डीजीएमएस (एयर) के तौर पर उन्होंने गगनयान मिशन को गति देने, अंतरिक्ष यात्रियों के चयन व प्रशिक्षण से पहले होने वाले एनालॉग प्रयोगों में अहम भूमिका निभाई थी।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में कार्यभार संभालने के साथ ही सैन्य अभियानों के लिए चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, चिकित्सा अनुसंधान और मानव संसाधन विकास उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में होंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, पुणे के पूर्व छात्र थरेजा दिसंबर 1986 में आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हुए थे।

वह चिकित्सक और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। करीब चार दशक के सैन्य करियर में उन्होंने 167 मिलिट्री अस्पताल के कमांडेंट, बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कमांड अस्पताल, सेंट्रल कमांड के कमांडेंट समेत कई अहम पद संभाले। उन्होंने एएफएमसी पुणे के निदेशक और कमांडेंट के रूप में चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान को भी आगे बढ़ाया।

नौकरशाही में फेरबदल 3 आईएएस के तबादले

मुंबई। महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। मत्स्य पालन आयुक्त बदले गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई पदों के प्रभार में फेरबदल हुआ है। तबादले और नियुक्ति संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। बैच 2013 के आईएएस अधिकारी भानुदास पलावे को मत्स्य पालन आयुक्त मुंबई पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम मुंबई के प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

इनको भी मिला नया पदभार

बैच 2022 के आईएएस अधिकारी कार्तिक पाणिग्रही को केरल से महाराष्ट्र में अंतर-कैडर प्रति नियुक्ति पर भेजा गया है। आईएएस अधिकारी विजय सिंह शंकरराव देशमुख को महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मुंबई के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है।

पहले भी हो चुका तबादला

अगस्त माह में विकास चंद्र रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सुधार) वित्त विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग मंत्रालय पद पर नियुक्त किया गया था। स्वामी योगेश म्हासे- पाटिल, मैनेजिंग डायरेक्टर, महाराष्ट्र स्टेट फिल्म, स्टेट एंड कल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सचिव व स्पेशल इंक्वारी ऑफिसर (1) प्रशासन पद पर तैनात किया गया था।

रचा इतिहास : शक्ति शर्मा बनीं पहली गैर चिकित्सकीय महिला एयर वाइस मार्शल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह देश के सशस्त्र बलों में एयर वाइस मार्शल या समकक्ष रैंक हासिल करने वाली पहली गैर-चिकित्सकीय महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने एक सितंबर को एयर मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख (शिक्षा) का पद संभाला। इससे पहले वह एयर कमोडोर के पद पर कार्यरत थीं।

यह उपलब्धि क्यों खास

शक्ति शर्मा की उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सशस्त्र बलों में कोई गैर-चिकित्सकीय महिला अधिकारी एयर वाइस मार्शल के पद तक नहीं पहुंचा था। उनकी नियुक्ति महिला अधिकारियों के बढ़ते नेतृत्व और जिम्मेदारियों को दिखाती है। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिलाओं के लिए एक नया अध्याय भी मानी जा रही है।

वायुसेना में उनका सफर

शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की शिक्षा शाखा में कमीशन मिला था। तीन दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमांड मुख्यालय और एयर मुख्यालय में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं। लंबे अनुभव के बाद अब उन्हें एयर मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख (शिक्षा) की जिम्मेदारी दी गई है।

कौन-कौन से दायित्व संभाले?

शक्ति शर्मा ने शिक्षा और रक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्थागत कामों में नेतृत्व किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर और पुणे

विश्वविद्यालय में वायुसेना के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इन केंद्रों का उद्देश्य शिक्षा और रक्षा से जुड़े रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। वह तीनों सेनाओं की पहली महिला अधिकारी भी बनीं, जिन्होंने सैनिक स्कूल की कमान संभाली। उन्होंने सैनिक स्कूल, कपूरथला की प्रिंसिपल के तौर पर काम किया।

एनटीए में दो डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में दो डायरेक्टर और एक जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किए हैं। एनटीए को नीट पेपर लीक और दूसरी चिंताओं को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, रवि कुमार सिंह (इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर) और प्रसन्ना वेंकटेश वी (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) को एनटीए में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

अमित समदरिया बने जॉइंट डायरेक्टर

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक, 2016 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस (कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस)

ऑफिसर अमित समदरिया को एनटीए में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त करने के लिए चुना गया है।

तीन हफ्ते के अंदर संभालना होगा पद

तीनों आदेशों में कार्मिक मंत्रालय के एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियुक्त अधिकारियों को आदेश जारी होने के तीन हफ्ते के अंदर अपना नया पद संभालना होगा।

कौन हैं रवि कुमार सिंह

रवि कुमार सिंह 2012 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी हैं और अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश कैडर से हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए सीधे चुने गए रवि कुमार सिंह ने एनटीए में डायरेक्टर के तौर पर शामिल होने से पहले दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में डीसीपी (पे लेवल 13) के पद पर काम किया है। वे सितंबर 2012 में आईपीएस में शामिल हुए थे और उन्हें सेवा में लगभग 14 साल का अनुभव है।

आईएएस प्रसन्ना वेंकटेश वी कौन हैं?

प्रसन्ना वेंकटेश वी आंध्र प्रदेश कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट, उन्होंने कई प्रशासनिक पदों पर काम किया है, जिनमें एलुरु के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, विजयवाड़ा के म्युनिसिपल कमिश्नर और कुरनूल के जॉइंट कलेक्टर के पद शामिल हैं। एनटीए में डायरेक्टर के तौर पर शामिल होने से पहले, उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी, गुंटूर में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया।

छात्राओं ने पीएम मोदी को बांधी राखी

ब्लिट्ज ब्यूरो

एक बच्ची ने पूछा- आपके बचपन का सपना क्या था?

नई दिल्ली। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रक्षा बंधन भाई-बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और एक-दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का त्योहार है। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। पीएम मोदी ने इसकी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 7, लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा बंधन के जश्न की कुछ यादगार झलकियां।

पीएम मोदी ने पीएम आवास पर बच्चों से मुलाकात की और छोटी-छोटी बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ खूब हंसी-मजाक किया, उनसे हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए 'हाई-फाइव' भी किया।

पीएम मोदी और बच्चों के बीच हुआ संवाद

बच्चों के चेहरों की चमक और पीएम मोदी का स्नेह इस पल को बेहद यादगार बना रहा था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और प्रधानमंत्री के बीच एक बेहद दिलचस्प और प्यारा संवाद भी हुआ।

पीएम ने बच्चों को बताया अपना सपना

बातचीत करते हुए एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा कि उनके बचपन का सपना क्या था? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया-आप लोगों से मिलने का।

इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी बच्चों के साथ हंसी-मजाक करते हुए नजर आ रहे है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटी बच्ची पीएम मोदी के बेहद करीब आती है और फिर उन्हें प्यार से किस कर देती है। बच्ची की इस मासूमियत पर पीएम मोदी भी मुस्कुराते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर अब ये प्यारा सा मोमेंट लोगों का ध्यान खींच रहा है।

द्रौपदी मुर्मू ने भी बच्चों से बंधवाई राखी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अलग-अलग स्कूलों और संगठनों के बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई-बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ विशेष रक्षाबंधन समारोह की झलकियां शेयर कीं।

विविधता में एकता भारत के डीएनए में : भागवत

ब्लिट्ज ब्यूरो

न्यूयॉर्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि विविधता में एकता भारत के डीएनए में है। इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

संघ प्रमुख भागवत विगत दिवस न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' फोरम द्वारा आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (सार्वभौमिक एकता उत्सव) कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 6,000 से अधिक सदस्यों और विभिन्न धर्मों के नेताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने विविधता को अपनाने और समुदायों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द की अक्सर चर्चा होती है और वह है बहुलतावाद और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश की चर्चा होती है 'विविधता में एकता'।

उनकी इस बात पर वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाई। भागवत ने कहा कि भारत के लिए एकता और विविधता, दोनों उसके डीएनए में हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के एक संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि हर राष्ट्र के सामने एक लक्ष्य होता है, जिसे उसे पूरा करना होता है और एक नियति होती है, जिसे उसे साकार करना होता है।

इंडियन एयरफोर्स ने खगांतक-243 बम का सफल 'ड्रॉप टेस्ट' किया

नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम (एलआरजीबी) खगांतक-243 का सफल 'ड्रॉप टेस्ट' किया है। इससे भारत की स्वदेशी हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। इसमें 125 किलो का एमके-81 वॉरहेड लगाया गया है।

यह बम 144 से 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। इसकी मदद से लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा में गए बिना दूर के लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। एयरफोर्स ने पहला टेस्ट पोखरण में सुखोई एसयू-30 एमकेआई से किया था। खगांतक-243 को नागपुर की स्टार्टअप कंपनी जेएसआर डायनेमिक्स ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ मिलकर बनाया है। इंडियन एयरफोर्स ने इसका पहला टेस्ट पोखरण में सुखोई एसयू-30 एमकेआई से किया था। इसे मिग-29 और मिराज-2000 लड़ाकू विमानों में भी शामिल करने की योजना है।

चिनाब के लिए पहाड़ खोदेगा भारत, बिलबिलाएगा पाकिस्तान

नई दिल्ली। सिंधु जल संधि रोके जाने के एक साल के दौरान भारत ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में नदी परियोजनाओं में तेजी ला दी है। अरसे से अटके प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है तो वहीं नदियों के पानी के भंडारण की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं, पाकिस्तान लगातार सिंधु जल संधि रोके जाने को लेकर रोना रो रहा है।

भारत चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना के तहत हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति में 8.7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य पूरा करने जा रहा है। यह काम मॉडर्न टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से किया जाएगा।

चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना के तहत पहाड़ों में सुरंग खोदने का काम नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) को सौंपा गया है। इससे लाहौल घाटी में बहने वाली चंद्रा नदी का पानी लाहौल के कोकसर क्षेत्र से मनाली के मढ़ी तक ब्यास नदी में पहुंचाया जाएगा। इसी काम के लिए टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाना है। परियोजना में पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड के बजाय टीबीएम से टनल खोदी जाएगी, ताकि पीर पंजाल की पहाड़ियों को कोई नुकसान ना हो और यहां की जैव विविधता भी बनी रह सके।

दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाएंगे मस्क

ब्लिट्ज ब्यूरो

वाशिंगटन। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अमेरिका के दक्षिणी लुइसियाना में दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बना रही है। इस प्रोजेक्ट पर कंपनी 100 बिलियन डॉलर यानी करीब ₹9.50 लाख करोड़ का निवेश करेगी। 'स्टारबेस, लुइसियाना' स्पेसएक्स का दूसरा 'स्टारबेस' कैंपस होगा।

यह नया स्पेसपोर्ट लुइसियाना के पिकान आइलैंड पर 1.25 लाख एकड़ में फैला होगा, जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर से भी आठ गुना बड़ा है। यहां से स्पेसएक्स के नेक्स्ट-जनरेशन रॉकेट 'स्टारशिप' और एआई बेस्ड सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। कंस्ट्रक्शन साल 2029 से शुरू होने की उम्मीद है। 3,000 नई नौकरियां मिलेंगी, औसत सैलरी ₹88 लाख सालाना होगी। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने इसे राज्य की इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम बताया है। लैंड्री के मुताबिक, इस स्पेसपोर्ट से क्षेत्र में कम से कम 3 हजार से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी।

यहां काम करने वाले कर्मचारियों की औसत सालाना सैलरी 92,600 डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए होगी, जो वर्मिलियन पैरिश की मौजूदा औसत इनकम से लगभग दोगुनी है। गवर्नर ने कहा, यह प्रोजेक्ट रोजगार, समुदायों के लिए प्रगति और हमारे तटीय इलाकों के लिए सुरक्षा लेकर आएगा।

'सेल्फ-सस्टेनिंग' होगा कैंपस, खुद बनाएगा ईंधन और बिजली

स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट ग्विन शॉटवेल ने बताया कि यह कैंपस पूरी तरह 'सेल्फ-सस्टेनिंग' होगा।

खुद का ई-धन और बिजली: कॉम्प्लेक्स के भीतर ही रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए मीथेन गैस का उत्पादन होगा और इलेक्ट्रिकसिटी जनरेशन फैसिलिटी लगाई जाएगी।

नासा ने लॉन्च की 4.3 अरब डॉलर की दूरबीन

वाशिंगटन। नासा ने 4.3 बिलियन डॉलर के खर्च से नैंसी ग्रेसन रोमन नामक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है। यह दूरबीन पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर स्थित दूसरे लैग्रेंज पॉइंट (एल2) की ओर बढ़ रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और हजारों नए एक्सोप्लैनेट (सौरमंडल के बाहर के ग्रह) की खोज करना है। एक वीडियो में नासा के नए रोमन स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च और उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है

मुख्य विशेषताएं : यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही बड़े प्राइमरी मिरर से लैस है, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह हमारी आकाशगंगा और अन्य गैलेक्सी के बड़े हिस्सों को बेहद कम समय में स्कैन कर सकेगा। इस बड़ी स्क्रीन का सबसे बेहतरीन फायदा उठाने के लिए कंपनी इसमें आईपैड जैसा एप लेआउट दे रही है।

देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता

देहरादून। दून की बेटी गुनगुन बियाल ने हौसले और संघर्ष की मिसाल कायम की है। तीन साल तक ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को मात देने के बाद गुनगुन ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता पीएंडआई इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह 2027 में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

देहरादून के डांडीपुर की रहने वाली 23 वर्षीय गुनगुन साधारण परिवार से हैं। पूर्व में 'मिस टीन उत्तराखंड' रह चुकी गुनगुन के जीवन में एक समय बड़ा संकट आया जब उन्हें ब्लड कैंसर का पता चला। अहमदाबाद में उनका इलाज चला और गत 25 अगस्त को ही उनका तीन साल लंबा इलाज सफलतापूर्वक पूरा हुआ। गुनगुन ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान अपने आत्मविश्वास, दृढ़ता और प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बल पर देशभर से आई प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की।

ब्लिट्ज विशेष

युद्ध बढ़ेगा तो भूख भी: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चेताया

कहा, संघर्षों का असर अब युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संघर्षों के कारण पैदा होने वाले मानवीय संकट को कम करने को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने की अपील की है। भारत ने चेताया कि ऊर्जा, उर्वरक, समुद्री परिवहन और कृषि व्यापार में रुकावटें वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर आयात पर निर्भर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। युद्ध बढ़ेगा तो भूख भी निश्चित ही बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ग्लोबल और लोकल फूड संकट को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय पर हुई खुली बहस में भाग ले रहे थे।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन, होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर से जुड़ी परिस्थितियों को खाद्य आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर और जहाजों के सत्यापन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है।

अपने संबोधन में पी. हरीश ने कहा कि आजकल के संघर्षों का असर केवल लड़ाई वाली जगहों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर-दूर तक फैलता है। ऊर्जा बाजार, उर्वरक की आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था और कृषि व्यापार में रुकावटों ने दिखाया है कि क्षेत्रीय संघर्ष किस तरह दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा असर

सुरक्षा परिषद में फूड अंडर फायर: खुली बहस में पी. हरीश ने कहा कि जो विकासशील देश खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, उन्हें इन रुकावटों का सबसे

ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। परिषद की पहली प्राथमिकता संघर्ष से होने वाले मानवीय संकट को कम करना होना चाहिए। इसके लिए सुरक्षित, तेज और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा देनी होगी और संघर्ष-रोधी इंतजामों में मदद करनी होगी।

प्रतिबंधों से मानवीय सहायता बाधित न हो

पी. हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उठाए गए कदम, जैसे प्रतिबंध, अनजाने में मानवीय सहायता या वैध खाद्य और कृषि व्यापार में रुकावट न डालें। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मजबूत और खाद्य-सुरक्षित समाज का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रीय सरकारों की जिम्मेदारी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र का विकास तंत्र और रोम स्थित एजेंसियां सहायता करती हैं, न कि सुरक्षा परिषद।

भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का किया जिक्र

हरीश ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों के जरिए भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देने वाला देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सब्सिडी वाले अनाज का कानूनी अधिकार देता है। वहीं पीएम किसान कार्यक्रम के तहत 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मजबूती बढ़ी है।

मिलेट्स से लेकर जलवायु-अनुकूल खेती तक भारत का जोर

हरीश ने कहा कि 2023 में भारत की ओर से 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स' यानी 'अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' को बढ़ावा दिए जाने से जलवायु-अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की ओर दुनिया का ध्यान गया। उन्होंने इसे विविध और टिकाऊ खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु-अनुकूल खेती के तरीकों से भारत न केवल खाद्य-सुरक्षित बना हुआ है, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति में भी अहम योगदान दे रहा है। हरीश ने वाणिज्यिक जहाजरानी और समुद्री व्यापार मार्गों में रुकावटों से खाद्य सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरों का व्यापक रूप से जिक्र किया।

गुटेरेस ने तीनों संघर्षों का किया जिक्र

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हालांकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले इन तीनों संघर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर काला सागर के जरिए होने वाले अनाज और ऊर्जा के निर्यात पर पड़ रहा है, जो यूक्रेन और रूस दोनों से होता है।

होर्मुज में उर्वरक और तेल आपूर्ति पर संकट

गुटेरेस ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की तेल आपूर्ति के करीब पांचवें हिस्से और उर्वरक व्यापार के लगभग एक-तिहाई हिस्से को संभालता है। वहां लगे प्रतिबंधों और मार्गों के बंद होने से कीमतें बढ़ गई हैं और उपलब्धता बहुत कम हो गई है। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों से भोजन और अन्य सामानों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए और खतरा पैदा हो रहा है।

होर्मुज से उर्वरक और अनाज के लिए सुरक्षित कॉरिडोर का प्रस्ताव

गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने एक सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए होर्मुज से उर्वरक और अनाज की आवाजाही सुनिश्चित करने के व्यावहारिक तरीके सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि भरोसा बढ़ाने की इस समयबद्ध कोशिश में शुरुआत में उर्वरक और उससे जुड़े कच्चे माल पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे दूसरे उत्पादों तक भी बढ़ाया जा सकेगा।

यूपीआई की ग्लोबल उड़ान, 11 देशों में पहुंचा भारत का पेमेंट सिस्टम

ग्रीस-मालदीव नए नाम, जुलाई में ₹29.87 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत का यूपीआई अब सिर्फ डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट का जरिया नहीं रहा, बल्कि दुनियाभर में अपनी पहचान बना रहा है। जुलाई 2026 में यूपीइई ने 29.87 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए, जबकि इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच 11 देशों तक हो गई है। ग्रीस और मालदीव इसके सबसे नए पड़ाव हैं।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल भारत के साथ-साथ अब विदेशों में भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने यूपीआई को भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की बैकबोन बताया गया है।

सरकार के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) का यूपीआई पिछले एक दशक में करीब 12,000 गुना बढ़ा है और अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जून 2025 में जारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में दुनियाभर के रियल-टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% थी। इससे यूपीआई की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यूपीआई अब क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए कई देशों में उपलब्ध है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई और फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव में भी यूपीआई ऑपरेशनल है। सरकार के मुताबिक, ग्रीस और मालदीव यूपीआई के इंटरनेशनल एक्सपेंशन में सबसे नए नाम हैं।

2020 से 2022 के बीच हुए बड़े बदलाव

यूपीआई में 2020 से 2022 के बीच कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत हुई, जिससे ईएमआई, एस आईपी और दूसरे रिकरिंग पेमेंट को आसान बनाया गया। वहीं, यूपीआई 123पे के जरिए फीचर फोन यूजर्स को आईवीआर और मिस्ड कॉल जैसे विकल्पों से डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिली। यूपीआई लाइट भी लॉन्च किया गया।

2024 में यूपीआई सर्कल लॉन्च किया गया, जिसके जरिए डेलीगेटेड पेमेंट की सुविधा दी गई। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने यूपीआई अकाउंट से दूसरे व्यक्ति को तय सीमा के भीतर पेमेंट करने की अनुमति दे सकता है।

एच-1बी वीजा पर ₹98 लाख वसूलेगा अमेरिका

ट्रम्प सरकार ने प्रस्ताव जारी किया, भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर

ललित दुबे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने एच-1बी वीजा के लिए नया प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक एच-1बी वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को हर वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर (करीब 98 लाख रुपए) की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी।

एच-1बी एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल वाले पेशेवरों को नौकरी पर रख सकती हैं।

इस फीस से एच-1बी वीजा लेना पहले के मुकाबले बहुत महंगा हो जाएगा। पहले एच-1बी वीजा लेने में आमतौर पर करीब 2,000 से 5,000 डॉलर (करीब 1.9 लाख से 4.7 लाख रुपए) तक फीस लगती थी। यह रकम अलग-अलग मामलों में अलग हो सकती थी। यह नया नियम साल के आखिर तक लागू किया जा सकता है। अगर यह लागू हो जाता है तो इसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय आईटी और टेक प्रोफेशनल्स करते हैं।

कोर्ट ने फीस को गैरकानूनी बताया था

पिछले साल ट्रम्प ने एक अस्थायी आदेश के जरिए यह फीस लागू की थी लेकिन जून में

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए अमेरिकी सरकार को फीस वसूलने से रोक दिया था। अब बोस्टन की एक अपीलीय अदालत इस फैसले की समीक्षा कर रही है। वहीं, वॉशिंगटन डीसी की एक दूसरी अदालत इस मामले में एक बड़े कारोबारी संगठन की याचिका पर फैसला देख रही है।

नए प्रस्ताव में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को फीस को स्थायी बनाने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया गया है। यानी सरकार अब इसे हमेशा के लिए कानून बनाने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 19 सितंबर 2025 को एच-1बी वीजा को लेकर नियमों में बदलाव से जुड़े ऑर्डर पर साइन किया था।

आवेदनों में 25% से ज्यादा गिरावट

पिछले साल कंपनियों ने करीब 3.44 लाख एच-1बी वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यह 2024 के मुकाबले 25% से ज्यादा कम था।

अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा होंगे रद

अमेरिकी सरकार 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा रद करने की तैयारी कर रही है।

यह अमेरिकी इतिहास में एक साथ सबसे बड़ी संख्या में वीजा रद करने की कार्रवाई होगी। अमेरिकी विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में बी1 और बी2 वीजा रद करने की घोषणा कर सकता है। ये वीजा 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए थे और उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया है या कर रहे हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि ऐसे लोग अमेरिका में कम समय के लिए आने वाले पर्यटक या कारोबारी के तौर पर दाखिल हुए थे, लेकिन बाद में स्थायी रूप से रहने के लिए शरण का आवेदन कर दिया।

विदेश विभाग ने वीजा रद होने वाले लोगों की सही संख्या बताने से इनकार किया है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी, इसलिए संख्या बदल सकती है।

पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्रीराम मंदिर के सीईओ

गोविंद देव गिरी नए महासचिव

ब्लिट्ज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को लेकर निर्णय हो गया है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के सीईओ चुने गए हैं। बुधवार को अयोध्या की मणिरामदास छावनी में महंत नृत्यगोपालदास की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बैठक में ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ ही आमंत्रित सदस्य भी मौजूद थे।

बैठक में नए महासचिव की भी घोषणा कर दी गई। गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के नए महासचिव होंगे। बैठक में ट्रस्ट के तीन नए सदस्यों की भी घोषणा की गई है। नए सदस्यों में मदन मोहन पांडेय अयोध्या से, महेश भागचंदका दिल्ली से और निर्मला यादव अयोध्या से हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि 16 लोगों के इंटरव्यू हुए थे। इनमें से तीन नाम चुने गए थे जिनमें एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह और श्रुति भारद्वाज के नाम शामिल थे। सीईओ पद के लिए जितेंद्र मिश्रा का नाम फाइनल किया गया है। इसके अलावा, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि नए महासचिव बनाए गए हैं।

कृष्ण मोहन ने बताया कि मदन मोहन पांडेय अयोध्या के रहने वाले हैं। पेशे से वकील हैं। वह राम जन्मभूमि-बाबरी विवाद मामले में रामलला की ओर से कानूनी पैरवी करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं।

डॉ. निर्मला यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं। वह हिंदी और संस्कृत में परास्नातक हैं। उन्हें विश्वविद्यालय में 15 साल तक काम करने का अनुभव है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ऑनलाइन जुड़े। दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे से हुई जिसमें राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए।

एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा मूल रूप से देवरिया जिले के भाटपाररानी क्षेत्र के भोपतपुरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने 18 से अधिक प्रकार के विमानों पर उड़ान भरी और 3,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव हासिल किया। कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर भी रहे हैं।

इसके अलावा एकीकृत रक्षा स्टाफ में उप प्रमुख (सिद्धांत, संगठन एवं प्रशिक्षण) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देश के साथ अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मिश्रा के पास बड़े संगठन के संचालन और नेतृत्व का व्यापक अनुभव है।

उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान कमांड का नेतृत्व किया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया था। मिश्रा को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' और 'विशिष्ट सेवा मेडल' से सम्मानित किया जा चुका है।

सैन्य अनुशासन से मंदिर प्रबंधन तक

राम मंदिर के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मंदिर अब निर्माण के चरण से आगे बढ़कर व्यवस्थित संचालन और वैश्विक धार्मिक-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, कर्मचारी प्रबंधन, सुविधाओं का विस्तार और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियां सीईओ के सामने होंगी।

सैन्य सेवा से आए मिश्रा के अनुशासन, नेतृत्व, बड़े संस्थान के प्रबंधन और समन्वय के अनुभव को ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छोटे से गांव भोपतपुरा से भारतीय वायुसेना के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे मिश्रा का अब अयोध्या के राम मंदिर के पहले सीईओ के रूप में नया अध्याय शुरू हुआ है।

राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य और स्थायी सदस्य

- के. परासरन : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य।
- महंत नृत्य गोपाल दास : अध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट।
- स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज : कोषाध्यक्ष।
- कृष्ण मोहन : अंतरिम महासचिव।
- जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज : सदस्य (प्रयागराज)।
- जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज : सदस्य (पेजावर मठ, उडुपी)।
- युगपुरुष परमानन्द जी महाराज : सदस्य (हरिद्वार)।
- महंत दिनेंद्र दास : सदस्य (निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि)।
- निर्मला यादव : नई महिला ट्रस्टी (शिकोहाबाद)।
- मदन मोहन पांडे : नए ट्रस्टी (अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता)।
- महेश भागचंदका : नए ट्रस्टी (दिल्ली)।

पदेन और सरकारी सदस्य

- नृपेंद्र मिश्रा : अध्यक्ष, मंदिर निर्माण समिति।
- प्रशांत लोखंडे : केंद्र सरकार के प्रतिनिधि।
- संजय प्रसाद : उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।
- शशांक त्रिपाठी : जिलाधिकारी अयोध्या।

उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भारी वृद्धि

ब्लिट्ज ब्यूरो

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए 2 सितंबर का दिन बहुत खास रहा। अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'यूपी आउटसोर्स सेवा निगम' की वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कर्मचारियों को मानदेय के चेक और सुरक्षा किट भी दिए। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

पहले इन कर्मचारियों को हर महीने औसतन 13,000 रुपये वेतन मिलता था। इसे अब बढ़ाकर सीधे 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार ने आर्थिक मदद के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। कर्मचारियों को अब 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।

इसके अलावा, आकस्मिक चिकित्सा और गंभीर दवाइयों के खर्च के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद सफाई कर्मचारियों और दूसरे विभागों के कर्मियों को चेक और सुरक्षा किट मिले। इससे परिसर में खुशी का माहौल था। सालों से आर्थिक असुरक्षा और कम मानदेय में काम कर रहे कर्मचारियों के चेहरों पर इस बदलाव के बाद उम्मीद दिखी। नगर निगम अलीगढ़ सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने इस कदम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश के मेहनतकश वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। कार्यक्रम में मौजूद सफाई कर्मचारी सिद्ध कुमार और संगीता ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई।

अनंत अंबानी के वंतारा और इंडोनेशिया सरकार ने मिलाया हाथ

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा और इंडोनेशिया के फॉरेस्ट्री यानी वानिकी मंत्रालय ने अपने देश में वाइल्डलाइफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटरनरी केयर और कंजर्वेशन की कोशिशों को मजबूत करने के लिए पार्टनरशिप का एलान किया है।

इस प्रोग्राम में वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट से जुड़े हाथियों की देखभाल करने वालों, वेटरिनेरियन यानी पशु चिकित्सकों और अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग के साथ-साथ इंडोनेशिया के जंगली जानवरों के लिए 10 वेटरिनरी हॉस्पिटल या 'हॉस्पिटल ऑन व्हील' शामिल होंगे। 'वे कांबस एलिफेंट हॉस्पिटल' को उपकरणों और तकनीक के साथ एक एडवांस एलिफेंट ट्रीटमेंट एंड केयर सेंटर में बदला जाएगा।

गडकरी बोले– सभी राज्य बाइक टैक्सी को दें मंजूरी

8 करोड़ रोजगार मिलेंगे

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से बाइक टैक्सी को मंजूरी देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी बाइक और स्कूटर से यात्रियों को ले जाने की सुविधा से खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। इससे करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है।

गडकरी ने बताया कि केंद्र ने बाइक टैक्सी की अनुमति दे दी है, लेकिन परिवहन राज्य का विषय होने के कारण कुछ राज्यों में अभी इसकी मंजूरी नहीं है। उन्होंने राज्यों से इसे मंजूरी देने की अपील की, ताकि लोगों को कमाई का नया जरिया मिल सके।

गडकरी ने कहा कि सरकार बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्ती करेगी। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर ड्राइवरों के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है।

भारी वाहन चालकों की ट्रेनिंग जरूरी

गडकरी ने भारी वाहन और निर्माण उपकरण चलाने वाले ड्राइवरों की अनिवार्य ट्रेनिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई जरूरी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जेसीबी इंडिया जैसी कंपनियों से उपकरण देने से पहले ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने की अपील की है।

सुरक्षा पायलट प्रोग्राम

गडकरी ने 'सुरक्षा' पायलट प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत हाईवे, खनन और निर्माण जैसे जोखिम वाले कामों से जुड़े करीब 10 लाख ड्राइवरों और कर्मचारियों की मुफ्त मेडिकल जांच व काउंसलिंग होगी।

पहले चरण में नागपुर-कामठी के एनएच-44 और चंद्रपुर के माइनिंग क्षेत्र में करीब 10 हजार लोगों की जांच का लक्ष्य है।

दोपहिया हादसों में सबसे ज्यादा मौतें

गडकरी के मुताबिक, भारत में दोपहिया हादसों में 81,780 मौतें हुई हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। सीट बेल्ट न लगाना, हिट एंड रन, गलत दिशा में ड्राइविंग, शराब और मोबाइल का इस्तेमाल हादसों की बड़ी वजह हैं। सीट बेल्ट न लगाने से 14,466 और हिट एंड रन में 34,030 मौतें हुईं। वाहन चालकों की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य जांच और ट्रैफिक नियमों के पालन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

भारत को मिली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी

आईसीसी ने वेन्यू और तारीख की भी घोषणा की

गुलशन वर्मा

नई दिल्ली। आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी भारत को दे दी गई है। 14 से 28 फरवरी तक इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब महिला चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। अभी तक महिला क्रिकेट के दो ही आईसीसी इवेंट्स, वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप का आयोजन होता है। 6 टीमों के इस टूर्नामेंट के मैच मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम के साथ ही वडोदरा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

श्रीलंका को करनी थी मेजबानी

पहले इस टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका को करनी थी। हालांकि, श्रीलंका क्रिकेट में जरूरी सुधार अभी जारी हैं। इसी वजह से टूर्नामेंट को श्रीलंका से भारत स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। मेजबानी के लिए बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नाम पर विचार किया गया था। आईसीसी ने अंत में कई फैक्टर्स पर विचार करने के बाद भारत को मेजबानी दे दी।

आईसीसी की तरफ से जारी बयान में चेयरमैन जय शाह ने कहा, 'आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक रोमांचक नया अध्याय है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के तौर पर, यह दुनिया की बेहतरीन टीमों को जबरदस्त और हाई-क्वालिटी मुकाबले के लिए एक साथ लाएगा। यह टीमों को रैंकिंग में ऊपर चढ़ने और ग्लोबल स्टेज पर जगह बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा। अब जब हर साल आईसीसी का कोई बड़ा महिला टूर्नामेंट होगा, तो हमारे पास महिला खेल, इसकी खिलाड़ियों और दुनिया भर में इसके फैंस के लिए बेहतर रफ्तार, ज्यादा निरंतरता और मजबूत लय बनाने का एक बड़ा मौका होगा।'

प्रतीकात्मक फोटो

टी20 फॉर्मेट में होगा आयोजन

महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके मुकाबले टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। ग्रुप राउंड में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी। इसमें सेमीफाइनल मुकाबले नहीं होंगे। राउंड रॉबिन के बाद टॉप-2 पर रहने वाली टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 15 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 16 मुकाबले होंगे। पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होती है।

मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया

इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट की, लिखा- यह फैसला बेहद मुश्किल और दर्दभरा

ब्लिट्ज ब्यूरो

ब्यूनस आयर्स। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हाथ से लिखे नोट की तस्वीर के साथ संन्यास का एलान किया।

39 साल के मेसी ने बताया कि फाइनल के 2 दिन बाद 21 जुलाई को ही उन्होंने संन्यास का फैसला लिख लिया था। उनका आखिरी मैच वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें अर्जेंटीना को स्पेन से हार मिली थी।

मेसी ने लिखा कि उनके पिता जॉर्ज मेसी की मौत के बाद उन्हें लगा कि अर्जेंटीना के लिए करियर खत्म करने का यही सही समय है।' जॉर्ज मेसी का 8 अगस्त को सेंट्रल अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक अस्पताल में निधन हुआ था। वे 68 साल के थे।

पोस्ट में क्या लिखा

मेसी ने लिखा, 'यह फैसला लेना तकलीफदेह था और आज भी दिल के अंदर तक दुख देता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया है। सिर्फ उन पिछले कुछ सालों में नहीं, जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी।'

मैंने इस जर्सी के लिए हमेशा संघर्ष किया। मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ा, ताकि आपको खुशी दे सकूं। फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीनियन होने पर गर्व महसूस करा सकूं।

समय कम बचा है और अध्याय खत्म होते हैं। यह भी ऐसा ही एक अध्याय है, जो मुझे बहुत दुख देता है। मुझे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनना पसंद था, पसंद है और हमेशा रहेगा।

ये प्रमुख खिताब जीते

फीफा वर्ल्ड कप (1): 2022 (कतर वर्ल्ड कप विजेता)
कोपा अमेरिका (2): 2021 और 2024
फिनालिसिमा (1): 2022 (यूरोपियन चैंपियन इटली को हराकर)
ओलंपिक गोल्ड (1): 2008 बीजिंग ओलंपिक
फीफा यू20 वर्ल्ड कप (1): साल 2005 में

वैभव सूर्यवंशी भारत की टी-20 टीम में बरकरार

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर टीम में जगह मिली है। श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाया गया है, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल हैं। सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी लगातार चौथी सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं। उन्हें पहली बार आयरलैंड दौरे के लिए चुना गया था लेकिन, डेब्यू का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करने के बाद वैभव जिम्बाब्वे दौरे पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे। उन्हें तीसरे मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया था। वे 6 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 193 रन बना चुके हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

बुमराह टी-20 इंटरनेशनल खेलेंगे

जसप्रीत बुमराह सहित 7 प्लेयर्स की टीम में वापसी हुई है। इनमें नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल शामिल हैं। बुमराह इंग्लैंड दौरे में घुटने की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर फिसले

नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताजा टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने पिछले हफ्ते बुमराह को पीछे छोड़कर नंबर-1 स्थान हासिल किया था। स्टार्क 872 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर कायम हैं।

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी 861 पॉइंट के साथ दूसरे और बुमराह 853 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ऋषभ पंत सातवें और शुभमन गिल नौवें नंबर पर हैं। गिल को दो स्थान का नुकसान हुआ है। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन ने 6 पायदान की छलांग लगाकर टॉप-5 में जगह बनाई है।

जर्मनी चौथी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन

फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराया

ब्लिट्ज ब्यूरो

बेल्जियम। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। उसने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की है। जर्मनी टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार चैंपियन बना है।

बेल्जियम के वॉवर में जर्मनी के लिए मैच का एकमात्र गोल मिशेल स्ट्रूथॉफ ने 44वें मिनट में किया। स्पेन ने 24 सर्कल एंट्री की, जबकि जर्मनी की 12 रही। स्पेन ने 9 शॉट और जर्मनी ने 5 शॉट लगाए।

पहले हाफ में गोल नहीं हुआ। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार अटैक किए, लेकिन 44वें मिनट में जर्मनी ने काउंटर अटैक पर बढ़त बना ली। स्ट्रूथॉफ ने गोलकीपर को छकाते हुए गेंद नेट में पहुंचा दी।

इस जीत के साथ जर्मनी के वर्ल्ड कप खिताबों की संख्या 4 हो गई है। पाकिस्तान ने भी 4 बार यह ट्रॉफी जीती है।

पाकिस्तान के खिताब 1971, 1978, 1982 और 1994 में आए थे। जर्मनी ने 2002, 2006, 2023 और 2026 में खिताब जीता।

फाइनल में स्पेन के मौके ज्यादा

स्पेन ने फाइनल में जर्मनी से ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने तीसरे क्वार्टर में 10 बार जर्मन सर्कल में प्रवेश किया और कई मौके बनाए, लेकिन फिनिशिंग कमजोर रही। जर्मनी ने अपने सीमित मौकों में से एक को गोल में बदलकर मैच जीत लिया।

स्पेन की टीम 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी। हालांकि, उसका पहला वर्ल्ड कप खिताब जीतने का इंतजार जारी रहा।

अर्जेंटीना ने ब्रॉन्ज जीता

ब्रॉन्ज मेडल मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। मैथियास रे ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से विजयी गोल किया। भारत ने इस वर्ल्ड कप 2026 में 8वां स्थान हासिल किया।

इसरो ने भेजा धरती का 'पहरेदार'

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अपनी असफलताओं को भुलाकर इसरो अब आगे कदम बढ़ा चुका है। इसरो ने तड़के 4 सितंबर को जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट से ईओएस-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। करीब 2,367 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से काम करने वाला भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए सैटेलाइट के थ्रस्टर्स की मदद से कई चरणों में कक्षा बदली जाएगी।

यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से काम करेगा। करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से यह बड़े इलाकों की लगातार निगरानी और बार-बार तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। इससे मौसम की सटीक निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की जल्द पहचान, कृषि और पर्यावरण पर नजर रखने के साथ-साथ सीमाओं और रणनीतिक इलाकों की निगरानी में भारत की क्षमता मजबूत होगी।

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट ईओएस-05 को जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया।

इसके लिए 27 घंटे का काउंटडाउन था। यह मिशन भारत के लिए बहुत खास है। इस रॉकेट को प्यार से 'नॉटी बॉय' कहा जाता है। पिछले कुछ मिशन में इसरो को असफलता मिली थी। कई असफलताओं के बाद इसरो इस लॉन्च से जोरदार वापसी की उम्मीद कर रहा था। यह सैटेलाइट आपदा प्रबंधन और मौसम की सटीक जानकारी देने में गेम चेंजर साबित होगा। 51.7 मीटर ऊंचे और 420.5 टन वजनी तीन चरणों वाले जीएसएलवी-एफ17 रॉकेट

ने शुक्रवार सुबह 2 बजकर 55 मिनट पर उड़ान भरी। रॉकेट ने करीब 2,367 किलोग्राम वजनी ईओएस-05 सैटेलाइट को उसकी निर्धारित सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह जीएसएलवी रॉकेट की 19वीं उड़ान थी।

सैटेलाइट कई चरणों में अपनी अंतिम कक्षा तक पहुंचेगा। इसके लिए सैटेलाइट में लगे थ्रस्टर्स यानी छोटे रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतिम कक्षा में इसकी न्यूनतम ऊंचाई करीब 170 किलोमीटर, अधिकतम ऊंचाई 28,934 किलोमीटर और कक्षा का झुकाव 19.28 डिग्री होगा।

इसरो चीफ ने क्या कहा ?

इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जीएस एलवी-एफ17 रॉकेट ने एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05 यानी जियो-इमेजिंग स्टार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक और बिल्कुल सटीक तरीके से उसकी निर्धारित और जरूरी कक्षा में स्थापित कर दिया है। एक बार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05 को कक्षा में पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाएगा, तो यह जियो ऑर्बिट से काम करने वाला भारत का पहला समर्पित इमेजिंग सैटेलाइट बन जाएगा। यह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा उपलब्ध कराएगा।'

इस सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में क्यों भेजा गया ?

यहां यह जानना जरूरी है कि आम सैटेलाइट धरती के चक्कर लगाते रहते हैं। इससे वे एक जगह पर लगातार नजर नहीं रख पाते। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का फायदा यह है कि सैटेलाइट एक बड़े इलाके पर फोकस बनाए रखता है। ईओएस-05 इसी तकनीक पर काम करेगा। यह लगातार भारत और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी करेगा। इससे मौसम के बदलाव और कृषि से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी। इससे धरती की पहरेदारी होगी। आपदा हो या कोई दुश्मन, इससे भारत हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा।

'नॉटी बॉय' का नाम क्यों ?

दरअसल, जीएसएलवी का पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। शुरुआती उड़ानों में इसे कई बार असफलता मिली। इसके पहले 18 मिशन में से 6 पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। इसी वजह से इसे 'नॉटी बॉय' कहा जाता है।

भारत के लिए क्यों खास है ईओएस-05 ?

फरवरी 2026 तक भारत के पास 21 सक्रिय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे। ज्यादातर सैटेलाइट लो-अर्थ ऑर्बिट या सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा में काम करते हैं। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से पृथ्वी की निगरानी करने की भारत की मौजूदा क्षमता इनसेट - 3डी, इनसेट-3 डीआर और इनसेट-3डीएस जैसे मौसम संबंधी सैटेलाइटों तक सीमित थी।

नेपाल ने जल प्रलय के दौरान मदद के लिए भारत को सराहा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। नेपाल के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में देश में आई विनाशकारी बाढ़ और जल प्रलय के समय तुरंत मदद भेजने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण रूप से उदार कहकर सराहना की है।

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने संकट की घड़ी में भारत के त्वरित और प्रभावी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए वायुसेना के जरिए 57 टन से अधिक की राहत सामग्री (दवाइयां, भोजन, कंबल और जरूरी उपकरण) भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर भारत ने मेडिकल स्टाफ और टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की टीमों को भी राहत कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। हिमनद के ढहने से शुरू हुई इस आपदा ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के जलस्तर को अचानक बढ़ा दिया, जिससे सीमावर्ती और नदी घाटी क्षेत्रों में बस्तियां, सड़कें, पुल तथा जलविद्युत परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई।

मीडिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, 1,204 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,216 लोग अब भी लापता हैं। करीब 11,993 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हालांकि अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़े खोज एवं पहचान अभियान जारी रहने के कारण बदल रहे हैं।

नेपाल सरकार ने सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य में लगाया है। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत, चीन और दक्षिण कोरिया की विशेषज्ञ टीमें भी बचाव अभियान में सहयोग कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, भोजन, दवाइयां, प्राथमिक चिकित्सा, अस्थायी आवास, कपड़े, सैनिटेशन सामग्री और बिजली-रोशनी की तत्काल जरूरत है। हजारों लोग विस्थापित हैं और कई स्थानों पर सड़क तथा संचार व्यवस्था क्षतिग्रस्त होने से राहत सामग्री पहुंचाना कठिन है। बच्चों के लिए पानी, स्वच्छता और अस्थायी शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था भी जरूरी हो गई है।

भारत को तेजस एमके 1ए के लिए मिले तीन और जीई इंजन

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। जीई ने तेजस एमके1ए के लिए एचएएल को तीन एफ 404 इंजन सौंपे हैं। सप्लाई में देरी और पेनल्टी के बावजूद साल के आखिर तक और इंजन मिलने की उम्मीद है। भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जीई एयरोस्पेस ने अगस्त 2026 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को तीन एफ404-आईइन20 टर्बोफैन इंजन का एक नया बैच सफलतापूर्वक भेजा।

एक आधिकारिक बयान में अमेरिकी कंपनी ने देश में बने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी इंजन उपलब्ध कराने के लिए एचएएल और भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर काम करने पर गर्व जताया।

यह हालिया शिपमेंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस एमके1ए प्रोजेक्ट के लिए एक अहम मोड़ पर आया है।

हाल के महीनों में एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शेड्यूल में काफी रुकावटें आई हैं, जिसकी मुख्य वजह सप्लाई चेन में भारी दिक्कतें थीं, जिससे इन जरूरी इंजनों की उपलब्धता सीमित हो गई थी।

तीन और यूनिट्स के आने से एचएएल की असेंबली लाइनें इंतजार कर रहे एयरफ्रेम में इंजन लगाने का काम आगे बढ़ा सकती हैं।

अप्रैल में इन लगातार हो रही देरी के बारे में बात करते हुए, एचएएल के पूर्व चेयरमैन

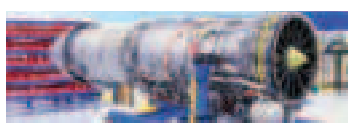

डीके सुनील ने बताया था कि जीई एयरोस्पेस ने इंजन की लगातार सप्लाई का भरोसा दिया था। अमेरिकी कंपनी ने जून से दिसंबर 2026 तक की अवधि में कुल 20 एफ404 इंजन देने के लिए कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन इंजनों की इस नई खेप के साथ कुल डिलीवर की गई यूनिट्स की संख्या दस हो गई है।

इन इंजनों की समय पर खरीद सबसे अहम बात है, क्योंकि इसी से तय होगा कि एलसीए तेजस एमके1 जेट्स कितनी जल्दी तैयार होकर आईएएफ को सौंपे जा सकेंगे।

हालांकि एचएएल ने लगातार कहा है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और असेंबली लाइनें पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन असल में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी तरह से एफ404 इंजन के समय पर मिलने पर निर्भर करती है।

डिलीवरी की समय-सीमा चूकने के जवाब में, एचएएल ने इंजन सप्लायर के साथ हुए समझौते में बताई गई पेनल्टी की शर्तों को लागू किया है। भारतीय एयरोस्पेस कंपनी के अधिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई में देरी होने पर जीई एविएशन पर 'लिक्विडेटेड डैमेज' (हर्जाना) लगाया जाएगा, ताकि इन रुकावटों से होने वाले आर्थिक नुकसान की आधिकारिक तौर पर भरपाई हो सके।

वायुसेना ने अपने कॉम्बैट फ्लीट को आधुनिक बनाने और पुराने जेट्स को बदलने के लिए एचएएल को कुल 180 तेजस एमके1ए फाइटर एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर दिया है। इस बड़ी खरीद में 83 जेट का शुरुआती ऑर्डर और 97 और विमानों के लिए संभावित अगला ऑर्डर शामिल है, जिससे भारत की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के लिए जीई इंजन की लगातार सप्लाई बहुत जरूरी हो जाती है।

पेज 1 का शेष

भारत विश्व-मित्र महाशक्ति

समुद्री सुरक्षा की चिंता: वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र (ब्लैक सी) के संघर्षों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पड़ रहे बुरे असर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

ब्रिक्स का निमंत्रण: पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसके लिए पुतिन ने सहर्ष हामी भरी।

पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान) पर यात्रा का प्रभाव : एससीओ एक ऐसा साझा मंच है जहां भारत, चीन और पाकिस्तान के शीर्ष नेता एक साथ उपस्थित होते हैं। इस यात्रा और भारत के कूटनीतिक व्यवहार ने पड़ोसियों को बड़े भू-राजनीतिक संकेत दिए हैं।

1. चीन पर असर (संतुलन और संदेश)

प्रभाव का मुकाबला : चीन लंबे समय से एससीओ को अपने हितों (जैसे 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव') को साधने का जरिया मानता आया है। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में संप्रायिकता (किसी घटना के घटित होने की संभावना) और संप्रभुता का सम्मान करने वाली कनेक्टिविटी पर जोर देकर चीन के आर्थिक आधिपत्य को चुनौती दी है।

गर्मजोशी बनाम कूटनीतिक दूरी: मंच पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच सहज मेल-मिलाप दिखा, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा विवाद सुलझ नहीं जाते, तब तक पूर्ण सामान्य द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं हैं। वहीं, रूस और भारत की अटूट दोस्ती (कार डिप्लोमेसी) ने चीन को यह संदेश दिया कि वह रूस को पूरी तरह अपने पाले में नहीं ला सकता। उल्लेखनीय है कि मोदी और पुतिन इस दौरान तीसरी बार एक साथ एक कार में साथ-साथ जाते दिखे थे।

2. पाकिस्तान पर प्रभाव (अलगाव और बेनकाब) : आतंकवाद पर दोहरे रवैये की घेराबंदी: एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण (टेरर फाइनेंसिंग), कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों (सेफ हैवेंस) को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पर दोहरे रवैये (डबल स्टैंडर्ड्स) की कोई जगह नहीं है। यह सीधे तौर पर पाकिस्तान की नीतियों पर तीखा प्रहार था।

कूटनीतिक हाशिये पर जाना: सम्मेलन के दौरान जहां पीएम मोदी वैश्विक आकर्षण का केंद्र बने रहे और रूस, ईरान व मध्य एशियाई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करते रहे, वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कूटनीतिक रूप से अलग-थलग दिखाई दिए। (यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी खीझ मिटाने के लिए ग्रुप फोटो को एडिट कर बाकी नेताओं को क्रॉप कर दिया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा)।

बुके-इकॉनॉमिक्स

फूलों के गुलदस्ते सिर्फ प्यार दिखाने का एक छोटा सा जरिया नहीं हैं; ये अर्थव्यवस्था को समझने का एक दिलचस्प पैमाना भी हैं। दुनिया भर के बाजारों में एक साधारण गुलदस्ते की कीमत पर नजर डालने से स्थानीय लोगों की खरीदने की क्षमता, मजदूरी की लागत और जटिल अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में बड़े अंतर का पता चलता है।

भारत रोजाना इस्तेमाल होने वाले मिले-जुले फूलों के गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग 350 रुपये होती है। देश के फूलों के बाजारों में रोजाना लाखों गुलदस्तों का लेन-देन होता है।

यूनाइटेड किंगडम सुपरमार्केट या फूलों की दुकान पर मिलने वाले आम गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग ₹3,200 (£30) होती है। ब्रिटेन के लोग हर हफ्ते लाखों फूलों की डंडियां खरीदते हैं।

अमेरिका विश्व के सर्वाधिक विकसित इस देश में एक आम मिले-जुले फूलों के गुलदस्ते की कीमत लगभग ₹4,200 ($50) होती है। यहां के बड़े कमर्शियल बाजार में रोजाना तीस लाख से ज्यादा लेन-देन होते हैं। संस्कृति और समाज के बीच तालमेल बैठाने के लिए यहां के लोग आतुर रहते हैं।

पश्चिम एशिया दुबई या रियाद जैसे शहरी इलाकों में एक आम गुलदस्ते की कीमत ₹3,800 (146 एईडी) होती है। प्रीमियम और बाहर से मंगाए गए फूलों की वजह से यहां का रिटेल बाजार लग्जरी चीजों पर केंद्रित है।

अफ्रीका एक आम स्थानीय गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग ₹900 (152 एसए रैंड) होती है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर केन्या तक फैले अलग-अलग बाजारों में यहां फूलों की बिक्री लगातार बनी रहती है।

सिंगापुर एक आम गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग ₹4,800 (एसजीडी 75) होती है। बाहर से मंगाए गए फूलों पर ज़्यादा निर्भरता के कारण, यहां कॉर्पोरेट और लाइफस्टाइल से जुड़ी बिक्री ज्यादा होती है।

ब्राजील सजावट वाले एक आम गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग ₹2,800 (बीआरएल 180) होती है। शहरी इलाकों में स्थानीय स्तर पर फूलों की अच्छी खेती की वजह से रोजाना बिक्री का स्तर स्थिर रहता है।

चीन रोजाना इस्तेमाल होने वाले एक लोकप्रिय गुलदस्ते की कीमत लगभग ₹2,500 (सीएनवाई 210) होती है। ई-कॉमर्स के जुड़ने से रोज़ाना लाखों की संख्या में भारी बिक्री होती है।

रूस एक आम रिटेल गुलदस्ते की औसत कीमत लगभग ₹2,200 (आरयूबी 2,400) होती है। रूस में तोहफे देने का चलन बहुत ज्यादा है, जिससे रोजाना लाखों गुलदस्तों की बिक्री होती है।

RNI No. DELHIN/2022/85477 । संपादित, मुद्रित एवं प्रकाशित द्वारा दीपक द्विवेदी : द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301 (उ.प्र.)। संपादकीय, विज्ञापन और प्रशासनिक कार्यालय : 8-बी, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं.- 43502031, 43502032, ई-मेलः info@blitzindiamedia.com, **मुंबई ऑफिस :** 311-बी, आईएनएस टावर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051, मुख्य सलाहकार : ए.के. शर्मा, संपादक : विनोद शील, ग्रुप क्रिएटिव हैड : कौशल श्रीवास्तव
निदेशक संपादकीय बोर्ड : राकेश शर्मा (समाचार व सभी संपादकीय निर्णयों के लिए पीआरबी एक्ट के अनुसार उत्तरदायी), चेयरमैन एवं प्रधान संपादक : दीपक द्विवेदी (सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा)